राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम सत्र, १९६१ का २२वां दिवस [संख्या १३

गुरुवार, दिनांक १६ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(पंचायत, गृह, सिंचाई, वन, चिकित्सा, राजस्थान नहर, सहकारी, स्वायत्त शासन, पशु-पालन, जन-सम्पर्क, विधि, आयुर्वेद एवं यातायात-विभाग)

प्रश्न संख्या ३१९

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३२०

श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३२१

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३२२

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३२३

श्री हरिप्रसाद यादव।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

डॉ० चन्द्रकला।

जुरेहरा (भरतपुर) पंचायत के भूतपूर्व सरपंच द्वारा श्री गुरुदयालप्रसाद की नाक का काटा जाना

३२४. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) [श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

(डॉ० चन्द्रकला)

(डीग) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि जुरेहरा, भरतपुर पंचायत के भूतपूर्व सरपंच ने वहां के एक नागरिक श्री गुरूदयालप्रसाद की नाक काट ली ?

(२) क्या यह घटना सरे बाजार और दिन दहाड़े हुई ? इस घटना का मूल कारण क्या था ?

(३) क्या यह सच है कि श्री गुरूदयाल प्रसाद ने उक्त सरपंच द्वारा किये गये गबन आदि के मामले का रहस्योद्घाटन किया था जिनकी जांच हो रही थी ?

(४) क्या इसी सरपंच ने इसके पहले भी एक व्यक्ति की नाक काट ली थी और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जी हां ।

(२) जी हां । क्योंकि श्री गुरुदयाल ने सरपंच द्वारा किये हुये गबन आदि का रहस्योद्घाटन किया था और जो मुकदमात में उसके खिलाफ गवाही दी थी ।

(३) जी हां ।

(४) जी हां, कार्यवाही अवश्य हुई थी, केस का चालान किया गया, किन्तु अदालत से वह बरी हुआ ।

प्रश्न संख्या ३२५

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३२६

श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

तहसील चाकसू व लालसोट के पटवारियों के खिलाफ हुई जांच का परिणाम

३२७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील चाकसू व लालसोट के कितने पटवारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार विभाग ने जांच की और उसका परिणाम क्या रहा ?

(२) सरकार के आदेशों के अनुसार कितनी अवधि में ऐसे मामलों का फैसला कर दिया जाता है तथा क्या उन मामलों का फैसला उस अवधि में हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) चार; परिणाम इस प्रकार हैं :

(१) १९५९. श्री नाथूलाल पटवारी, ग्राम बिलका, तहसील लालसोट के विरुद्ध ।

Page No.3

(श्री रामकिशोर व्यास)

एक अभियोग धारा ४०६ ता० हि० की तहत में स्थानीय आरक्षी द्वारा अनुसन्धान किया गया था जो कि न्यायालय में अन्वीक्षाधीन है।

(२) श्री बद्रीप्रसाद पटवारी, लालसोट के विरुद्ध।

जिलाधीश महोदय, जयपुर, इसके विरुद्ध विभागीय जांच कर रहे हैं।

(३) श्री शम्भुदयाल पटवारी, तहसील चाकसू, के विरुद्ध।

श्री शम्भुदयाल पटवारी, तहसील चाकसू, को १०० रु० की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। जिलाधीश महोदय, जयपुर, से चालान की स्वीकृति की प्रतिक्षा है।

(४) १९६०। श्री पीताम्बरदास पटवारी तहसील चाकसू, के विरुद्ध।

जांच भ्रष्टाचार विरोधी विभाग में प्रगतीशील है।

(२) संभवतः जांच अनुसन्धान या अभियोग की अन्वीक्षा के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती और न कोई समय, सीमा सरकार द्वारा निर्धारित की गई। सर्वदा पूर्ण रूप से जांच—अनुसन्धान कम से कम समय में पूर्ण करने के लिये प्रयत्न किये जाते हैं।

लूणकरणसर, बीकानेर एवं कोलायत तहसील के गांवों को उपनिवेशन क्षेत्र से पृथक करना

३२८. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या मंत्री, राजस्थान केनाल विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की लूणकरणसर, बीकानेर एवं कोलायत तहसील के समस्त गांवों को राजस्थान नहर की लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम के अन्तर्गत उपनिवेशन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है जब कि ऐसी कोई योजना राज्य सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत नहीं की गई ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों को उपनिवेशन क्षेत्र से अलग करने के लिये कदम उठा रही है ?

(२) क्या यह सही है कि आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा राज्य सरकार को ऐसे गांवों को उपनिवेशन क्षेत्र से निकालने हेतु लिखा जा चुका है ? अगर हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाया है ?

राजस्थान केनाल मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (१) जी हां। पुनरीक्षित राजस्थान नहर परियोजना, जिसमें इस भाग के लिये लिफ्ट इर्रिगेशन का प्रावधान किया गया है सरकार के विचाराधीन है।

(२) जी हां, मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री भीमसेन : सरकार इस पर कब तक निर्णय लेगी ?

Page No.4

श्री रामचन्द्र चौधरी : शीघ्र ही।

पी० एस० आई० श्री पृथ्वीसिंह

३२६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि श्री पृथ्वीसिंह, पी० एस० आई०, खेतड़ी को सन् १९५३ में रेलवे मजिस्ट्रेट की कोर्ट से सजा हुई थी? यदि हां, तो कितनी और किस मामले में?

(२) श्री पृथ्वीसिंह राज्य सेवा में किस वर्ष से है तथा उनकी सर्विस पर इस सजा का क्या असर पड़ा है?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) इस विभाग के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(२) वह पुलिस विभाग में ८ जून, सन् १९५४ से है। इस विभाग के पास सजा के बारे में सूचना नहीं है; अतः इसके प्रभाव का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रश्न संख्या ३३०

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह।

प्रान्त में हुई डकैतियां

३३१. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में सन् १९५९—६०, १९६०—६१ में कहां २ और कब २ डकैतियां हुई?

(२) इन डकैतियों में किस २ डकैती में कितना २ माल डाकू ले गये तथा किस २ डकैती में कितना २ माल बरामद हुआ?

(३) इन डकैतियों का किस २ गिरोह पर शुबहा है तथा इन डकैतियों से सम्बन्धित कौन २ डाकू फरार हैं तथा कौन २ और कब गिरफ्तार कर लिये गये हैं?

(४) क्या इन डकैतियों में इन डाकुओं से कोई व्यक्ति भी मारे गये हैं? यदि हां, तो कब व कहां २ और कितने २?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब बहुत लम्बा है, अतः इसके लिये और समय चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : इसमें कितना समय लग जायगा?

श्री रामकिशोर व्यास : तीन हफ्ते लग जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को दिये हुए छः महीने का समय हो गया व इसके उत्तर के लिये तीन सप्ताह और चाहते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इस सैशन में इसका जवाब नहीं मिल सकेगा?

श्री रामकिशोर व्यास : देने में कुछ ऐतराज की बात नहीं है। पर आपने जो बातें पूछीं वे डिटेल की हैं। कहां कहां डकैती हुई, कब कब हुई, किसमें कितना माल ले गये या

(श्री रामकिशोर व्यास)

बरामद हुआ, किस किस गिरोह पर शुबहा है। तो इतना लम्बा क्वेश्चन है, इसमें समय तो लगेगा ही सारी सूचनाएं कलेट करने में।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आप जिसे नियमित काम कहते हैं वह क्वेश्चन मैंने पूछा है। दूसरी बात इसमें है नहीं। आंकड़े आपके पास नियमित रूप से रहते हैं। तो इस स्थिति में इसमें टाइम लगे, ऐसी बात नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : I will try to reply as soon as possible.

श्री भैरोंसिंह : वह तो आप अन्दाज से कहते हैं।

उद्योग मन्त्री (श्री सिखबचन्द धारीवाल) : आप तो ऐसा समझते हैं कि ये सारी सूचनाएं आई० जी० के पास रहती हैं। एस० पी० के पास रहती हैं और वहां से कलेक्ट करने में समय लगता है।

श्री रामकिशोर व्यास : फिर भी जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह : 'जितनी जल्दी में' तो फिर यह सैशन भी चला जावेगा। तो इस सूरत में तो मैं, अध्यक्ष महोदय, दरख्वास्त करूंगा कि इस प्रश्न को अगली किसी तारीख के लिये स्थगित कर दीजिये। कोई आगे की तारीख दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : जैसा आप कह रहे हैं अगर आई. जी. के पास में सूचनाएं होतीं तो जल्दी मिल जातीं।

श्री भैरोंसिंह : सब के पास हैं साहब, ये सूचनाएं। मंथली स्टेटमेंट बनते हैं और उनकी प्रतियां सब के पास जाती हैं। आई. जी. पी. के पास भी रहती हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं अर्ज करूं कि कुछ आइटम्स के स्टेटमेंट तो रहते हैं। पर जैसा आपने काफी डिटेल में पूछा वे सब सूचनाएं—जैसे डकैती में कितना २ माल गया, कितना कितना बरामद हुआ, किस किस पर शुबहा है, ये सब मैन्टेन नहीं करते। हरएक का इन्डिविजुअल रेकॉर्ड आई. जी. पी. के पास नहीं रहता।

श्री अध्यक्ष : आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में कहा गया है कि इतनी पर्सेन्ट रिकवरी हुई।

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो जनरल है। जनरल बता सकता हूँ कि कितने पकड़े गये, कितने मारे गये, कितनी टोटल बरामदगी हुई। वह तो है, वह तो कभी भी बता सकता हूँ। पर डिटेल हर एक की नहीं है और इन्होंने डिटेल डेकोइटीवाइज़ पूछी है।

श्री अध्यक्ष : भाग ३ का मामला जनरल भी हो सकता है। औरों में दिक्कत हो सकती है, पर इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आप जनरली भी बता सकते थे।

श्री भैरोंसिंह : वैसे भी पुलिस मैन्युअल के अनुसार यह हीनियस ऑफेन्स है। इसकी रिपोर्टें दर्ज होती हैं और डे—टु—डे की प्रोग्रेस आई.जी.पी. के पास आती हैं। तो इन सब का एक कन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट आई. जी. पी. के पास निश्चित रूप से होना चाहिये। मैंने

(श्री भैरोंसिंह)

उसी स्टेटमेंट की नकल मांगी है और केवल आकड़े मांगे हैं उस रिपोर्ट के, और कुछ नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास : जनरली चाहें तो मैं दे सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : जनरल ही में तो आपके स्टेटमेंट की शिड्यूल और डिटेल्स अवेलेबिल हैं।

श्री अध्यक्ष : जो आपके पास है वह दे दें, और आगे माननीय सदस्य टाइम मांगेंगे तो दे दिया जावेगा।

प्रश्न संख्या ३३२

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा।

पाली में मेला दरवाजे के बाहर के काला कोटा के पीछे की जमीन के आवंटन के सम्बन्ध में कार्यवाही

३३३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार को विदित है कि नगरपालिका पाली के भूतपूर्व एडमिनिस्ट्रेटर श्री व्रजवल्लभसिंह मेहता ने मेला दरवाजे के बाहर काला कोटा के पीछे की ऊंची-नीची जमीन को कम कीमत पर पाली शहर के कुछ कम आय वाले घर-विहीन गुमाश्तों को देने की सिफारिश डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ के मार्फत की थी ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां। दिनांक ११-७-६० को। अभी प्रश्न डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ के विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा : उस पर आज तक ११-७-६० के बाद कोई कार्यवाही हुई है या बिल्कुल यों ही रखा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा न कि विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा : इसका कोई पीरियड भी है कि कब तक विचाराधीन रहेगा ?

आर. जे. एल. ६१६३ (स्टेशन वैगन) का दुरुपयोग

३३४. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या पशु—पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि आर. जे. एल. ६१६३ (स्टेशन वैगन) Rinderpest Officers के Rinderpest pertis के चैकिंग के लिए नियुक्त की गई थी ?

(ख) क्या यह सही है कि इस गाड़ी को संचालक, पशु—पालन विभाग, ने अपने काम में लिया जिसके कारण सरकार ने संचालक को डिसप्लेज़र्स कन्वे किये है ?

Page No.7

(श्री भैरोंसिंह)

(ग) यदि हां, तो सरकार गाड़ी के इस दुरुपयोग के लिए संचालक से रुपये क्यों नहीं वसूल करती है ?

मन्त्री, पशुपालन विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : मामला कब से विचाराधीन है और कब तक अन्तिम निर्णय ले लिए जावेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एग्ज़ेक्ट डेट तो नही मालूम है, पर फैसला जल्द कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पिछले साल में भी आश्वासन दिलाया गया था कि सरकार इस पर जल्दी निर्णय लेने वाली है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस वक्त एन्क्वायरी चल रही थी।

प्रश्न संख्या ३३५

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

भारत १६५८ प्रदर्शनी हेतु खरीद किये गये कांच

३३६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि भारत १६५८ प्रदर्शनी के लिए बड़े कांच जयपुर से खरीद कर दिल्ली भेजे गये ? यदि हां, तो कितने कांच और कितनी कीमत के ?

(ख) यह खरीद किस प्रकार से हुई ? यदि टेन्डर्स मांगे गये तो उनका कांपेरेटिव स्टेटमेंट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) क्या यह सही है कि ये कांच नुमायश के काम में नहीं लाये गये तथा उनको जयपुर वापिस लाया गया अथवा उनमें से कई रास्ते में टूट गये ?

(घ) यदि हां, तो यह अनावश्यक खरीद क्यों की गई और इस हानि के लिए कौन जिम्मेदार है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ३३७

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री अनूपसिंह।

Page No.8

कुम्हार सांवलिया, साकिन खण्डप द्वारा अपनी औरत की हत्या कर दिये जाने का मामला

३३८. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि कुम्हार सांवलिया, साकिन खण्डप, तहसील सिवाना, जिला बाडमेर वाले ने अपनी औरत को अपने खेत में दिन के दो बजे के करीब ले जाकर उसके गुप्तांगों में लकड़ी डाल कर घायल कर दिया और फिर गला घोंट कर मार डाला ?

(ख) क्या मरने के बाद उस औरत की लाश को डॉक्टरी जांच के लिये भेजा गया ? अगर हां, तो कहां, किस दिन और डॉक्टर ने जांच के बाद क्या रिपोर्ट दी ? मरने का कारण क्या मिला ?

(ग) पुलिस चौकी खण्डप में इस वारदात के बाद कब रिपोर्ट दी गई और उस समय चौकी में कौन कौन सिपाही थे और उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

(घ) क्या इस केस को सी. आई. डी. द्वारा जांच की गई ? अगर हां, तो चौकी में रहने वाले सिपाहियों ने क्या रिपोर्ट दी ?

(ङ) क्या यह सही है कि सी. आई. डी. जांच के बाद मुकदमा किसी के भी खिलाफ दायर नहीं किया गया ?

(च) क्या यह सही है कि गोलिया निवासी पिटल सोनाराम वल्द रताराम व वक्ताराम वल्द अमराराम के समक्ष कातिल ने अपना जुर्म कुबूल किया और लाश के दाह संस्कार के लिये मदद मांगी ?

(छ) क्या इन दोनों व्यक्तियों को सी.-आई. डी. जांच के समय बुलाया गया ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? केस के बाबत अब क्या कार्यवाही चल रही है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जांच से मु० सांवलिया की औरत का कुदरतन मरना न पाया जाकर उसको मार दिये जाने का शक हुआ, अतः कत्ल का केस दर्ज कर तफतीश की है। केवल कत्ल किस तरह किया गया, इसका अभी तक पता नहीं पड़ सका है।

(२) जी हां, लाश दूसरे रोज यानि २—१०—६० को ही शफाखाना, सिवाना वास्ते डॉक्टरी मुआयना भेजी गई। डॉक्टर ने लाश का मुआयना किया, दिनांक ३—१०—६० को किया, पर मौत का कारण नहीं बतलाया जा सका क्योंकि लाश बहुत सड़ी हुई हालत में थी।

(३) पुलिस चौकी, खण्डप में इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। वकुए के रोज चौकी पर एच. सी. हुकमसिंह, एफ. सी. कल्याणसिंह मौजूद थे। एच. सी. हुकमसिंह ने इस घटना की रिपोर्ट थाना समदड़ी पर तत्काल भेज दी।

(४) जी हां, चौकी के इन्चार्ज एस.-सी. हुकमसिंह तथा कॉ० कल्याणसिंह जो उस रोज चौकी पर मौजूद थे उन्होंने बताया था कि सांवलिया ने चौकी में आकर कहा था कि उसने औरत की मार—पीट की है जिससे

Page No.9

(श्री रामकिशोर व्यास)

वह मर गई है, जिसकी इत्तला थाने में भेज दी थी ।

(५) जी नहीं; मुकदमा नम्बर ३, जुर्म ३०२ ता० हि० ता०६-२-६१ को थाना समदड़ी पर कायम हो चुका है जिसकी तफ्तीश हो रही है ।

(६) जी नहीं । गोलिया निवासी पिठल सोनाराम वल्द रत्नाराम तथा बकताराम के बयान अवश्य सी. आई. डी. अधिकारी ने लिये किन्तु उन्होंने सांवलिया; का उनके समक्ष अपराध स्वीकार करना नहीं बताया ।

(७) जी हां । सी. आई. डी. अधिकारी ने उनके बयान लिये । अब मुकदमे की तफ्तीश हो रही है ।

श्री अनूपसिंह : जो वाकया हुआ उस वाकये में ३ दिन बाद लाश लाये जाने का क्या कारण है जब कि पुलिस चौकी वालों को उसी दिन मालूम हो गया था कि मर्डर हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस को जिस समय इत्तला मिली उसी दिन पुलिस रवाना हो गई ।

श्री अनूपसिंह : वह रवाना नहीं हुई । तीन दिन लगते हैं क्या ? सिवाना से खण्डप ७-८ कोस के करीब है, यानी १०-१२ मील है; तो १०-१२ मील के लिए ३ दिन लग जायेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : ६ तारीख को इत्तला मिली और ६ तारीख को ही रवाना हो गए ।

श्री अनूपसिंह : तो फिर लाश के सड़ने का क्या कारण था ?

श्री रामकिशोर व्यास : पता नहीं ।

श्री अनूपसिंह : ३ दिन लग गए इसलिए लाश सड़ गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : और देख लेंगे इसको ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उसका पोस्ट मॉर्टम किस डॉक्टर के द्वारा कराया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो भी डॉक्टर था ।

श्री मूलचन्द डागा : डी. एम. एच.- ओ. से कराई गई या किससे और फिर कोई इन्जरी मिली है या क्या हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिसका भी ज्युरिस्डिक्शन था । कोई इन्जरी नहीं मिली ।

श्री अनूपसिंह : जिस समय लाश को थाने में ले जाया गया उस समय तक वह औरत बिल्कुल मरी नहीं थी और उससे जो कुछ भी इशारे से या जो कुछ भी कहा जा सकता था उस तरह से उसने पुलिस के कर्मचारियों को बताया है कि मेरी मौत किस तरह से हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्वेस्टीगेशन कल्ल का ही हो रही है ।

Page No.10

श्री अनूपसिंह : क्या इन्वेस्टीगेशन करते समय यह बात सामने नहीं आई कि मर्डर क्यों किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मालूम नहीं है।

श्री अनूपसिंह : तो आपकी सी. आई.-डी. ने क्या जांच की और उसका क्या फायदा हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसमें शक है और मर्डर की तरह से विचार किया जाना चाहिए और ऐसा ही किया जा रहा है।

श्री अनूपसिंह : डॉक्टरों की क्या रिपोर्ट है कि जिसकी वजह से यह मौत हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : नम्बर (२) में मैंने बता दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

पशु-पालन विभाग को मिली सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग

३३६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर, एनिमल हस्बेन्डरी, राजस्थान, रेन्डरपेस्ट की स्टेशन वैगन तथा को विलेज स्कीम की जीप का खुद के घूमने के लिए उपयोग करते हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट के इन्सपेक्टर द्वारा इन दोनों गाड़ियों की लॉग बुक्स की जांच करवाई गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

(ग) इस विभाग में मास इमूनीसेशन यूनिट्स की कितनी जीप हैं और कहां कहां ?

(घ) मोबाइल डिस्पेन्सरी की कितनी जीप्स है और कहां कहां ?

(ङ) क्या यह सही है कि गत वर्ष इन गाड़ियों के लिए निर्धारित पैट्रोल की रकम वर्ष पूरा होने से पूर्व ही समाप्त हो गई थी ? यदि हां, तो यह बताया जावे कि किस किस अधिकारी ने इन गाड़ियों में कितना कितना दूर किया ? गत वर्ष के लिये निर्धारित कार्य पूरा हुआ या नहीं। यदि हां, तो कितना कार्य निर्धारित था ? इसके डिटेल्स बताए जावें !

पशु पालन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री भोगजी भाई।

ब्रह्मपुरी में नल लगाना

४४०. **श्री भोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या नगरपालिका, जयपुर, की ओर से जल-प्रदाय विभाग को ब्रह्मपुरी में नल लगाने के लिए कोई आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो कब तथा अब वहां नल कब तक लगा दिये जायेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां। नगरपालिका द्वारा जल प्रदाय विभाग को सितम्बर, १९६० में ब्रह्मपुरी में नल लगाने के लिए आदेश दिये गये थे। ब्रह्मपुरी में केवल दो स्थानों पर पाइप लाइन है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उनमें से एक स्थान पर नल लगा दिया गया है। दूसरी जगह पर नल लगाने के लिए अभी तक किसी ऐसे स्थान का चुनाव नहीं हो सका है जिसके लिए सब निवासी राजी हों। शेष जगहों पर पाइप लाइन नहीं हैं। पाइप के लिए ऑर्डर दे दिये गये हैं। पाइप आने पर नल लगा दिये जायेंगे।

श्री भोगजी भाई : ये कब तक लगा दिये जायेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने उत्तर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

डी०आई० एस० पीज० की होम डिस्ट्रिक्ट में नियुक्तियां

३४१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि डीवाई.एस. पी. रेंक के कई पुलिस अधिकारी अपने जिले में (होम डिस्ट्रिक्ट्स) में नियुक्त हुए हैं ? अगर हां, तो ऐसे कितने व कौन कौन अधिकारी हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि ऐसी नियुक्तियां (पोस्टिंग्स) राज्य सरकार की नीति के विरुद्ध हैं ? अगर हां, तो ऐसी नियुक्तियां करते समय इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां। निम्नलिखित पांच अधिकारी अपने निजी जिलों में नियुक्त हैं :

१. श्री यू. एन. मिश्रा—सी. आई. डी., जयपुर।

२. श्री ओंकारसिंह-लीव रिज़र्व, अजमेर।

३. श्री विजयसिंह-सी.आई. डी., जयपुर।

४. श्री आर. एस. खुटेटा—सेन्ट्रल स्टोर्स, जयपुर।

५. श्री एन. डी. खन्ना-व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु, अजमेर।

(ख) श्री यू० एन० मिश्रा, श्री विजयसिंह और श्री खुटेटा की नियुक्तियां समस्त राजस्थान से सम्बन्धित होने के कारण राज्य सरकार की नीति के विरुद्ध नहीं हैं। श्री खन्ना की नियुक्ति नहीं की गई है उन्हें केवल प्रशिक्षण काल के लिए ही वहां लगाया गया है। श्री ओंकारसिंह को 'लीव रिज़र्व' के रूप में रेन्ज हैड क्वॉटर्स पर लगाया हुआ है। लीव रिज़र्व को आवश्यकतानुसार अन्य जिलों में नियुक्त किया जाता रहा है, अतः उनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के विरुद्ध नहीं पड़ती है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि बीकानेर के जो डीवाई. एस. पी. हैं वे वहां के रहने वाले नहीं हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे चूरू के हैं, जिनके लिए आप फरमा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

Page No.12

सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, पाली की बकाया की वसूली

३४२. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, पाली की आज तक कितनी कितनी रकम किन किन सोसाइटीज़ में बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) किन किन सोसाइटियों में कर्ज़ा ओव-रड्यू हो चुका है और क्यों?

(ग) सरकार ने उसकी वसूली के लिये आज तक क्या कदम उठाये हैं?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, इसका भी उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

रतनगढ़ में हुई चोरियों की बरामदगी

३४३. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कस्बा रतनगढ़ में सन् १९५९-६० में कितनी चोरियां हुईं, कितना माल बरामद हुआ और कितना कितना बरामद करना बाकी है?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : कस्बा रतनगढ़ में सन् १९५९-६० में कुल ११ चोरियां तथा नकबजनी के मुकदमे दर्ज हुए। इनमें पुलिस द्वारा २०७०.७५ रु० का माल बरामद किया जा सका और शेष १९४२.७५ रु० का माल अथक प्रयत्नों के उपरान्त भी बरामद नहीं हो सका।

श्री किशनाराम : १९४२ रुपये का माल बरामद नहीं होने का क्या कारण है?

श्री रामकिशोर व्यास : पता नहीं चला है।

श्री किशनाराम : क्या यह सही है कि यह जो माल बरामद नहीं हुआ है उसके अन्दर पुलिस ने कोशिश तो की, लेकिन उच्च अधिकारियों ने पुलिस वालों को रोक दिया इसलिए यह बरामदगी नहीं हुई है?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री किशनाराम : क्या यह सही है कि चोरी करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार या दूसरे विभाग में कोई कार्यवाही की गई है?

श्री रामकिशोर व्यास : किसी अलग केस का पूछें तो मैं अर्ज कर सकता हूँ, वर्ना कहना मुश्किल है।

श्री किशनाराम : सुना नहीं ठीक से।

श्री रामकिशोर व्यास : किसी खास मुकदमे के बारे में पूछें तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर सकता हूँ, वर्ना अलग अलग कहना मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

Page No.13

पाली जिले में सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट व एक्सट्रा फर्स्ट क्लॉस मजिस्ट्रेट्स की अदालतों में कल्कों द्वारा बयान लिया जाना

३४४. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पाली जिले में कुल कितने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एवम् सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट हैं तथा प्रत्येक के पास कितने कितने फौजदारी मुकदमात एक साल से पुराने पेन्डिंग हैं ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

(ख) क्या यह सत्य है कि सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट व एक्स्ट्रा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कई बार अदालतों में फौजदारी मुकदमात में स्वयं बयान न लेकर क्लर्क ले लेते हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि पाली जिले की मजिस्ट्रेटों की अदालतों में सन् १६६० में कल्कों द्वारा कम से कम १००० गवाहों के बयान कलमबन्द लिए गए हैं ? यदि हां, तो इस पद्धति को रोकने के लिए क्या सरकार कोई उपाय निकालना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

न्याय मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) पाली जिले में सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट की चार अदालतें पाली, बाली सोजत व जैतारण में हैं व असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की एक अदालत बाली में है व एक अदालत मुंसिफ मजिस्ट्रेट देसूरी की है । उपरोक्त अदालतों में एक साल पुराने मुकदमात निम्न संख्या में प्रत्येक अदालत के समक्ष विचाराधीन हैं :—

१. एस० डी० एम०, पाली	२६
२. एस० डी० एम०, बाली	४६
३. एस० डी० एम०, सोजत	६
४. सहायक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी, पाली	२०
५. मुंसिफ मजिस्ट्रेट, देसूरी	२८ ।

(ख) यह सही है कि कभी कभी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में व उनके लिखाने व हिदायत करने के अनुसार रीडर बयानात फौजदारी मुकदमों में लेते हैं ।

(ग) पाली जिले के मजिस्ट्रेटों की अदालतों में करीब ८५० बयानात गवाहान के सन् १६६० में रीडरों द्वारा लिये गये हैं । सी०आर० पी०सी० की धारा ३५५,३५६ के अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष मजिस्ट्रेट द्वारा की गई हिदायत व डिक्टेशन पर रीडर से मजिस्ट्रेट के बयान लिखवा सकते हैं, जो गैर कानूनन नहीं है । कार्य-भार जो दिन दिन बढ़ रहा है उसे देखते हुए इस पद्धति को रोकना सम्भव नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : आपने बताया कि ८५० बयानात कल्कों द्वारा लिए गए । मैं यह अर्ज करता हूँ कि कमिटल प्रोसीडिंग्स में वे बयान लेते हैं ।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : कमिटल में तो दोनों जबानों में लिखते हैं । मजिस्ट्रेट नहीं, सेशन्स जज लिखता है at the time of trial.

श्री मूलचन्द डागा : ये सारे बयानात क्लर्क ले लेते हैं और क्रिमिनल केसेज़ में इन बयानों पर ही निर्णय होता है। वे ८५० बयान लिये हैं तो मेरी समझ में सारे बयान क्लर्कों ने ही लिये हैं। मजिस्ट्रेट साहब घूमते हैं और जजमेंट कागजों पर होता है।

श्री रामकिशोर व्यास : आपका फरमाना ठीक है। उनकी प्रेज़ेन्स में ही लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका और ध्यान आकर्षित इस ओर करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह जो ८५० बयानों के लिये कहा है तो यह रीडरों ने लिये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि कुछ बयानात ऐसे भी हैं जो कि रीडरों के अलावा दूसरे क्लर्कों ने लिये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : क्रिमिनल प्रोसीडिंग्ज़ में जो डे-टू-डे हियरिंग होनी चाहिए वह मजिस्ट्रेट नहीं लेते हैं और गवाह काफी लम्बे अर्से तक चलते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन अधिकारियों के जमाने में रीडरों ने जमानतें और बयानात लिए हैं सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह कोई इल्लीगल नहीं है। मैंने कहा कि सी० आर० पी० सी० के तहत लिख सकते हैं; उनकी प्रेज़ेन्स में ऐसा कर सकते हैं। यह लीगल है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह मामला सीरियस यों भी है कि जुडिशियल फंक्शन्स जो वहां के मजिस्ट्रेट्स हैं उनको एन्ट्रस्ट किये हैं। उनको वे डिस्चार्ज नहीं करते हैं धारा ३५५ और ३५६ के अन्तर्गत। वह तो एक्सेप्शनल सर्कम्स्टान्सेज़ में ही हो सकता है कि वे बयान लिखाते जायें। हाई कोर्ट में स्ट्रिक्चर पास होते हैं, फिर भी सरकार ध्यान नहीं देती। आप इम्प्रोप्राइटी के लिये एक्शन ले सकते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो मैंने कहा ही है।

प्रश्न संख्या ३४५

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

पाली शहर के आयुर्वेदिक 'बी' श्रेणी के औषधालय का 'ए' श्रेणी में परिवर्त्तन

३४६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) पाली शहर के आयुर्वेदिक 'बी' श्रेणी के औषधालय को 'ए' श्रेणी में कब तक परिवर्त्तन कर देने का सरकार का इरादा है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि मंत्री महोदय ने पुराने पाली अस्पताल के कमरे जिनमें

Page No.15

(श्री मूलचन्द डागा)

कि शिक्षा विभाग के इन्सपेक्टर का कार्यालय है, हटवाने को आज्ञा कलेक्टर को दी थी ? यदि हाँ, तो कब और उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

(ग) क्या सरकार उन कमरों को खाली करवा कर आयुर्वेदिक औषधालय को सुपुर्द करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । दो कमरे खाली करने के लिये आदेश २५-४-६० को दिया था, इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स को कमरे खाली करने की कार्यवाही जारी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या आदेश की तामील हुई है ?

श्री भीखाभाई : उन्होंने एजुकेशन विभाग के पास लिख कर भेजा है । वहां से स्वीकृति मिल जायगी तब कमरे खाली कर दिये जायेंगे । मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि वहां से भी आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इस औषधालय में कितने बैड्स रखे गये हैं ?

श्री भीखाभाई : इसके लिये योजना स्वीकृत हो चुकी है ।

डॉ० बहादुरसिंह : 'ए' श्रेणी के औषधालय में बैड्स का प्रोविज़न तो होगा ही ?

श्री भीखाभाई : 'ए' श्रेणी में बैड्स का प्रोविजन है । लेकिन जैसा मैंने बताया था 'ए' श्रेणी के औषधालय के लिये लोग कितनी तैयारी दिखाते हैं, भवन निर्माण के लिये कितनी सहायता देते हैं, इस पर निर्भर है । अब तक जो किया जाता रहा है वह सरकार की तरफ से किया जाता रहा है ।

प्रश्न संख्या ३४७

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखें)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

पंचायत समिति, देवली द्वारा खरीद की गई कुट्टी की मशीनें

३१६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, देवली ने कुट्टी की मशीनें खरीद की हैं ? अगर हां, तो कितनी २ व किस किस फर्म से और कितने २ में ?

(ख) क्या इस खरीद से पूर्व टेन्डर मांगे गये थे ? अगर हां, तो ज्यादा से ज्यादा और कम से कम किस फर्म का टेन्डर आया और किसकी मार्फत खरीद किये गये ?

Page No.16

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(ग) किन २ ग्राम पंचायतों को ये मशीनें सप्लाई की गई और पंचायतों से क्या धन-राशि ली और समिति से क्या ? क्या यह मशीन किसी व्यक्ति विशेष को भी दी गई हैं ? यदि हां, तो किसको ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) जी हां। कुल पन्द्रह मशीनें। मेसर्स कपिला ब्रॉदर्स, नया बाजार, देहली से ६६) रु. प्रति मशीन के हिसाब से खरीदी गई थीं।

(ख) जी हां। ज्यादा से ज्यादा टेन्डर मेसर्स श्री राजकुमार एण्ड ब्रॉदर्स और कम से कम टेन्डर मेसर्स कपिला ब्रॉदर्स, देहली वालों का था। इन मशीनों की खरीद के लिए देहली जाकर अध्यक्ष, कृषि उप समिति, कृषि प्रसार अधिकारी व ५ व्यक्ति जिन्होंने अपने खर्चे से मशीनें खरीदी हैं उनके एक प्रतिनिधि द्वारा खरीद की गई थी।

(ग) जिन पंचायतों को एक एक मशीन दी गई है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। पंचायतों से कोई धन-राशि नहीं ली गई। पांच मशीनें ग्राम धुआं के पांच काश्तकारों को दी गई। ये मशीनें उनके लिये उनके खुद के खर्चे से खरीदी गई थीं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने यह बताया कि टेन्डर मांगे गये थे, तो टेन्डर देहली जाकर मांगे गये थे या वहां जाने से पहले एडवर्टाइज़मेन्ट द्वारा मांगे थे या वैसे ही कार्यवाही कर ली थी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे पास यह जानकारी अभी नहीं है कि टेन्डर मांगे गये थे वे विज्ञापन देकर मांगे गये थे या कैसे मांगे गये थे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : टेन्डर आये थे या कोटेशन आये थे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : टेन्डर के सम्बन्ध में ही एडवर्टाइज़मेन्ट दिया जाता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने कहा कि ५ व्यक्ति अपने खर्चे से गये थे वे कौन थे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वे ५ काश्तकार थे।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह जानकारी माननीय सदस्य पंचायत समिति से ले सकते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप कहते हैं कि ५ काश्तकार थे तो कृषि अधिकारी भी गये थे, तो वे लोग अपने खर्चे से क्यों गये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ५ काश्तकारों का एक प्रतिनिधि गया था और जो मशीनें आई उनमें से ५ उनको दे दी गई थीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फरमाया कि १५ मशीनें खरीदी गई थीं और लिस्ट में यह दिखाया है कि १० दे दी गई तो बची हुई ५ पड़ी हैं या उनका क्या हुआ ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ५ काश्तकारों को दे दी गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जो १० बच गई उनका क्या हुआ ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १५ आईं और १५ ही दे दी गई। १० हैड क्वार्टर पर और ५ काश्तकारों को दे दी गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : १० एक समिति के हैड क्वार्टर पर पड़ी हैं या अलग अलग जगह पर ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अलग अलग।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अलग अलग कैसे, आपने तो कहा कि हैडक्वार्टर पर पड़ी हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

चोर विरोधी पुलिस अभियान

३२०. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) चोर विरोधी पुलिस अभियान के अन्तर्गत कहां कहां कैम्प लगाये गये ? प्रत्येक कैम्प में चोरी के अपराध में कितने कितने स्त्री–पुरुष पकड़े गये ?

दोषी एवं निर्दोष व्यक्तियों की संख्या पृथक २ शिविरों में कितनी रही ?

(३) अपराधियों के पास किस किस चोरी का कितना कितना माल बरामद हुआ ? इस अभियान पर सरकार का कितना व्यय हुआ ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) एक जनवरी, सन् १९६० से आज तक कुल १० स्थानों पर ऐसे कैम्प लगाये गये जिनमें बन्दी बनाये गये स्त्री–पुरुषों की संख्या इस प्रकार है :

१	२	३	४
जिला	स्थान	पुरुष	स्त्री
चित्तौड़गढ	बान्सी	७	—
	जवासा	१०	—
टोंक	निवाई	१५	—
	देवली	४	—
जयपुर	चन्दवाली	६	—
अजमेर	मांगलियावास	६	२
अलवर	प्रतापगढ़	१	—
	खेडली	—	—
बीकानेर	बीकानेर	१८	—
सीकर	अजीतगढ़	७२	—

(२) प्रश्न एक में बताये गये बन्दी हुए अपराधियों में से २५ व्यक्तियों को पर्याप्त प्रमाण न होने के कारण छोड़ दिया गया। शिविर जवासा में ६, देवली में १, चन्दवाजी १, प्रतापगढ़ में १ तथा अजीतगढ़ में २६।

(३) कुल ४४ चोरियों हुईं जिनमें कीमतन ३६,५२० रु० ४७ न० पै० एक मोहर बन्द संदूक, एक धोती, एक चद्दर एक

Page No.18

(श्री रामकिशोर व्यास)

ब्लाउज़, एक साड़ी, एक बैल तथा १७ वस्त्र बरामद हुए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह कैम्प लगाने का, कैम्प आप कब करते हैं और किस स्थिति में करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास: क्या फरमाया ?

श्री मूलचन्द डागा : कैम्प या अभियान करते हैं, वह किस आधार पर करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह उनकी डिस्क्रीशन पर है; जब चाहें तब और जहां चाहें कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या इन चोरियों को बरामद करने में साइन्टिफिक मैथड्स एप्लाई किये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या कुछ औरतें भी पकड़ी गई थीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मांगलियावास में पकड़ी गई थीं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : मेरे पास ८ के नाम हैं जिनको पकड़ा गया था; उनमें से कुछ ये हैं: सुरती, कचूड़ी, टाखली। क्या उनको पकड़ कर उनके साथ बलात्कार भी किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह बिल्कुल झूठी बात है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह झूठी बात नहीं है, मेरे पास रिपोर्ट है, उनके हल्फनामा वगैरा हैं, आप चाहें तो मैं पढ़ कर सुना सकता हूँ....

श्री रामकिशोर व्यास : Absurd.

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आप मानें चाहे न मानें, उन पर बलात्कार किया गया नंगा करके।

श्री अध्यक्ष : हलफनामा किसने दिया है ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैं जाकर लिखा कर लाया हूँ।

श्री अध्यक्ष : केवल लिखाने से कुछ नहीं होता।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': लिखा कर लाया हूँ। एक भी चोरी साबित नहीं हुई, आप रेकॉर्ड मंगा कर देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : रेकॉर्ड आप मंत्री महोदय को भेजें।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मंत्रीजी को कई बार कहा, डेपुटेशन भी मिल कर गये, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिल्ली तक यह मंत्रीजी के पास भी गये। शिड्यूल्ड कास्ट के कई आदमी जानकारी के लिये नियुक्त हुए थे और उन्होंने भी इस बात की शिकायत की है।

श्री रा किशोर व्यास : मारने की शिकायत आई थी, लेकिन यह नहीं लिखा था कि बलात्कार किया गया।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : जो आदमी जांच करने गये थे उनसे हलफिया कहने को कहा जाय तो वे कहेंगे कि ऐसा अत्याचार किया गया था कि देखा नहीं गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जब एक माननीय सदस्य ने जानकारी करके रिपोर्ट दी है पुलिस एट्रोसिटीज़ के बारे में, तो क्या इस बारे में जांच कराने का सरकार का कर्त्तव्य नहीं है?

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.) जिनको गिरफ्तार किया गया उनके पास से माल बरामद नहीं होने से वे छूट गये तो उन गिरफ्तार करने का क्या कारण था?

श्री अध्यक्ष : जितनी भी चोरियें होती हैं उन सब में माल बरामद नहीं होता है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह बुरी बात है, अबलाओं पर अत्याचार करते हैं, उनको मारते हैं! यह तो कहें कि इन्क्वायरी करायेंगे।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष, ऐसे ही सवाल का गये साल उत्तर दिया था। उस वक्त, माननीय मंत्री ने कहा था कि थोड़े लोगों को गिरफ्तार किया था इस कैम्प में, उन्होंने औरतों के साथ बलात्कार किया था। उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। उसका मतलब होता है कि बड़े बड़े लोगों के लिए ही सरकार चलती है और उनके द्वारा ही शासन चलाया जाता है जिन्होंने औरतों के साथ बलात्कार किया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि इस तरह की शिकायत हमारे पास आज तक नहीं आई। कई व्यक्तियों ने कहा है कि मेरे साथ यह ज्यादती हुई, मेरे साथ मार-पीट हुई। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की बात उनके सामने नहीं आई। अगर आये तो वे जांच करने के लिए तैयार हैं।

श्री हीराभाई : मंत्री महोदय का ध्यान हमने आकर्षित किया था। उन्होंने कहा था कि वे जल्दी जानकारी करके कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कार्यवाही नहीं की, इसका कुसूर किस पर पड़ेगा?

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : क्या भोगीलाल पंड्या अपनी रिपोर्ट सरकार के पास दे चुके हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : I have given reply.

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री के पास इस प्रकार की शिकायत आये तो जांच करनी चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास : वह हमेशा कहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इस प्रकार की शिकायत आई नहीं?

श्री रामकिशोर व्यास : इस प्रकार की नहीं आई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस प्रकार की शिकायत नहीं आई, यह खड़े होकर कहें, कि इस प्रकार की शिकायत नहीं आई । अध्यक्ष महोदय, कुछ आदमी आये थे, एम० एल० एज़० से मिले थे, मेरे से भी मिले थे । उन्होंने बताया कि शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की रिपोर्ट में इस बात को लिखा है । वह कम्प्लीट रिपोर्ट आपको दे दी । आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास शिकायत नहीं आई ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने यह नहीं कहा कि शिकायत नहीं आई, लेकिन जिस नेचर की शिकायत की बात कहते हैं, इस प्रकार की शिकायत नहीं आई ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इन सारे बयानात को मंत्री महोदय को पेश करना चाहता हूँ ।

श्री रामकिशोर व्यास : आप शौक से दे सकते हैं, मैं इन्क्वायरी करा लूंगा ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय के द्वारा देने में आपको क्या एतराज है ताकि ये बीच में जिम्मेदार बने रहें, पूरा रेकॉर्ड दे रहा हूँ, इसको भी गायब न कर दें ।

श्री रामकिशोर व्यास : आपके द्वारा दे दें, मुझे एतराज नहीं ।

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल' ने पत्र गृह मंत्री को दिये)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मुझे चार महीने लगे हैं इसकी इन्क्वायरी करने में । अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है । जो बिजली का करेंन्ट लगाया जाता है, क्या उस मशीन का नाम 'पंत' मशीन है ?

श्री हीराभाई : उस वक्त दो औरतों को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उनके खाविंद भाग गये थे । उस समय मंत्री महोदय ने कहा था कि कार्यवाही करेंगे । आज कहते हैं, शिकायत आती नहीं है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : जो बिजली का करेंन्ट लगाते हैं; यह कहते 'लगाओ पंत मोहर, पंत मोहर लगा दो इनके' । उस पंत मोहर को गुप्त अंगों पर नंगा करके लगाते हैं, यह शर्म की बात है ।

('शेम-शेम' की आवाज)

श्री रामकिशोर व्यास : आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको जिम्मेदारी के साथ सारी बात कहनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

किशनगढ़ मैटल वर्क्स के बरामदशुदा तांबे का मामला

३२२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि किशनगढ़ पुलिस ने २–६–६० को स्थानीय मैटल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वर्क्स का तांबा देहली जाते हुए पकड़ा था ?

(२) यदि हां, तो क्या उसे छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या कोई जमानत ली गई थी ? यदि हां, तो किसकी और कितने की ?

(३) क्या इस सम्बन्ध में एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट, जयपुर को कोई शिकायत इस प्रकार की की गई कि उपरोक्त माल को स्थानीय एस० डी० ओ० व डीवाई०-एस० पी०, किशनगढ़ ने रिश्वत खाकर माल छोड़ा है ?

(४) अगर हां, तो क्या एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट ने इसकी इन्क्वायरी की है ?

(५) अगर हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ? अगर नहीं, तो क्यों नही ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं, २–६–६० को किशनगढ़ पुलिस ने ट्रक नं० ३६६३ को उसमें अगली सीट में पार्टिशन व लाइट न होने से रोका था। इस ड्राइवर का चालान भी किया उसमें महेश मैटल वर्क्स, मदनगंज के तांबे के टुकड़ों के पैकेज भी थे।

(२) जी नहीं, पुलिस ने कब्जे में नहीं लिया। ट्रक के ड्राइवर का चालान जेर दफा १६५ मोटर विहीकिल्स एक्ट लाइट व पार्टिशन न होने से किया गया, तांबे के टुकड़े लाने–ले जाने की कानूनी रोक न होने से जप्त नहीं किया। अतः छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) जांच करने के पश्चात् किसी के विरुद्ध किसी प्रकार की रिश्वत लेने का आरोप साबित नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव।

भूपालसागर तालाब की पाल

३३२. **श्री हरिप्रसाद यादव** (वल्लभ-नगर-सु.) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या भूपालसागर तालाब की पाल को तीन फीट ऊंचा उठाया जा रहा है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : जी नहीं। ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव : क्या यह सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस तालाब की पाल को तीन फीट ऊंचा उठाने का प्रावधान था ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : मैं निवेदन कर चुका हूँ, 'जी नहीं, ऐसा नहीं था।' इस तालाब की अब जितनी ऊंचाई है, उतना भी पूरा नहीं भरता, इसलिए पाल को तीन फीट ऊंचा उठाने की आवश्यकता नहीं है।

Page No.22

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस तालाब में पांच वक्त तीन फीट तक चद्दर चली है। जब तालाब भरा तो तीन फीट तक पानी जाता है। इसलिए बजट में देखते हैं कि इस तालाब को तीन फीट ऊंचा उठाने का प्रावधान था। मैं माननीय उप मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस तालाब की पाल को ऊंचा उठाने का प्रावधान है। गवर्नमेंट ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसे सर्वे में ले लिया, इसका एस्टीमेट बनाया गया, सारी चीजें हो गईं, अब अगर उस तालाब की पाल को तीन फीट ऊंचा उठाया जाता है और भगवान् की कृपा से वर्षा हो जाती है और उसमें पानी भर जाता है तो उससे किसानों की फसल की जो अवस्था है उस एक फसल की जगह दो फसलें होंगी। माननीय उप मन्त्रीजी को इसमें क्या एतराज है ?

श्री भीखाभाई : उस पूरे तालाब की केपेसिटी ६५५ मिलियन क्यूबिक फीट है। लगभग १० फीट के अन्दर छः वर्ष तक लगातार पानी भरा नहीं है, उसकी फुल कैपेसिटी तक पानी नहीं भरा। जैसा माननीय सदस्य कहते हैं उस तालाब का सर्वे हुआ था। सर्वे पूरा हुआ ५६ में, उसके बाद में डेढ़ फीट ऊंचाई बढ़ाने का प्रपोज़ल था लेकिन बढ़ाया नहीं गया इसलिए कि पानी नहीं चढ़ता है।

एक माननीय सदस्य : यज्ञ करवा लीजिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : क्या यह सही है कि भूपाल सागर का तालाब सिंचाई विभाग की दुर्व्यवस्था के कारण इस तरह बन गया कि पांच वर्ष पहले जो यह तालाब भर जाता था, इसका पानी रुक गया ?

श्री भीखाभाई : यह जानकारी रेडिली अवेलेबल नहीं है। माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसमें पानी भर जाय, तो मैं निवेदन कर दूं कि मातड़ी डेम से पानी देने की व्यवस्था की जा रही है, उसकी डिटेल्स वर्क आउट की जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

जिला बांसवाड़ा के वन विभाग द्वारा जंगल की पैदावार का दिया जाने-वाला ठेका

३०५. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के वन विभाग ने जिले के समस्त जंगल की छोटी-मोटी पैदावार को ३० वर्ष की अवधि पर ठेका दियाजाने का निश्चय किया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में वन विभाग, बांसवाड़ा ने नक्शे आदि बना कर सरकार को पेश किये हैं ? यदि हां, तो जिले के वन विभाग की आमदनी का क्या आधार माना है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि उक्त जिले के वन विभाग ने एरिया का डिमार्केशन किसानों के खेतों के नजदीक किया है जिसमें इमारती लकड़ी नहीं है ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : बांसवाड़ा जिले के degraded सागौन के dlear felling से उपलब्ध सागौन की लकड़ी के integraded saw एवं chip board फेक्ट्री में बेहतर उपयोग के लिए फेक्ट्री खोलने के लिये सरकार बातचीत कर रही है। Lease की अवधि २० से ३० वर्ष होने की सम्भावना है।

(ख) जी नहीं। अभी बातचीत इस अवस्था में नहीं पहुंची है।

(ग) जी नहीं।

श्री मोगजी भाई : क्या यह सही है कि सरकार उससे जिस फेक्ट्री के खोलने की बातचीत कर रही है किन शर्तों पर सरकार उस फेक्ट्री के मालिक को वन देगी, किस आधार पर, किस प्रकार जंगल का ठेका देगी; पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक साथ देगी या अलग अलग एरिया के कूप बना कर देगी ? इस प्रकार की जानकारी दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी मैंने कहा कि यह सारा मामला बातचीत की स्टेज पर है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : बिना प्लान बनाये कैसे बातचीत हो रही है ? फेक्ट्री बनाने के लिए ठेका किस आधार पर दिया जायगा और कई फेक्ट्रीज़ चलती होंगी उनमें रखी गई शर्तों पर ठेका देगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा है, आधार तो क्या है। कोई आदमी वहां फेक्ट्री लगाना चाहता है, टीक जंगल का डिग्रेडेशन करना है, अच्छी टीक का उपयोग हो, यह व्यवस्था करनी है। यह देखते हैं कि कुछ तो लकड़ियों की छोटी-मोटी चीजें निकाली जायं, इस तरह की फेक्ट्रीज़ लगाई जाय। इस उद्देश्य से बातचीत हो रही है।

श्री हीराभाई : स्थानीय लोगों के लिए लकड़ी के लिए कुछ भाग रखा जायगा या पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट उनको दे दिया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा नहीं है, लोगों के लिए लकड़ी का प्रबन्ध रहेगा। जिसके साथ बातचीत चल रही है, उसमें यह व्यवस्था रखेंगे कि जो लोगों के राइट्स हैं वे कायम रहें।

श्री मोगजी भाई : यह कब तक दिये जाने का विचार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : निश्चित समय नहीं बताया जा सकता।

श्री मोगजी भाई : एक वर्ष, दो वर्ष, कब तक खोलेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि निश्चित समय नहीं बता सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद यादव।

भूपालसागर तालाब को मांथड़ी बांध की नहर से पानी

३३०. **श्री हरिप्रसाद यादव** (वल्लभनगर-मु०) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हरिप्रसाद यादव)

क्या यह सच है कि भूपालसागर तालाब को पानी मांधड़ी बांध से देने के सम्बन्ध में कार्यवाही दो वर्ष से चल रही है, किन्तु पानी अभी तक नहीं दिया गया ? क्या यह भी सही है कि मांधड़ी बांध की नहर बन कर भूपालसागर से तीन माईल दूर ससेरा तालाब में यह नहर डाल दी गई है।

यदि हां, तो इस नहर का पानी भूपालसागर तालाब को क्यों नहीं दिया गया ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर जो पहले दिया जा चुका है, उससे सम्बन्धित है।

जी नहीं। ऐसी कोई कार्यवाही नहीं चल रही है।

जी नहीं। मांधड़ी बांध की नहर भूपालसागर से लगभग १२ मील दूर भराई तालाब में डाली गई है। यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय मन्त्री कहें कि मांधड़ी बांध की नहर कब तक निकाल दी जायगी और पानी कब तक भर दिया जायगा ?

श्री भीखाभाई : यह केस अन्डर इन्वेस्टिगेशन है। उसकी डिटेल्स वर्क आउट करने पर ही कहा जा सकता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्या सम्भव है क्या असम्भव है।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने फर्माया कि ३२३ प्रश्न के जवाब में दिया है कि मांधड़ी बांध की नहर से पानी दे दिया जायगा और इस प्रश्न ३३० के उत्तर में आप इसको गोलमाल करें, मैं क्या मान कर चलूं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सिंचाई मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इसका उत्तर तो स्पष्ट दें।

श्री भीखाभाई : मैं अर्ज कर चुका हूँ, पानी देने का इरादा सरकार रखती है। पानी दिया जाय, नहर से दिया जा सकता है, या दूसरे तालाब में डाल कर दिया जा सकता है, यह टैक्निकल विषय है, अभी मैं इस बारे में जवाब नहीं दे सकता।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष, वहां की जनता श्रमदान देने को तैयार है, गवर्नमेंट पैसा दे तो किसान लोग मेहनत करने को तैयार हैं, मेहनत करके नहर तैयार करने को तैयार हैं।

श्री भीखाभाई : इसका स्वागत किया जाता है, आगे विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

लोक गीतों तथा लोक नृत्यों के आयोजन एवं प्रदर्शन हेतु निर्मित समितियां

३३२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने लोक गीतों तथा लोक-नृत्यों के आयोजन एवं

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

प्रदर्शन हेतु समितियां बनाई हैं ? अगर हां, तो कहां कहां ?

(ख) क्या सरकार से उपरोक्त समितियों के लिये कोई धन-राशि स्वीकृत कर प्रदान की है? अगर हां, तो कितनी कितनी सन् ५८, ५९ व ६० में प्रदत्त धन-राशि की जिलेवार सूची देने का कष्ट करें।

(ग) क्या टोंक जिले में भी ऐसी कोई समिति बनाई गई है ? अगर हां, तो कहां २ और अब तक किस कदर लोक गीतों व नृत्यों से संबन्धित संग्रह हुआ ? अब तक टोंक जिले में साल वाइज़ कितनी धन-राशि दी गई तथा उसका संचालन कौन कर रहा है ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) सहकारी विभाग द्वारा कोई नहीं।

(ख) सहकारी विभाग के बजट से कोई नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद यादव।

जेवाणा, झावा व पटोल्या तालाबों का निर्माण

३२७. **श्री हरिप्रसाद यादव** (वल्लभ-नगर-सु.) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

जेवाणा, झावा व पटोल्या तालाबों (तहसील भूपालसागर) को कब तक बना दिया जावेगा ?

सिंचाई उप-मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष, मन्त्री महोदय फरमा रहे हैं कि सर्वे नहीं हुआ है, हमारे यहां सब तालाबों की सर्वे हो गई है। यह बतायें कि कब तक काम शुरू होगा ?

श्री दौलतराम सारण : माननीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रस्तुत कर चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल कालाबादल : माननीय अध्यक्ष, ३४७ जवाब दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : Yes.

जयपुर कोटा बस रूट को झालावाड़ तथा भोपाल तक बढ़ाना

३४७. श्री **रामचन्द्र** (डग-सु.). [भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा-सु,) द्वारा

(श्री रामचन्द्र)

पूछा गया]: क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) जयपुर से कोटा डिवीज़न में चलने वाली मोटर बस रूट का अन्तिम स्टेशन झालावाड़ होते हुए भी यह बस सर्विस केवल कोटा तक ही क्यों चलाई जा रही है।

(२) क्या सरकार इस रूट को भविष्य में झालावाड़ तक बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(३) क्या इस रूट को भोपाल तक भी बढ़ाने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो इस रूट का दर्मियानी डिपो कहां होगा?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) वर्तमान में जयपुर से कोटा व जयपुर से झालावाड़ तक कोई सीधी बस-सेवा उपलब्ध नहीं है। अतः, जयपुर से कोटा मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है।

(२) नहीं।

(३) नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(११. ४६. म. पू.)

मांग संख्या २२—उद्योग और प्रदाय

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३--उद्योग और प्रदाय के संबंध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५७,९८,००० रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :—

(१) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग एवं रसद में एक रुपये की कटौती की जाय (शिल्प केन्द्रों की स्थापना करने में विभागीय अकर्मण्यता पर विचार करने हेतु)

(२) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग एवं रसद में एक रुपये की कटौती की जाय [औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दिये जाने वाले कोटा (Quota) के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु]

डॉ० बहादुरसिंह :—

(३) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग तथा प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (चमड़ा, सिलाई केन्द्रों की अव्यवस्था पर बहस करने के लिये)

(४) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३— उद्योग तथा प्रदाय में एक रुपये की

Page No.27

(डॉ० बहादुरसिंह)

कटौती की जाय (धौलपुर उद्योग बस्ती के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने पर बहस करने के लिये)

(५) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग तथा प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (कपड़े के उत्पादन में गिरावट पर बहस करने के लिये)

(४२) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग और प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (इम्पोर्ट के लिये दिये गये लाईसेन्स पद्धति पर वाद–विवाद करने हेतु)

(३९) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग और प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (माचिस फैक्ट्री धौलपुर को चलाने पर बहस करने के लिये)

(४०) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग और प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (उदयभानु इन्डस्ट्रीज की स्थिति पर बहस करने के लिये)

(४७) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग और प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (भरतपुर में दिये गये लोहे के परिमिटों पर वाद–विवाद करने हेतु)

श्री भैरवलाल कालाबादल :—

(६) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग और प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (उद्योग सम्बन्धी सुविधाओं के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु)

श्री मूलचन्द डागा :—

(९) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग और प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (बुनकरों की सोसाइटियों को कम आर्थिक सहायता देने के कारण उनका विकास न होने पर बहस करने के लिये)

(१०) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग और प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (घरेलू उद्योगों की आवश्यक प्रगति न होने पर बहस करने के लिये)

(११) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग और प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (पाली जिले में कोयले का संतोषजनक तरीके से ठीक कीमत पर वितरण न होने पर बहस करने के लिये)

(१२) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग एवं प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (उद्योग विभाग में अव्यवस्था के कारण उद्योगों की प्रगति में रुकावट पर बहस करने के लिये)

(३०) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग एवं प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (खादी बोर्ड की दी जाने वाली सहायता पर बहस करने के लिये)

श्री मुरलीधर व्यास :—

(२१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग तथा रसद में एक रुपये की

श्री मुरलीधर व्यास)

कटौती की जाय (बीकानेर शहर के औद्योगिक विकास पर बहस करने हेतु)

(२२) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग तथा रसद में १) रुपये की कटौती की जाय (भीलवाड़ा मील की अव्यवस्था पर प्रकाश डालने के लिये)

श्री लक्ष्मीचन्द :—

(२३) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग तथा रसद में १००) रुपये की कटौती की जाय (सप्लाइज़ विभाग के प्रशासक की अव्यवस्था पर विचार करने हेतु)

(२४) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग तथा प्रदाय में १००) रुपये की कटौती की जाय (सप्लाईज़ विभाग के कर्मचारियों के एब्जोर्पशन पर विचार करने हेतु)

(२५) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग और प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (जालोर जिले के उद्योग धन्धों की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिये वाद-विवाद करने हेतु)

(२६) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग व प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (जालोर जिले में सप्लाइज़ विभाग द्वारा लोहे व सीमेन्ट के कोटा के विभाजन पर विचार करने हेतु)

श्री भीमसेन :—

(२७) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग और प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान के औद्योगीकरण की मन्द गति की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु)

(६३) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग तथा प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (लीज Holders द्वारा शर्तों के मुताबिक लूणकरणसर में प्लास्टर ऑफ पैरिस की फैक्ट्री लगवाने की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु)

श्री पी० के० चौधरी :—

28. Demand No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to encourage establishment of adequate number of power houses in the State).

29. Demand No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to publish a detailed report on the state of existing manufacturing industries in the State).

30. Demand No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to conduct a survey for the assessment of consumer's demand for various types of manufactured commodities in the State).

31. Demand No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be

(श्री पी० के० चौधरी)

reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to establish a Steel Plant at Jaipur).

32. Demand No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to establish an Industrial Estate at Sambhar).

33. Demand No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (to discuss the Government's failure to conduct an Intensive Industrial Survey of Jaipur District).

34. Demand No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to prepare a project report for Soda ash factory at Sambhar).

35. Demand No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (to discuss the question of reorganisation of the Industries Deptt).

36. Demand No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (to discuss the question of reducing the number of posts in the grade of Rs. 500-900 in the Deptt.)

37. Demand No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (to discuss the question of reducing the number of posts of Joint Directors in the Department.) .

38. Demand No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to check the misuse of facilities provided by the Government for industrial developments of the State).

(१) श्री चन्दनमल वैद,

(२) श्री श्रीमानसिंह व

(३) डॉ० बहादुरसिंह :

44. Demand No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (to discuss non-availability of Milk Powder to Rajasthan).

(१) श्री चन्दनमल वैद व

(२) श्री श्रीमानसिंह :

45. Demand No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (to discuss non-availability of G. I. sheets and cement).

46. Demand No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (to discuss essential certificates issued by the Deptt.)

Page No.30

श्री चन्दनमल वैद :—

(४३) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग और प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (उद्योग विभाग के पुनर्गठन पर बहस करने के लिये)

श्री हीराभाई :—

(४८) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग और प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (छोटे उद्योगों को पनपाने पर विचार करने हेतु)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :—

(५१) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग और प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (उद्योग विभाग में नियन्त्रण के अभाव पर बहस करने हेतु)

(५२) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग और प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (औद्योगिक सम्पदाओं की उचित व्यवस्था न होने पर बहस करने के लिये)

(५३) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग और प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाय (कुटीर उद्योगों को लोकप्रिय नहीं बनाये जाने पर बहस करने के लिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह :—

54. Demand No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (for discussing the failure of the Government to establish a big Industry in District Tonk).

55. Demand No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (to discuss the mismanagement of the Government with regard to the supply of coal for daily use).

श्री अनूपसिंह :—

57. That the Demand No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government in developing Cottage Industries in Balotra).

58. That the Demand No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government in developing modern Industries in District Barmer).

59. That the Demand No. XXII- Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government in the proper distribution of Cement and Iron and Steel goods).

श्री सोहनलाल भटनागर :—

60. That the Demand No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (to discuss

Page No.31

(श्री सोहनलाल भटनागर)

the failure of the Government to start large and medium size industries in public sector).

61. That the Demand No. XXII, Major Head 44-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to fix separate quotas of steel, cement and sheets for Municipal areas in Rajasthan).

श्री भैरोंसिंह :–

(६४) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग तथा रसद में एक रुपये की कटौती की जाय (Controlled commodities) के परमिट वितरण एवम् उपयोग में अव्यवस्था पर बहस करने के लिए)

(६५) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग तथा रसद में एक रुपये की कटौती की जाय (खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को दी जाने वाली सहायता पर बहस करने के लिए)

श्री भैरोंसिंह : क्या ये प्रस्ताव एक साथ मूव किये हुए समझे जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यही उचित होगा। सभी मूव किये हुए समझे जायं, जो माननीय सदस्य बोलना चाहें बोलें।

डॉ० बहादुरसिंह : कटौती के प्रस्तावों पर क्रमशः बोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : उचित तो यही होगा कि क्रमशः बोलें। पर यह माना जायगा कि सभी कटौती प्रस्ताव मूव कर दिये गये।

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २२ मुख्य शीर्षक ४३, उद्योग एवं रसद के सम्बन्ध में जो मांग प्रस्तुत की गई है उसके सम्बन्ध में मेरे कुछ कटौती के प्रस्ताव हैं। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, जो कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनके सम्बन्ध में भी मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगा।

उद्योग के सम्बन्ध में आगामी पंचवर्षीय योजना की दृष्टि से लगभग ५३० लाख रुपयों की धन–राशि रखी गई है। राज्य में जब कभी भी बेकारी को दूर करने के सवाल खड़े होते हैं, राज्य के विकास के प्रश्न खड़े होते हैं तो राज्य में औद्योगीकरण के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री महोदय मुख रूप से चर्चा करते हैं। राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के बहस के अवसर पर और बजट पर सामान्य वाद–विवाद के समय सदन के माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि राज्य में औद्योगीकरण की जो नीति अपनाई गई है वह ठीक नहीं है, राज्य में उद्योग नहीं पनप रहे हैं, न पब्लिक सेक्टर में पनप रहे हैं, न प्राइवेट सेक्टर में और न कोऑपरेटिव सेक्टर में। तो मैं कह सकता हूँ कि औद्योगिक दृष्टि से राज्य को जितना आगे बढ़ना चाहिये हमारा राज्य इस सम्बन्ध में आगे नहीं बढ़ पाया है। इसका

Page No.32

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एक मात्र कारण अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ, यह है कि हमारे यहां का आज जो औद्योगिक विभाग है, उसमें भारी अव्यवस्था है, जो अधिकारी हैं उनका भी जो दृष्टिकोण होना चाहिये वह दृष्टिकोण नहीं है। इस सन्दर्भ में एक बात मैं सरकार के सामने कहना चाहूँगा कि इन्डस्ट्रीज़ का डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि जिसका डाइरेक्टर आये दिन बदलता रहे। पर अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन चार साल के काल में इस विभाग के तीन चार डाइरेक्टर बदल चुके हैं। यह मानी हुई बात है कि कोई भी अधिकारी कार्यभार सम्हालता है तो उसको उस विभाग के कार्य को सम्हालने में समझने में और सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में समय लगता है, विशेष कर के ऐसा डिपार्टमेंट जो कि टेक्निकल हो उसके सम्बन्ध में हमेशा इसी पोइन्ट ऑफ व्यू से बात की जाती है। आज देश में जिस प्रकार की औद्योगीकरण की नीतियां चल रही हैं, इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन की जिस प्रकार की बातें विश्व में चल रही हैं, उस दिशा में जिसको रुचि नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, लगन के साथ काम नहीं करेगा तब तक राज्य में किसी प्रकार भी औद्योगीकरण नहीं हो सकता; केवल दस्तखत कर देना, ग्रान्ट दे देना, सब्सिडी दे देना, लोन एप्लीकेशन्स आयें उनको फोर्वर्ड कर देना, यही डाइरेक्टर का काम नहीं है। यदि आप राजस्थान में उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं, राज्य को औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि जो औद्योगिक विभाग का डाइरेक्टर हो उसको तीन—चार साल के लिये काम करने का मौका दें।

मैं समझता हूँ, राज्य सरकार ने औद्योगिक विभाग के सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित की है और बजट में भी इस बात का इंगित किया है—औद्योगिक विभाग का पुनर्गठन कर रही है, सारे ढांचे में परिवर्तन करने जा रही है। यह तो बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने इस प्रकार की आवश्यकता को अनुभव किया महसूस किया पर यह बात अवश्य है, और यह कह सकता हूँ कि हम चाहे बातें कितनी ही करें, इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन की बातें करें पर इन्डस्ट्रियल दिशा में जितनी प्रगति करना चाहिये बिलकुल नहीं कर पाये हैं। जयपुर जिले में कोई पब्लिक सेक्टर में इन्डस्ट्रीज़ राज्य सरकार कायम नहीं कर सकी है, जितनी हैवी इन्डस्ट्रीज़ राज्य में चल रही हैं वे उस जमाने की हैं जब कि कांग्रेस की हुकूमत नहीं हुई थी। १९४९ के बाद में सरकार ने कोई भी इन्डस्ट्री, पब्लिक सेक्टर में, या प्राइवेट सेक्टर में नहीं चलाई है।

छोटी इन्डस्ट्रीज़ के बारे में निवेदन करूं, इन्डस्ट्रियल एस्टेट में क्या काम होता है, कितना कोटा दिया जाता है, कितना प्रोडक्शन होता है, कितना माल तैयार किया जाता है, कितनी उसकी खपत होती है, कोटा जो दिया जाता है उसका प्रोपर युटिलाइज़ेशन होता है या नहीं, इस पर राज्य सरकार कोई नियन्त्रण नहीं रखती। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, न नाम लेकर कहूँगा; बल्कि उद्योग मन्त्री के ध्यान में यह लाना चाहूँगा कि इन्डस्ट्रियल एस्टेट का जितना कोटा इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की ओर से राजस्थान में दिया जाता है, उसका सही उपयोग नहीं होता है।

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

(१२ मध्याह्न)

यह बात सच है कि आज कोई भी आदमी बेकार बैठा हो और उसके पास काम धन्धा नहीं हो तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार ट्रान्सपोर्ट से एक परमिट लेकर साल भर की कमाई कर सकता है अगर उसी प्रकार इन्डस्ट्रीज़ विभाग से किसी को कोटे का परमिट मिल जाए तो दो साल की कमाई उसके हो सकती है। कोटा वे लोग ले लेते हैं और उसको ब्लैक में बेच दिया जाता है। यही कारण है कि जिस प्रकार से इन्डस्ट्रियल स्टेट में जिस मात्रा में प्रोडक्शन होना चाहिये नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई 'मिली भगत' भी हो सकती है। कई बार इसके लिये अखबारों में भी आया था कि आये दिन इस प्रकार के घोटाले इन्डस्ट्रीज़ में हो रहे हैं। लोगों को कोटा नहीं मिलता है और जो कोटा जिस किसी को दिया जाता है वह जनता को नहीं देता और उस माल को ब्लैक में दे दिया जाता है। जिस स्थान के लिये प्रयोग में आने के लिये वह माल दिया जाता है वह दूसरी जगह भेज दिया जाता रहा है। इसलिये इन्डस्ट्रीज़ से जो कोटा जिलों को दिया जाता है उसके सम्बन्ध में मैं यह समझता हूँ कि उनको सर्टिफिकेट देने से पहले इस बात की जानकारी सरकार को पूरी तरह से करनी चाहिये कि पहले उनको जो कोटा दिया गया था उसका दुरुपयोग तो नहीं किया गया है; आया लोगों को उस कोटा का सामान दिया गया या नहीं? उस जिले की आवश्यकता क्या है और कितना कोटा उनको दिया जावे? उसके लिये स्टेटमेंट आदि जिसकी जरूरत हो वे सारे उनसे ले लें। इसके लिये जितने भी इन्सपेक्टरों को नियुक्त करने की जरूरत हो उनकी नियुक्ति भी कर लें और सख्ती से काम करें। जिससे कोटा जो लोगों को दिया जाता है वह ब्लैक में नहीं जाने पाए। अगर किसी दूकानदार का कोटा ब्लैक में बेचा हुआ पाया जावे तो उसको केवल चेतावनी देकर ही नहीं छोड़ दिया जावे, लेकिन उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाये जावें।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया और विशेष रूप से राजस्थान में, जयपुर में जैसी इन्डस्ट्रीज़ की बातें सुनी कि कोटा में लिनेन और उदयपुर में सूती टैक्सटाइल शुरू हो रहे हैं। यह भी कहा गया कि मिलें बन्द होती जा रही हैं इसलिये आप उनको टेक-ओवर करना चाहते हैं। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता कि उनको टेक-ओवर करना और चालू करना, किस प्रकार लेबरर्स के हित में पड़ेगा? मगर इन सारी बातों को सोचते हुए हमारी पब्लिक की इन्डस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देने के लिये, तीसरी पंच वर्षीय योजना में धन-राशि दी है उसे हैवी इन्डस्ट्रीज़ के बजाय लघु उद्योगों में लगाने की आवश्यकता है। मैं कहूँगा कि हैवी इन्डस्ट्रीज़, चाहे स्टील की हो, चाहे किसी दूसरी चीज़ की हो जयपुर में लगावें; मगर छोटे छोटे उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देने की बहुत आवश्यकता है। इनको प्रोत्साहन देने का मतलब यह नहीं कि इनको केवल ग्रान्ट-इन-एड दी जाए या सब्सिडी दी जाए। मगर आज इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। हमारा इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट यह समझता है कि जितनी धन राशि जिस जिस को देनी है उसको वितरण कर दिया जाता है तो वह समझता है कि हमारा कर्त्तव्य पूरा हो

Page No.34

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गया। मगर आज जो धन–राशि लोन या सब्सिडी के रूप में किसी को देनी चाहिये उसको देने से ही सारी उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती और यह नहीं कहा जा सकता कि हमने अपना जो टार्गेट था उसको एचीव कर लिया और अपनी डयुटी पूरी कर दी। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में बेकारी और कुटीर उद्योग की जो हालत है उसे देखते हुए यह कहा जाय कि राजस्थान के प्रोडक्शन की हालत ठीक है और उन्नति हो रही है, तो मैं कहूँगा कि यह प्रगति हलकी हो रही है। हमारे यहां का विभाग किसी प्रकार से उन पर कन्ट्रोल रखने में सफल नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब सदन के सामने कुछ बातें रखना चाहूँगा। हमारे बजट में कुछ कटौती के प्रस्ताव उद्योग एवं रसद में कटौती करने के सम्बन्ध में आये हैं। हमने बजट में कुछ राशि सब्सिडी और लोन के रूप में रखी है। हमने खादी उद्योग को उन्नति की दृष्टि से, धन–राशि की व्यवस्था की है। हम उनको सब्सिडी दे दें, सहायता दे दें। उस खादी बोर्ड में किस प्रकार का वाद–विवाद हुआ और राजस्थान खादी बोर्ड पर लगाये गये चार्ज के बाद कोई दलील इस बात को देने की आवश्यकता नहीं है कि खादी बोर्ड को धन–राशि नही दी जावे क्योंकि वे आरोप स्वयं इस बात को सिद्ध करने के लिये प्रमाणित थे ; जिसके सम्बन्ध में शब्दों द्वारा व तथ्यों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं कि आज राजस्थान के खादी बोर्ड में किस प्रकार का घोटाला, गबन, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। मैं समझता हूँ कि बजट में इस सम्बन्ध में नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य और मैंने जो कुछ मसाले सदन में प्रस्तुत किये वे पर्याप्त थे कि खादी बोर्ड को देने वाली सहायता तुरन्त बन्द कर दी जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैंने कल–जिस समय उत्तर दिया जा रहा था तब इनके बारे में कुछ बातें सुनी और हमारे राज्य के मुख्य मंत्री का उच्च स्तरीय भाषण सुना और उन्होंने राज्य के खादी मंत्री, जो हमारे फाइनेन्स मंत्री भी हैं, उन पर जो आरोप लगाये गये उनके बारे में कहा कि १४००) रुपये की छोटी बात कही, खादी की बात कही है वह वित्त मंत्री के स्तर के नीचे की बात है। उन्होंने जो यह १४००) रुपये की ग्रान्ट एग्जेम्प्ट की है, मैं अब उनके लिए १४००) की बात नहीं कहता, इसके लिए तो उनको छूट दे दी गई है। उसके ऊपर की बात कर रहा हूँ।

आज से पहले हम इस प्रकार की छूट बार रेट में और रेवेन्यू में सुनते आ रहे थे लेकिन कल १५ मार्च, १९६१ का समय हमारे लिये एक महत्वपूर्ण दिन होगा और हमारे इतिहास के उन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जावेगा कि इस रोज राज्य के मुख्य मंत्री ने यह कहा कि वित्त मंत्री के लिये १४००) तक की छूट दे दी है। उन्होंने यह जो १४००) की छूट उनको दे दी है उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। १४००) रु० तक के घोटाले के मामलों को मैं छोड़ता हूं। उनको इन्कमटैक्स में तीन हजार की छूट है, सेल्स टैक्स में दूसरी है और हिसाब में १५००) की छूट है।

राव राजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : १४००) की छूट है यह एक समय के लिये है या हर साल के लिये है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अच्छा हो कि खादी मंत्रीजी यहां आ जावें।

एक माननीय सदस्य : खादी मंत्री जी कौन हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं सम्मानपूर्वक कह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि हर चीज़ के लिये सम्मानपूर्वक बोल रहा हूँ।

विशेषकर उन परिस्थितियों में जब कि उनकी कुर्बानियों को राजस्थान के हर आदमी से ऊपर रख दी गई हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी कुर्बानियों के सामने मुख्य मंत्री की कुर्बानियां भी कोई वकत नहीं रखती हैं। उन्होंने हर चीज़ कुरबान कर दी। आप सबसे पहले खादी बोर्ड के चेयरमैन बने। इसके बाद इन्डस्ट्रियल बोर्ड के जो मिनिस्टर नहीं, वे चेयरमैन नहीं हो सकते, मगर वे चेयरमैन बने। उन्होंने कानून की कुर्बानी की, उसके बाद कानून की तहत जो रूल्स बनने चाहिये उनकी कुर्बानी की। रूल्स चेन्ज हो सकते थे। जो आदमी जिस कमेटी का चेयरमैन हो अगर वह लोन ले तो वह चेयरमैन नहीं रह सकता। वे खादी का लोन लेते हैं। फाइनेन्स में वे ही बैठे हैं, एन्टी करप्शन में भी वे ही बैठे हैं। चारों ओर जिधर देखो आप ही आप नजर आते हैं और जिस प्रकार ब्रह्मा के चार मुख हैं उसी प्रकार आप ब्रह्मस्वरूप की तरह से सर्वव्यापक हैं और सब जगह विराजमान हैं। लोन लेना हैं तो वे दें और लोन देना है तो वे दें। मैं समझता हूँ कि हर प्रकार को कुर्बानी की है। जहां तक खादी बोर्ड का ताल्लुक है, खादी बोर्ड को दें और खादी के वे कर्णधार हैं। मगर आज खादी पहिन कर पान की दुकान पर लोगों में खड़ा होने पर लोगों में यह भावना पैदा होती है कि खादी में पाप छुपा है। खादी पहिनने में लोगों को शर्म आती है। जब अभी कोई खादी पहने मिलता है तो लोग उसको पूछते हैं कि इसमें कौन सी मील का सूत छुपा है, क्या इसमें किशनगढ़ मील का सूत छुपा है; ये बातें होती हैं। वर्ष बीते, आपने इसमें काम किया है। हो सकता है कि आपने खादी का काफी कार्य किया हो, आप उन पर इस प्रकार के आक्षेप लगाते हैं! नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य को मालूम नहीं कि उन्होंने खादी की बहुत सेवा की है! हम जो यहां पर उनके खिलाफ कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं। खादी के प्रोत्साहन के लिये सरकार की तरफ से मदद मिली थी। खादी का काम उनको दिया गया कि वे खादी का काम करें। जब यह काम आपको दिया गया तो शिकायत हुई और शिकायत कोई विरोधी दल के सदस्य ने नहीं की: उन्ही लोगों ने की उनके त्याग और निम्न स्तर की बातें कहते हैं वे कोई निम्नस्तर के व्यक्ति नहीं थे। इस पर महात्मा गांधी के नज़दीक रहनेवाले लीला साहब आये और सारे कोन्टेन्ट की जांच करके गये और और कार्य करनेवालों को पीतल का सर्टिफिकेट दिया कि खादी में किशनगढ़ मिल का सूत मिलता है। यह सर्टिफिकेट उनको मिला उसके बाद यह संस्था बन्द कर दी गई। उसका लाइसेन्स केन्सिल कर दिया गया। लीला साहब ने बताया कि खादी में मिल का सूत मिला है। इस संस्था में ऐसे व्यक्ति हैं, इनका लाइसेन्स बन्द कर दिया जावे। लेकिन फिर सेवा के दो साल के बाद जब उनके पास यह पोर्टफोलियो आया तो फिर से उनको

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लाइसेन्स दे दिया जाय। फिर से उसको लाइसेन्स दे दिया गया। फिर उस संस्था का कार्य प्रारम्भ हुआ और वे आज कितनी खादी की सेवा कर रहे हैं ! खादी की सेवा ! खादी जैसी पवित्र चीज़ की सेवा ! मेरे लिये तो यह एक कोई मजाक हो सकता है क्योंकि मैं खादी नहीं पहिनता। लेकिन उधर बैठने वाले सदन के माननीय सदस्यों के लिए खादी एक विशेष बात है, पवित्र चीज़ है, उन्होंने इस बात के लिए फॉर्म भरा है कि खादी हमारी रीढ़ है, खादी हमारे लिए एक सूत्र है, इसका प्रत्येक धागा हमारे लिए पवित्र है। वे विचार करें, सोचें, मौन धारण कर बैठने से काम नहीं चलेगा। उस खादी का आज क्या हाल है, उसकी पवित्रता कहां गई, उस खादी में घोटाला हो रहा है, खादी के धागे-धागे में अपवित्रता आ गई है। कहते यह हैं कि खादी में काम करने वाले मजदूरों को, कातने वालों को हम पैसा देंगे, सब्सिडी देंगे और अध्यक्ष महोदय, होता क्या है कि बुनकरों को पैसा मिलता नहीं कातने वालों को पैसा मिलता नहीं। खादी का राज्य ऐसा विचित्र राज्य है कि राजस्थान का हजारों, लाखों और करोड़ों रुपया दिया जाता है वह बेकार जाता है। मौसम आती हैं तो खादी की बिक्री होती है, रिबेट मिलता है, इसलिए लोग इन्तजार करते हैं कि कब मौसम आवेगा और वे चार आना, छः आना रिबेट के लेकर खादी खरीदेंगे। जो खादी की प्रतिष्ठा थी, उसके प्रति जो भावना थी वह आज भावना ऐसी हरकतों से नहीं रही। आज वह भावना नहीं है। मैं आपकी तरफ से वकालात करता हूँ। आप कहां मुंह दिखायेंगे जाकर, लोग क्या कहेंगे कि खादी मंत्री ऐसे हैं कि मिल का सूत मिलवाते हैं। खुद खादी मंत्री जी उस खादी बोर्ड के चेयरमैन हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो तथ्य सदन के सामने रखना चाहूँगा और जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि १४००) रु० से नीचे की बातें नहीं रखूंगा और उनसे जो ऊपर के तथ्य हैं वे ही निवेदन करूंगा।

यहां पर खादी बोर्ड के तहत लकड़ी की खरीद का सवाल खड़ा हुआ। खादी बोर्ड के अन्तर्गत सरंजाम कार्यालय बना हुआ है, वह भी खादी बोर्ड का एक भाग है। सरंजाम कार्यालय ने कहा कि ७) रु०, १४) रु० क्युबिक फीट तक के हिसाब से लकड़ी देंगे। खादी बोर्ड ने कहा कि हमारे महकमे के मातहत हो, ७), १४) के हिसाब से नहीं लेते। उस भाव से वे लकड़ी नहीं ले सके। लेकिन नासिक से २१) क्युबिक फीट के हिसाब से खादी बोर्ड ने लकड़ी खरीदी। इसमें खादी बोर्ड ने ७ हजार रुपयों का घोटाला किया। माननीय वित्त मंत्रीजी खादी बोर्ड के चेयरमैन हैं जिनके मातहत ये सारी बातें हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या लकड़ी की खरीद में ७ हजार का नुकसान नहीं हुआ ? क्या कहना है उनको इस सम्बन्ध में ? उनके प्रति यह एक चार्ज सम्हाले रखता हूँ, वे जवाब दें।

लोहे के बारे में भी, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बातें हुई। एक और पर्चेज़ की बात थी। खादी बोर्ड को लोहे के कड़ाह खरीदना था। खांडसारी खांड वगैरहा के लिए, उस दृष्टि से पर्चेज करने के लिए ८३) रु० का हाइयेस्ट टेन्डर हो सकता था, वह उन्होंने उस भाव से खरीदा। सरंजाम कार्यालय से ही

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राजस्थान सरकार भी खरीदती है और टेन्डर व कोटेशन्स मांगना उचित नहीं समझती है। इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट ने सर्कुलर निकाला है कि बिना टेन्डर के सरंजाम कार्यालय से खरीद लिया जाय। राजस्थान सरकार यह व्यवहार करती है कि बिना टेन्डर के ही माल ले लिया जाय सरंजाम कार्यालय से, लेकिन खादी बोर्ड का कार्यालय सरंजाम कार्यालय से पर्चेज नहीं करता है और दूसरों से ७० हजार के कड़ाह खरीद करता है और जिसमें १५-२० हजार का खादी बोर्ड को नुक्सान होता है। यह चीज़ साफ है और ये पर्चेजज हुई उन रेट्स पर और उन परिस्थितियों में हुई हैं।

लोन्स के बारे में एक बात देखी गई है, खादी बोर्ड को पैसा देते हैं। सारा खादी का चक्कर ही, अध्यक्ष महोदय, विचित्र ढंग का है। क्या राज है, यह समझ में नहीं आता। लेने वाले, देने वाले, खाने वाले और खिलाने वाले, नियंत्रण रखने वाले और मंजूरी देने वाले ये मानों सारे मिलकर बड़ा परिवार हैं। उसमें सब कुछ चलता है। हिसाब नहीं है। लोन मंजूर करने वाले और लेने-देने वाले कौन हैं? लोन कमेटी खादी बोर्ड की है। लोन अजमेर ग्राम सेवा-मंडल के लिए मंजूर करते है, अजमेर ग्राम सेवा-मंडल की एप्लीकेशन लोन कमेटी के सामने आती है। बोर्ड के चेयरमैन हैं श्री हरिभाऊजी उपाध्यक्ष, और लोन कमेटी के और बोर्ड के सेक्रेट्री श्री चिरंजीलाल। अन्दाज़ लगाइये! जिस बोर्ड के स्वयं वित्त मंत्री चेयरमैन हो, जिस संस्था के कर्त्ता धर्त्ता हरिभाऊजी उपाध्याय, चेयरमैन और उस बोर्ड के सेक्रेट्री श्री चिरन्जीलाल शर्मा हों, उस बोर्ड की कौन हिमाकत कर सकता है कि लोन मंजूर न करें। लोन मंजूर किया उन्होंने। मैंने कल भी कहा था कि अजमेर ग्राम सेवा-मंडल के लिए ५० हजार रुपया भवन बनाने के लिए श्री हरिभाऊजी उपाध्याय, वित्त मंत्री ने लिया और उसकी रजिस्ट्री बालकृष्णजी गर्ग के नाम से हो रही है। वित्त मंत्री महोदय ने उसका जवाब नहीं दिया। आरोप जितने भी सदन में लगाये गये, वित्त मन्त्रीजी ने उनका जवाब नहीं दिया, वे तो ऊपर उठे हुये हैं? परमहंस की स्थिति आ गई। कोई कितना ही आरोप लगाये, कोई कितनी ही बातें कहे, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूँगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अपने उच्चस्तरीय भाषण में उनके बारे में जो उन्होंने कुर्बानियां की हैं उनका जिक्र किया है, उनके भाषण का वह पोर्शन, राजस्थान का इतिहास लिखने के लिये जो एडिटोरियल बोर्ड और एडवाइज़री बोर्ड बनाया गया है उसमें भेज देना चाहिये ताकि जब राजस्थान की संस्कृति का इतिहास लिखा जाय तो श्री हरिभाऊजी उपाध्याय ने जो कुर्बानियां की हैं, राजस्थान की संस्कृति के इतिहास के उस अध्याय में उस भाषण को जोड़ दिया जाय एक अध्याय के रूप में और मैं कहता हूँ कि उनके भाषण को उस अध्याय में जोड़ दिया जाय और जो आरोप सदन में लगाये गये हैं उन सबको उस अध्याय के आगे एक उप-अध्याय के रूप में जोड़ दिया जाय, जिसको राजस्थान की आने वाली संतति देखेगी कि यह उस भाषण का अध्याय है और यह आरोपों का उप-अध्याय है, उपाध्याय था; है। अध्याय ऐसा था और उप-अध्याय क्या यह राजस्थान की आने वाली संतति देख

Page No.38

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सकेगी कि राजस्थान में क्या क्या कुर्बानियां की गई हैं। उस अध्याय में उनको पढ़ने को मिलेगा मुख्य मन्त्री का उच्चस्तरीय भाषण और उप-अध्याय में उनको पढ़ने को मिलेगा कि ये ये कुर्बानियां,........

(विराम)

उनकी कुर्बानियों को लिख दीजिये। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं और माननीय सदस्यों की जो राय है उसको भी उस छोटे से अध्याय के साथ उप-अध्याय के रूप में जोड़ दीजिये जिससे राजस्थान की संतति अध्याय और उसके साथ लगे उप-अध्याय को पढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि आरोपों का कोई उत्तर नहीं है। आरोपों के नाम पर ऐसा उसको पी जाते हैं कि जैसे ब्लॉटिंग पेपर स्याही को पी जाता है। चुप बैठे हैं। प्रगतिशीलता का सवाल खड़ा करते हैं, राजस्थान का यह प्रगतिशील बजट है। राजस्थान में यदि कोई विकास के काम हुये हैं तो वे सारे हमने किये हैं। पैदावार घट गई और यदि बढ़ गई तो हमने पैदावार बढ़ाई है और अकाल आ गया तो हम क्या करें, यह तो प्रकृति का प्रकोप है। ये सारी बातें, अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी यहां कही गई हैं, मेरी निश्चित मान्यता है कि जहां तक खादी बोर्ड का सवाल है उसको एक पैसा न दिया जाय और चेयरमैन के रूप में रहने के लिए कानून में इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर के लिये लिखा है। कानून वे जानते नहीं। मैं वित्त मन्त्रीजी से कहूँगा कि क्या इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर हैं आप? आपका क्या जवाब है इसके लिए? इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर इसके चेयरमैन नहीं हैं, हालांकि इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो भी आपके पास नहीं है। इन्डस्ट्री का पोर्टफोलियो किसी दूसरे मिनिस्टर का है। आपने इसको लेने की चेष्टा की। प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, छोड़ें कैसे? इसलिए इसका बाइफकेशन करवाया। माइन्स, मिनरल्स अलग, इन्डस्ट्रीज़ अलग और विलेज इन्डस्ट्रीज़ का तुगमा खड़ा करके आप हो गये।

मैं समझता हूं, पिछले १२ सालों से राजस्थान में खादी का प्रोडक्शन बढ़ा होता तो वित्त मंत्री महोदय, राजस्थान की जो दो करोड़ जनता है उसमें से काफी लोगों के सिर पर ढाई आने के ढक्कन नजर आते, लेकिन खादी का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है। गांव गांव में खादी का प्रचार हो गया होता आज जो लोग खादी के हामी बनते हैं और कहते हैं खादी हम पहनते हैं उनका कोट उतरवा कर देखिये, आपको रेशमी बनियान नजर आयेंगे। खादी के नाम पर जो एक प्रकार से भ्रष्टाचार पनप रहा है और जिस बारे में इस सदन में जो बातें आयी हैं उन पर आप गम्भीरता से विचार करेंगे। जहां तक खादी बोर्ड को पैसा देने का सवाल है आप खादी बोर्ड को पैसा न दीजिये और जो संस्था के कार्य कर्ता हैं जिनके खिलाफ चार्जेज़ हैं उनका प्रोसीक्यूशन किया जाकर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव सदन के सम्मुख उपस्थित करता हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २२ मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय के सम्बन्ध में मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं उनको तो पेश करता हूँ कुछ और जो कटौती के प्रस्ताव हैं उन पर मैं अपने विचार भी रखूंगा। सबसे पहले राजस्थान के उद्योग विभाग की तरफ से प्रोडक्शन-कम-ट्रेनिंग

(डॉ० बहादुरसिंह)

सेन्टर्स हैं उनके बारे में इतना निवेदन करना चाहूँगा, ये जो थोड़े इस प्रकार के प्रोडक्शन कम-ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं उनके बारे में अक्सर इस प्रकार की शिकायत सुन लिया करते हैं कि वहां जो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त हैं उनकी पूरी योग्यता नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा न कह कर इतना ही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में यदि वास्तविक रूप से औद्योगिक प्रगति लानी है तो हमें मैकेनाइज्ड ट्रेनिंग सेन्टर्स शुरू करने चाहिये जिससे हम यहां पर अधिक से अधिक मैकेनिक्स तैयार कर सकें। बढ़ईगिरी, लोहारी आदि कामों में एक्सपर्ट लोग तो मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य चीज़ जो है, मैकेनिक्स, उनकी बड़ी आवश्यकता पड़ती है। मैं आपके सामने धौलपुर ग्लास वर्कस के लिए निवेदन करूं, ट्रेन्ड लेबरर्स हैं उनकी वहां बहुत आवश्यकता रहती है जो बाहर से मिलते हैं आज राजस्थान के अन्दर प्रोडक्टिव सेन्टर्स हैं उनके बारे में अक्सर यह देखने को मिलता हैं कि या तो लोकल विद्यार्थियों को सहायता मिला करती है या कुछ लोग जो ट्रेनीज़ हैं उनको सहायता मिला करती है, इस प्रकार से थोड़ा सा इस विषय पर निवेदन करने के बाद दूसरे सब्जेक्ट पर आ जाऊंगा; इन ट्रेनिंग सेन्टर्स की जगह अच्छे स्टेन्डर्ड के मैकेनिक्स हों तो प्रान्त को ज्यादा लाभ मिल सकता है।

दूसरी बात धौलपुर की बात है, धौलपुर में उद्योग बस्ती स्टार्ट करने के लिए कहा गया है; लेकिन इसके बारे में बजट व्यवस्था न होने के कारण कुछ चिन्ता हुई है। आपने इस सदन में कहा था कि अगले वर्ष में वहां उद्योग बस्ती का निर्माण कराया जायगा। मैं समझता हूँ, आप अपने विचारों में दृढ़ होंगे और इसी बजट के साल में कार्य प्रारम्भ कर देंगे।

अब मैं राजस्थान के प्रोडक्शन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां राजस्थान में कपड़ा और ग्लास वर्क्स के प्रोडक्शन के अन्दर गिरावट आयी है। छोटे जो निज के कारखाने हैं, चाहे वे सरकार द्वारा चलाये जाय, वहां के प्रोडक्शन में गिरावट हमारे मजदूरों और लेबरर्स के सामने एक प्रकार का संकट है; इससे बेरोजगारी फैलेगी किन्तु यह ठीक है कि उससे मुनाफा मिलेगा। प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा आयगा उसके अनुसार लेबर मिल सकती है। १९५७ में ग्लास का उत्पादन ६६६ टन था और सन् १९५९ में ८२८ हुआ और ६० में जाकर ६७२ टन रह गया है। इस प्रकार से १५६ टन का जो फर्क आ गया है वह कोई छोटी बात नहीं, लाखों रुपये जो लेबरर्स को मिलने वाले थे उसमें भी कमी आती है।

इसी तरह से कपड़े के उत्पादन को ही ले लीजिये। सन् ५४ से इसमें गिरावट आयी है। राजस्थान में कितनी ही मिलें हैं, उनमें से कुछ तो मिल मालिकों के हाथ में है और कुछ का प्रबन्ध सरकार ने भी अपने हाथ में लिया है। इस ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे उद्योग विभाग का इसके प्रोडक्शन की तरफ जरूर ध्यान दिया जाना चाहिये। जो लोग निजी तौर पर कारखाने चलाते हैं उनकी कठिनाइयों के बारे में भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है; आया

Page No.40

(डॉ० बहादुरसिंह)

हमारे राज्य के अन्दर जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उन फैक्टरियों में उत्पादन की गिरावट का कारण क्या है, इस बारे में इस विभाग को सोचना चाहिये । हमारे यहां सीमेन्ट का अभाव है, लेकिन हमारे यहां जो सीमेन्ट फैक्ट्री है उसके लिये कहा जाता है कि एशिया में यहां सबसे अच्छी और सबसे बड़ी फैक्ट्री है । इन सब बातों के होते हुए भी यहां के लोगों को सीमेंट मिलता नहीं है । इन सब बातों की ओर विशेष ध्यान देने की बात है । हमारे यहां के प्रोडक्शन में क्यों गिरावट आयी है, इसका क्या कारण है, यह हमारे इस विभाग को देखना चाहिये ! जब तक हम यहां उद्योग-धन्धों की ओर ध्यान नहीं देते हैं उनको नहीं बढ़ाते हैं, तो राजस्थान के अन्दर जो बेकारी की वृद्धि हुई है उसको देखते हुए हमें चाहिये कि हमारे यहां जो उद्योग-धन्धे हैं उनके प्रोडक्शन में गिरावट क्यों आ रही है, इसका क्या कारण है ?

शक्कर के बारे में ५७ और ६० में बड़ा फर्क है । बीच में रेट गिरी, बाद में बढ़ोतरी हुई । मैं समझता हूँ, हमारे इधर पार्वती बांध का उद्घाटन हो रहा है । इससे धौलपुर में शुगर फैक्ट्री और स्टार्ट की जा सकती है ।

धौलपुर के एक और मिल के बारे में जिक्र करूंगा । मैच फैक्ट्री है । इसके लिये हम या तो उस व्यक्ति को फोर्स करें कि वह स्वयं स्टार्ट करे या फिर दूसरे व्यक्ति को दे । मैं उम्मीद करता हूँ, आप इस बारे में भी विचार करेंगे और जिसको जो वाजिब सहायता करनी हो तो वह भी आप करेंगे ।

इसी तरह से उदयभान इन्डस्ट्री है । इसको जब नीलाम करने जा रहे हैं तो उसकी बिल्डिंग के बारे में भी तय करें कि उसका क्या हो ? इसी तरह पोटरीज़ की इन्डस्ट्री है । इसमें हमारा कैपिटल शेयर लगा है और बहुत सी विघटित फैक्टरियां हैं, उनके बारे में तय करें कि आया उनको चलाया जाय या समाप्त कर दिया जाय । ज्यादा दिनों तक पड़ी रहने से तो फैक्टरियों की मशीनें और अधिक खराब ही होंगी ।

अब विभाग के द्वारा कुछ इस प्रकार परमिट दिये जाते हैं, उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ । इस सदन के अन्दर भी जो आरोप लगाये जाते हैं और जिससे मुख्य मन्त्रीजी को भी दुःख होता है तो उन पर भी आप ध्यान दें । पहले तो मैं भरतपुर के बारे में बताऊं कि पिछली बार इसी सदन में बताया गया था कि २२ लोहे के ऐसे कारखाने हैं जिनका लोहा ब्लैक में पकड़ा गया । हमारे अधिकारी भी हमारे बहुत से फैक्ट्री ओनर्स के साथ भिन्न-भिन्न तरह के बर्ताव करके परेशान करने की कोशिश करते हैं कि या तो वे उनकी इच्छा के अनुसार काम करें, नहीं तो उनका भी इसमें लपेटा जाता है । इससे दो नुकसान होते हैं । एक तो राजस्थान बदनाम होता है और यहां के ईमानदार व्यापारी भी इनके साथ बदनामी की लपेट में आते हैं कि राजस्थान के फैक्ट्री ओनर्स ऐसे हैं जो ब्लैक में बेचते हैं । दूसरा हमारे अधिकारियों में इससे डीमोरेलाइजेशन पैदा होता है । कोई ईमानदारी से काम भी करना चाहे तो नहीं कर सकता । तो हमें अच्छी तरह से सख्ती के साथ इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये ।

(डॉ० बहादुरसिंह)

दुग्ध चूर्ण के बारे में भी यह सत्य है कि राजस्थान के उन व्यापारियों को स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने ब्लैक लिस्ट कर दिया। यह सूचना पुरानी है। एक साल तक झगड़ा चला। मैं यहां किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, पर इतना कहना चाहता हूँ कि हमें किसी व्यक्ति से मोह नहीं होना चाहिये।

अन्त में, मैं जो हमारे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने हमारी खादी के बारे में अनेकों बातें बताईं; मैं उन सब का उत्तर तो देना नहीं चाहता पर एक निवेदन करना चाहता हूँ। खादी के अन्दर घोटाला है। क्या है, क्या नहीं है, सदन के नेता ने इस बारे में काफी उत्तर दे दिया था, पर फिर भी बार बार खादी के प्रश्न को यहां लाना सदन का समय बेकार लेना है। उनको इस भावना की कद्र करनी चाहिये थी कि आज वास्तव में राजस्थान में खादी का उत्पादन बराबर बढ़ रहा है। इसमें दो राय नहीं। स्वयं मेरे क्षेत्र में खादी का काम बढ़ा है। वहां राजस्थान खादी संघ बराबर काम कर रहा है। मुझे निकट से देखने का मौका मिला है। जो लोग काम कर रहे हैं वे एक मिशनरी स्पिरिट से करते हैं क्योंकि खादी एक तो भाव में तेज, दूसरा उसके पहिनने वाले को संकल्प करना पड़ता है। पर स्वास्थ्य की दृष्टि से........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपके यहां कौनसी खादी संस्था काम करती है ?

डॉ० बहादुरसिंह : खादी संघ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके यहां करौली वाली संस्था काम करती है ?

डॉ० बहादुरसिंह : राजस्थान खादी संघ है, करौली वाली नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसके आप मेम्बर हैं क्या ?

डॉ० बहादुरसिंह : नहीं, इससे मेरा सम्बन्ध नहीं है। मैं केवल ग्राहक हूँ। खादी अपनाना तो मैं कह रहा था कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम है। यहां हमारे सन स्ट्रोक से लगने की बीमारी है, यह बीमारी उसको नहीं हो सकती जो खादी पहिनेगा। कारण यह है कि खादी स्वयं गर्मी में पसीना देगी और जिसको पसीना आता रहेगा उसको लू नहीं लगेगी। तो इसलिये मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप खादी के मामले में इतने परेशान न हों। घोटाले का सवाल अलग बात है : इसके लिये राजस्थान में भ्रष्टाचार विरोधी संस्था मौजूद है। तो फिर बार बार एक ही बात का रिपीटीशन क्या ? पहले इसके कि मैं अपना स्थान ग्रहण करूं मैं पुन : निवेदन करूंगा कि सरकार धौलपुर की इन्डस्ट्रियों के बारे में पूरी तरह से विचार करेगी।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उद्योग के बारे में कट मोशन है।

उद्योग सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव रहने के कारण उद्योग ठीक तरह से तरक्की नहीं कर रहे हैं।

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उद्योग विभाग का काम है कि हमारे क्षेत्र में छोटे और बड़े उद्योग तरक्की करें।

सब लोगों की इस समय यह भावना बढ़ रही है कि सारे राजस्थान वासी खेती करें। पर न तो हमारे पास इतनी जमीन है जो सब को दे सकें और आबादी जो तेजी से बढ़ रही है उसको हम खेती पर नहीं लगा सकते हैं। इसलिये हमारे विकास के लिये खेती के साथ साथ हमें उद्योग भी चलाने पड़ेंगे। आज उद्योग तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके कारण हैं। इसका एक कारण तो यह है कि सही लोगों को ऋण नहीं दिया जाता; ऐसे लोगों को मिल जाता है जिनका देने वालों के साथ किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध रहता है। उद्योग के नाम पर पैसा ले लेते हैं और उसमें न लगा कर और कामों में लगा देते हैं। अब इधर विभाग के लोग जांच करने जाते हैं तो कहीं न कहीं लेने वाले के सम्बन्धी या मित्र दोस्त होने के कारण वह मामला दबा दिया जाता है और इस तरह से वह लोन गलत जगह खर्च हो जाता है।

हमारे कोटा में जिस नाम का कोई प्रेस नहीं था उसे लोन मिल गया। इसी तरह कई फैक्टरियां हैं जो मशीन के नाम पर लोन ले लेती हैं, पर मशीनें पूरी नहीं मंगातीं और हाउस में जवाब यह मिल जाता है कि आ गई। मैं तो समझता नहीं, पर जानने वालों ने कहा।

अध्यक्ष महोदय, इस कारण आज गांवों के छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे भी नष्ट हो गये हैं, गांवों में बेकारी बढ़ती जा रही है। लोग गांवों में बांस की छोटी छोटी टोकरियां बनाकर अपनी आजीविका चला रहे थे, पर आज बांस मिलता नहीं और वे बेरोजी होकर मारे मारे फिरते हैं।

बढ़ईगिरी का काम था। लोग मोटा फर्नीचर बना कर अपना काम चलाते थे, पर आज उनको भी लकड़ी नहीं मिलती, न ट्रेनिंग ही। गत साल मैंने एक इस प्रकार का सुझाव भी दिया था कि अकलेरा, मनोहरथाना में बढ़ईगिरी की स्कूल खुलनी चाहिये। सरकार ने मांग भी मंजूर की, पर स्कूल खोला पाटन में मनोहर थाना के नाम पर। पर वहां लड़के भी ज्यादा आये नहीं, लकड़ी मिलती नहीं और स्कूल ठप्प हो गई। जहां लकड़ी नहीं मिलती, वहां शहर की चार दिवारी में वहां स्कूल खोलते हैं तो लगता है उल्टी गंगा बहती नजर आती है।

कृषि उत्पादन की ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको तो उनके द्वारा जो कृषि का काम नहीं जानते और यह भी दी जाती है अंग्रेजी में। हिन्दी तो बोल नहीं सकते और अंग्रेजी में जाकर कृषि उत्पादन का विषय सिखावें ! तो लड़के समझते नहीं हैं और उनके आगे बड़े बड़े ऑफिसर होने के नाते वे कह देते हैं कि हां, समझ में आ गया, लेकिन समझ में कुछ आता नहीं है। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि लोहा और चद्दर जो कि कृषि उद्योग में काम आने की चीज है वह आज गरीबों को नहीं मिलता है। वह शहरों में से कलेक्टर ऑफिस है या जहां से तकसीम होता है वहां से बड़े बड़े आदमी ले लेते हैं, अपने मकानों पर छप्पर डालने के लिए।

Page No.43

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

इसके अलावा जो लाइसेन्स लेते हैं वे इधर-उधर बाहर बेच देते हैं। कई पकड़े भी जाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब आ जाता है कि नहीं पकड़े गये और चद्दरें इधर-उधर फर्जी नाम से चली जाती हैं।

इसी तरह से हमारे यहां खानपुर का इलाका है। वहां शुगर फैक्टरी के लिए लोगों ने काफी शेयर खरीदे और केवल दो-तीन हजार की कमी रह गई है। दुर्भाग्य की बात है कि अभी रेवड़ की पंचायत समिति आई तो उसने प्रस्ताव पास कर लिया कि शुगर की फैक्टरी नहीं लगाई जाये और उसका पैसा वापिस लौटा दिया गया। अगर पहली पंचायत समिति कोई योजना बना कर रखती है और उसके बाद में दूसरी आती है और वह उस योजना को खत्म कर देती है तो इस तरह से हमारे उद्योग नहीं पनपेंगे। मैं कहता हूँ कि शुगर फैक्टरी जिसके लिए कोशिश कर करके और घूम घूमकर एक सोसाइटी बनाई और सौ-सौ रुपया उसके लिए इकट्ठा किया और दो-तीन हजार की कमी रहती है उसको भी पूरा करवा दें, लेकिन इस प्रकार से एक पंचायत समिति के कहने पर इस तरह से योजना को फेल नहीं होने दें....

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि पंचायत समिति के रिज़ोल्युशन पास करने से कुछ नहीं होगा। आपकी जो योजना होगी उसमें जो कुछ मदद सरकार की होगी वह जरूर की जायेगी।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इसके लिए धन्यवाद है। यदि शुगर फैक्ट्रीज़ वहां पर चालू कर दी जायें तो बहुत अच्छा हो। वहां पर दो दो नहरें हैं। यह तो वहां का दुर्भाग्य है कि वहां पर कई वर्षों से बांध टूट जाते हैं और जवाब दे दिया जाता है कि जांच करवा रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि इस प्रकार से अगर वहां पर फैक्ट्री चालू करवा दी जाये तो बेकारी दूर हो जायेगी। मैंने पहले बजट के टाइम पर भी कहा था कि आप टैक्स लगा दें, हम टैक्सों से घबराते नहीं हैं। हमारे देश का बच्चा बच्चा योजना के लिए खून देने के लिए भी तैयार है, तो टैक्स से तो घबरायेंगे नहीं। लेकिन टैक्सों से लिया गया पैसा हमारी योजनाओं में सही तरीके से खर्च किया जाये तो मैं समझता हूँ कि टैक्स का विरोध करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन हमें इसकी आलोचना इसीलिए करनी होती है कि पैसा ठीक तरह से खर्च नहीं किया जाता। लोग वोट देकर निराशा प्रकट करते हैं। यहां पर सुनवाई नहीं होती तो वहां हमारे लिए जवाब देना मुसीबत हो जाती है। हम घबरा जाते हैं। आत्मा तो कुछ कहना चाहती है लेकिन दबाव के कारण कुछ और ही कहना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे किसी को वोट मिलें या नहीं मिलें, लेकिन जो जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं उनको तो यहां हाउस में सही बात कहनी ही चाहिए। सही बात कहने में पार्टी भी दबाव नहीं दे सकती। सच्ची बात तो यह है कि 'समरथ को नहीं दोष गुसाईं'। बड़े बड़े आदमी सब कुछ कर लें! अध्यक्ष महोदय, उद्योग के नाम पर न जाने क्या क्या घोटाले हो रहे हैं? आत्मा तो सभी

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

कुछ कहना चाहती है, लेकिन जब सभी दब गये तो मैं क्या बताऊं ?

अब मैं आपको खादी उद्योग के बारे में बताऊं । केथून और मांगरोल में खादी इतनी चलती थी कि विलायत तक प्रसिद्ध थी । वहां पर उद्योग चलाते तो अच्छा होता । मैं समझता हूँ कि ऐसे आदमी उसमें बैठ गये कि वे गौ-सेवा संघ में बैठे थे, भारत सेवक समाज में भी बैठे थे, समितियों में भी बैठे थे और सरकार में भी बैठे थे । अब आप ही बताएं कि एक एक आदमी के पास पांच-पांच पद मिल जायें तो क्या हाल होगा ? इसीलिए खड़ोदी के संघ में घोटाला निकला । न तो वहां पर कोई कहता है कि सूत ले लो, बुनाई दे दो । लेकिन वहां पर सूत और बुनाई तक की व्यवस्था नहीं है । हमारे यहां पर कताई की कला बहुत ऊंची थी वह नष्ट हो गई । मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारे गांव का उद्योग पनपे और सही तरीके से इन योजनाओं को चलायें । आलोचना मैंने की है तो उस पर नाराज न हों और अगर नाराज होते हैं तो आपका टिकट रखो ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं ६ कटौती के प्रस्ताव एक साथर रख रहा हूँ । राज्य का पहले काम यह था कि रक्षा करना और किसी भी जुर्म करने-वालों को पकड़ना और अपना लगान वसूल करना । लेकिन जब जनता का राज्य आया तो राज्य का एक काम और हो गया और वह यह कि लोगों को भर पेट रोटी दी जाये, उनको कपड़ा दिया जाये और उनको स्कूल दिये जायें जिनमें वे पढ़ सकें । तो यह जिम्मेदारी जब सरकार ने ले ली तो हिन्दुस्तान में इस जिम्मेदारी को लेने के बाद प्लानिंग कमीशन ने यह सोचा कि हमें क्या करना चाहिए । तो राजस्थान के अन्दर जो इन्डस्ट्रियल पॉलिसी थी उसके अन्दर यह विचार किया कि पहला काम तो यह है कि राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा प्रगतिशील काम कोई है तो वह है कृषि । हमें कृषि के आधार पर ही निर्भर होना है । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के किसान अपनी जमीन पर एक फसल के अलावा दूसरी फसल नहीं बो सकते और यही कारण है कि आज गांवों में बेकारी देखने को मिलती है ।

सवाल यह है कि बेकार उसको कहते हैं जो कि भर-पेट रोटी और कपड़ा पैदा नहीं कर सकते और बहुत कम समय में काम करते हैं । राजस्थान के अन्दर बहुत से लोग जो काश्तकार हैं वे पानी के ऊपर निर्भर रहते हैं और एक फसल करते हैं, अन्यथा बेकार हो जाते हैं । हम यह समझते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार से उद्योगों का विकास करें । मैंने जब बजट देखा तो उसके अन्दर जो आपने बजट एस्टीमेट्स रखे हैं ५.४ लाख ६३ हजार के रखे हैं । यह जो रुपया आपने रखा है वह रखा है कि राजस्थान में हम

(श्री मूलचन्द डागा)

विकास के अन्दर इस साल १९६१–६२ में इतना व्यय करेंगे ।

अब आप उसके एस्टेब्लिशमेन्ट का खर्चा देखिये । आप ताज्जुब करेंगे कि २० पर्सेन्ट खर्चा इस पर होता है । सारा का सारा खर्चा एस्टेब्लिशमेन्ट पर जाता है और उसका क्या खर्चा है, डाइरेक्शन का खर्चा है, सुपरिन्टेन्डेन्स का खर्चा है । यह नोन प्लान एक्सपेन्डिचर है जिससे कोई उत्पादन नहीं हो सकता । इसमें उन्होंने बताया है, थोड़े से आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ । हम किस प्रकार से चलते हैं, इसमें हमारा दोष नहीं है । कुछ न कुछ बात कहते रहना जनतंत्र और लोकतंत्र की प्रणाली है, उसका दोष है । हम बराबर कह चुके हैं कि इतने लोग नौकरी में हैं, राजस्थान में उद्योग का इतना विकास किया है । क्या किया है, यह अलग बात है । हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि राजस्थान ने उद्योग में प्रगति की है, उद्योग की नींव मजबूत की है । कुछ ऐसा विश्वास हो गया है कि राजस्थान उद्योग में तरक्की करेगा । लोकतंत्र चलाने वाली सरकार में कुछ खूबी चाहिये और वह खूबी यह हो कि वह लोगों के सामने लंबी–चौड़ी योजना दे और यह बतावे कि हम ऐसा करना चाहते हैं और थोड़े दिन के बाद यह उत्तर दे दो कि हम योजना को इसलिये फलीभूत नहीं कर सके कि इसमें ये बाधाएं आ गई । एक बार चर्चिल ने यह बात कही थी कि लोकतंत्र में लोगों को योजना देनी चाहिये ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : कब कहा था ?

श्री मूलचन्द डागा : तारीख मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो बाद में बता दूंगा । उन्होंने कहा था कि हम बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते रहें तब लोग यह समझेंगे कि यह बिल्कुल ठीक तरह से काम हो रहा है । थोड़े दिनों के बाद यह उत्तर दे दो कि थोड़े कारणों से योजना में असफल हुए । उसके बाद यह कह दो कि असफल होने पर योजना को चलाने के लिये तैयार हैं, ताकि लोकतंत्र का कार्य चलता रहे । यह लोकतंत्र की प्रणाली है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : चर्चिल ने तो नहीं कहा, आपने कहा है ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूँ कि किसी चीज़ को कहने पर आप मान लेते हैं । किसी चीज़ को कहने की मनाही नहीं है । राजस्थान की औद्योगीकरण की नीति पर यह लागू होता है । उद्योग मन्त्री इतने सुन्दर ढंग से पेश करेंगे और सेक्रेटरी और डाइरेक्टर खुश होंगे कि हमने कमाल किया, इतने साफ तरीके से बजट पेश किया । लेकिन कौन पढ़ता है बजट के इतने लंबे पोथे को ? लेकिन यदि कोई बार बार इसे पढे तो दो बातें पहले पहल उसको नजर आयेंगी ।

डाइरेक्टोरेट का जो खर्चा बताया है उसमें बताया है कि १,६६,२०० रुपये केवल तनख्वाहों पर खर्च होंगे, उसके बाद दिया है सर्विस पोस्टेज, टेलीग्राम्स, टेलीफोन्स, लाइट एण्ड वाटर चार्जेज, लिवरीज, बुक्स वगैरह पर ४,२५,५०० रुपये केवल नोन प्लान एक्सपेन्डिचर है, इतना इस पर खर्चा पड़ता है । आपने कहा, बजट बड़ा टाटदार है ।

(श्री मूलचन्द डागा)

इन्क्वायरी ऑफिसर है, कागज़ निकलते हैं, पब्लिसिटी होती है, राजस्थान उसका स्वागत करता है। अब स्वागत हुआ या नहीं, दो सवाल चलते हैं। एक तो चलती है मशीनरी और दूसरे चलते हैं मिनिस्टर जो चुनिन्दा आते हैं। आपने एलान किया कि आपका स्वागत करते हैं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मिनिस्टर की तरह मत बोलें, जो होता है वह कहें।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने चार बातें रखी थीं। उन चार बातों पर मैं बोलना चाहता हूँ। मिनिस्टर्स के कहने का मतलब यह है कि क्या वहां प्रगति हो रही है? मिनिस्टर कहते हैं कि हमने यह उसूल बनाया है, सिद्धान्त बनाया है और उसको लागू करना चाहते हैं। लेकिन जो मशीनरी लागू करती है, अमल में लाती है वह इसके लिये बड़ी शान्त है। वह समझती है कि बात क्या है। इतने काम के बारे में कहा गया है, हमने कैसी तरक्की की है, यह कौन देखता है। प्रगति करें या न करें, इसकी किसको चिन्ता है।

हिन्दुस्तान में और खास करके राजस्थान में हम बुनकरों की समस्या हल करना चाहते हैं। मैंने खुद दो-तीन जगह जाकर देखा कि जो कपड़ा बुनकर बुनते हैं उसको वे खुद अपने काम में नहीं लाते हैं। उनको पूछिये कि तुम कौनसा कपड़ा काम में लाते हो तो वे कहेंगे कि मिल का कपड़ा काम में लाते हैं जो सस्ता पड़ता है और टिकाऊ है। जब उनको कहते हैं कि तुम बुनकर हो, अपना कपड़ा खुद बुनते हो तो तुम उसे खुद भी काम में नहीं लाते तो बेचते किसको हो? वे कहेंगे कि यहां दूकान लगा लेते हैं, सोसाइटी बना रखी है उसके सहारे रुपये जमा कर लेते हैं उससे काम चलाते हैं। उनके पास ही एक बनिया भी बैठा है जो चाहता है कि बुनकर अपने काम में फैल हों और वे फैल होते भी हैं। क्योंकि आप तो उनको रुपये दोगे १२ हजार या १५ हजार और उनको चाहिए अपने काम को अच्छी तरह से चलाने के लिये ५० हजार रुपये। तो जब पूरे रुपये नहीं मिलते हैं तो कुछ तो एसोसियेशन में चले जाते हैं और कुछ बनिये के पास चले जाते हैं।

पाली में हर साल बुनकर सप्ताह मनाते हैं। इसकी सूचना निकाली जाती है कि बुनकर सप्ताह मनाया जायगा। जरूर मनाया जायगा क्योंकि हुक्म निकला है, आज्ञा का पालन करना है। लेकिन बुनकर सप्ताह होता क्या है? बड़ी लंबी-चौड़ी बात होती है। उन बुनकरों को जब हम पूछते हैं कि तुम क्या कमा लेते हो तो वे उत्तर देते हैं कि सवा रुपया रोज कमा लेते हैं जिसके लिये हम दिन भर काम करते हैं, सुबह से शाम तक बीच में कुछ देर के लिये चिलमें आदि भी पी लेते हैं और काम करने वालों में मैं भी हूँ, मेरी धर्म-पत्नि भी है और छोटा बच्चा जो स्कूल जाता है वह भी घंटा—डेढ़ घंटा काम करता है। और सब मिल कर कमाते क्या हैं? सवा रुपया।

आप स्वयं देखिये कि आपके बुनकर जो कपड़ा बुनते हैं उसके लिये मार्केट कौनसा है और उनका स्टॉक पर्चेज़ करने वाला कौन है? उधर मिल्स जो कपड़ा निकालती हैं वह

(श्री मूलचन्द डागा)

सुहावना होता है, टिकाऊ होता है और सस्ता होता है। इसलिये सभी लोग इस मिल के कपड़े को खरीदते हैं और आप जो बुनकर सप्ताह मनाते हैं या बुनकरों के कपड़ों के लिये स्टोर चलाते हैं उसमें कभी कभी कोई एम. एल. ए. या मिनिस्टर पहुँच गया तो एक-आध चद्दर खरीद ली इस ख्याल से कि वहां तक गये हैं तो कुछ न कुछ खरीदना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेन्ट को एक बात देखनी चाहिये कि इन बुनकरों को आप पूरी मदद दीजिये, जिसके जरिये वे ऐसा कपड़ा तैयार कर सकें, जिससे दूसरे लोग खरीदने को तैयार हो जावें।

आपके यहां के नियम इस प्रकार के हैं कि जो बुनकर संस्था में काम करेगा उसको १०० रु० तनख्वाह दी जायगी। फिर उसके लिये क्लर्क या लिपिक चाहिये। उसको ६० रु० माहवार देंगे। उसके बाद चपरासी चाहिये उसको भी तनख्वाह देंगे और ये सब मिल कर बुनकरों की दूकान चलाते हैं। दूसरी ओर एक महाजन अपनी दुकान चलाता है जिसमें सेठ खुद बैठता है १२ घंटों तक तथा और ज्यादा काम होता है तो एक मुनीम और रख लेता है। इस तरह से आप दोनों का मुकाबला कर लीजिये। हम लोग जो घूमने-फिरने वाले हैं, ये पूछते हैं कि आया बुनकर संस्थाएं अच्छी तरह चल रही हैं? हम लोग यह सोचें कि हम उनको रोजगार दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, लेकिन आप सोचिये कि न तो इस तरह से उनको रोटी मिलती है और न रोजगार मिलता है। वे बुनकर वर्षा के समय अपनी जमीन पर जाकर खेती करते हैं, उससे उनका काम चलता है।

फिर वे जो कपड़ा बुनते हैं और रंग निकालते हैं वह कैसा होता है? वह ऐसा थर्ड क्लास होता है कि जौहरी बाजार या चौड़ा रास्ता होकर रामनिवास बाग में घूमने जाने वाले लोग उसको कदापि पसन्द नहीं करते। आप बुनकर संस्थाओं से कपड़ा लेकर पहिनने की कोशिश करिये। आज बुनकर संस्थाएं कमजोर हैं, कुछ आदमी जो मजबूत होते हैं वे उनका शोषण कर लेते हैं।

(१. म. प.)

कुछ नाम चलते हैं, साहब। बुनकर सप्ताह चल रहा है। लेकिन बुनकरों के कपड़े को खरीदने वाला कौन है? आप मार्किन खरीदते हैं।

इन संस्थाओं को चलाने वाले हैं, इनको चलाने के लिए मैं समझता हूँ दो-तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि इस कपड़े के मार्केटिंग के लिए उम्मीद होनी चाहिए, दूसरा है कि पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। आपने ग्यारह हजार रुपये दे दिये, दस हजार रुपये दे दिये, आठ हजार रुपये दे दिये, लेकिन लोग इस कपड़े को पसन्द करते नहीं हैं, फिर आप प्रोडक्शन ज्यादा करवाना चाहते हैं। वह कपड़ा पड़ा रहता है, थान के थान पड़े रहते हैं। उस पर बुनकर को एक रुपया, डेढ़ रुपया कमाने को मिलता है, लोगों के पल्ले कुछ नहीं बचता। फिर एक तरफ बनिये की दूकान चल रही है और आपका प्लॉन है कि वह कपड़ा बुनकर दे। मैं समझता हूँ, चाहे आप एक दूकान चलायें,

(श्री मूलचन्द डागा)

लेकिन लोगों को विश्वास रहना चाहिए, लोगों में आज विश्वास नहीं है।

थोड़े समय से धीरे धीरे राजस्थान में राष्ट्रीयकरण की बात सामने आ रही है, वह बात साफ होनी चाहिए। मैंने देखा है कि पाली में ८० बुनकर हैं। उन ८० बुनकरों को देखा है; थके, मांदे, गिरे हुए, गरीब भाई। कहा, तुम संस्था चलाते हो, गवर्नमेंट तुम्हें मदद करती है? बोले, क्या करें, बड़ी हीन अवस्था है। हमें कोई बता दे, खादी क्षेत्र में इन बातों का क्या असर होगा? उनका कपड़ा खरीदने वाला नहीं है। खादी वाले कहते हैं, हम हाथ का बुना कपड़ा पहिनेंगे। बुनकर का कपड़ा कौन पहिनने वाला है, खरीदने वाला है? मद्रास से कपड़ा आता है, एक—दो नमूने उसके पेश करते हैं। इसके साथ जो प्रदर्शनी होती है, वह उस सब को खत्म कर देती है। उसमें एक—एक, दो—दो टुकड़े रख दिये जाते हैं और कहते हैं कि कपड़ा बनाना चाहते हैं अच्छा। लेकिन उस कपड़े को काम में नहीं लेते। तो आपको बुनकरों का विकास करना पड़ेगा, उसके लिए गौर करना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री को कहना चाहता हूँ कि दो चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं; महाजन, जो दूकान चलाता है और बुनकर। वे साथ साथ नहीं चल सकते। जहां दो साथ चलते हैं वहां कोई काम नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि बुनकर का कपड़ा गवर्नमेंट को अपने काम में लेना होगा, वह कपड़ा स्कूल के काम में आयेगा, डस्टर बनाने के काम में आयेगा। नहीं तो वह किसी काम का नहीं है। केवल लोन की गर्ज से संस्था बनाते हैं, जिनको अधूरा थोड़ा बहुत लोन मिल जाता है। इस तरह आप उनको अधर में रखते हैं, न जमीन पर हैं और न आकाश पर हैं। आकाश में होते तो हवाई जहाज में उड़ते। जमीन पर चलते हैं और कोई संस्था चलाते हैं तो वे संस्थायें फैल हो जाती हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होता। मैं समझता हूँ कि इस पर आप और गौर करें कि बुनकर संस्थाओं से क्या लाभ है।

मैं दूसरी बात कह रहा था कि....

श्री अध्यक्ष : आपके और भी कटौती प्रस्ताव हैं। एक पर आप इतना बोल लेंगे तो दूसरों पर क्या बोलेंगे?

श्री मूलचन्द डागा : मैंने अभी बुनकर पर नींव डाली है....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अभी नींव डाली है, मकान बनना बाकी है।

श्री मूलचन्द डागा : आप घरेलू उद्योग की मोटी मोटी और बड़ी बातें करते हैं, आप सर्वे करना चाहते हैं; सर्वेक्षण करना चाहते हैं, हम वह चाहते हैं। बड़े बड़े आदमियों को नियुक्त करते है। अब सर्वेक्षण का और सर्वे का काम रहे हैं, लेकिन घरेलू उद्योगों की चीजों को आखिर खरीदेगा कौन? आपके घरेलू उद्योगों की चीजों को इस जमाने में खरीदने वाला नहीं। आप खरीद लेओ। न कोई ऐसी चीज हैं और न ऐसे कोई कलाकार ही हैं। फिर आप घरेलू उद्योग को पनपाना चाहते हैं। इसमें क्या होता है

(श्री मूलचन्द डागा)

कि पंचायत समिति की एक मीटिंग होती है, उसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आता है, इन्डस्ट्री ऑफिसर । वह आकर भाषण शुरू करता है । कहता है, घरेलू उद्योग को पनपाने के लिए....

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि इतने विस्तार से इस तरह के अवसर पर बहस करने का मौका नहीं है । आप इस मौके पर ऐसे सुझाव दे सकते हैं—आंकड़े क्या हैं, नीति के बारे में क्या राय है । कटौती प्रस्ताव का जो तरीका है उस तरीके से बोलें, न कि सामान्य वाद-विवाद के रूप में ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं सुझाव दे देता हूँ । यह सवाल है घरेलू उद्योग का । हमें होम इन्डस्ट्री को पनपाना है । उसका तरीका यह नहीं है, जिस तरीके को आप अख्तियार करते हैं । जो इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है उससे होम इन्डस्ट्रीज़ को लोन दिया जाता है । मेरी समझ में जितने घरेलू उद्योग हैं, जिन्होंने होम इन्डस्ट्री के नाम पर लोन उठाया है, उनके बारे में इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट यह बतला दे कि हमने इतने घरेलू उद्योगों में सहायता देकर इतनों को पनपाया है ? जो इन्डस्ट्रीज़ अम्बाला, लुधियाना में चल रही हैं, जापान में उद्योग चल रहे हैं, उनके मुकाबले में वे चल नहीं पाते हैं और न हमारी भूमि ही ऐसी है । जहां तक घरेलू उद्योगों का सवाल है, हमारे यहां सिर्फ तीन घरेलू उद्योग हैं । कुछ लोग कपड़ा बुनने का काम करते हैं, कुछ मिट्टी का काम करते हैं, कुछ लोग रंगाई का काम करते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पाली में जहां रंगाई-छपाई का काम बहुत ज्यादा होता है वहां पर कोई इन्स्ट्रक्टर नहीं है और न अभी तक इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट द्वारा ध्यान दिया गया है । मैं समझता हूँ कि पाली की रंगाई-छपाई राजस्थान में प्रसिद्ध है । वहां पर इन्स्ट्रक्टर दीजिये, ताकि वहां जो छीपे लोग हैं, वहां इस काम को करने वाले लोग हैं, उनको काम सिखा सकें । लेकिन जिस जगह पर आप इन्स्ट्रक्टर दे रहे हैं वहां पर उनका उपयोग नहीं हो पाता । इसलिए मैंने पाली के लिए खास तौर से कहा है, घरेलू उद्योग के मामले में छीपे लोग पानी में काम करते हैं, उनको हमें मदद देनी चाहिए ।

कोयले के वितरण के बारे में मेरा एक प्रश्न था । अभी तक मैं समझ नहीं पाया कि राजस्थान में कोयले का सवाल है, उसके सम्बन्ध में गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग जगह पर अलग अलग दरें होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती ; कहीं पर ठेकेदार दो रुपये ज्यादा ले लेता है, कहीं पर चार रुपये ज्यादा ले लेता है, कहीं पर तीन रुपये ज्यादा ले लेता है । सरकार ने एक दफा ऐसी आज्ञा निकाली थी कि कोयले का जो वितरण हो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाय जिला स्तर पर और जिला स्तर पर कमेटी उस कोयले का वितरण करे । जयपुर में सुनते हैं दरों के बारे में, और सब जगह इस तरह का सवाल है । मैंने खास तौर पर पाली का लिखा है कि जो कोयले का वितरण होता है उसमें गड़बड़ी होती है ।

आज लकड़ी बहुत मंहगी मिलती है । फिर भी परमिट से कुछ कोयला मिल पाता है । यह परमिट देने का डिस्क्रिशन किसका है ? परमिट मिलती किसको है, किसको कोयले

(श्री मूलचन्द डागा)

की आवश्यकता है, क्या शर्तें हैं? मेरी समझ में जो कोयले का व्यापारी हैं वह भी अपने कुछ आदमी बांध देता है किसी सरकारी कर्मचारी के साथ, जो हमेशा उसके साथ रहते हैं, जैसे मक्खी छत्ते पर भनभनाती है। कोयला जैसे ही आता है, दो–तीन दिन में सारे पर्मिट इश्यू हो जाते हैं। उसके बाद स्टॉक नहीं है, दो–तीन दिन में स्टॉक खत्म हो जाता है। पर्मिट कौन इश्यू करता है, कोयला किस भाव पर देते हैं, एक जगह पर कितने वैगन्स देते हैं ?

पाली में इस मामले में बेचारे हलवाइयों ने शिकायत की कि हम मुश्किल से गुजर करें और पर्मिट के लिए एक घन्टे तक खड़े रहें, उसके बाद जाकर कोयला मिलता है। मैं समझता हूँ कि उसके लिए कोटा फिक्स होना चाहिए कि फलां हलवाई को इतनी जरूरत है कोयले की, उसको इतना मिलेगा। फिर सवाल है कि कोयला किसको मिलना चाहिए, क्या साधारण स्तर के लोग हैं, वे कोयले का पर्मिट ले सकते हैं या जो उच्चतम वर्ग के लोग हैं वे पर्मिट ले सकते हैं या जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं वे कोयले पा सकते हैं ? इस कोयले के मामले में इतनी गड़बड़ी है। मैं समझता हूँ कि सरकार को वापिस सोचना चाहिए और खास तौर पर पाली के मामले में। वहां जो कोयले का ठेकेदार होता है वह काफी नफा कमा लेता है। कोयले के वितरण में पर्मिट बिकती हैं, इससे लोगों का नैतिक पतन होता है और उनका नैतिक स्तर फॉल होने लगता है।

मैं समझता हूं कि जो कोयले की कमेटी मुकर्रर है उसका कोई सिद्धान्त नहीं है, हर जगह वह मुकर्रर नहीं होती है। इसके बाद कोयले के काम में किसकी जिम्मेदारी होती है, कहीं पर यह मामला तहसीलदार को सौंपा हुआ है, कहीं एस०डी०ओ० को सौंपा हुआ है, अगर मन चाहा तो कलेक्टर को दे दिया। उसके बारे में कोई वितरण करने का सवाल नहीं है, कोई कमेटी मुकर्रर करने का सवाल नहीं है। आपके जयपुर में कुछ भाव से मिलेगा, जोधपुर में किसी भाव से मिलेगा, पाली में किसी भाव से मिलेगा, दर फिक्स नहीं है। मैं इस कोल के मामले में, कोल के वितरण में पाली जिले में एक असंतोष पाता हूँ। हलवाइयों को, रोज के काम करने वालों को, खोमचे वालों को काफी परेशानी है और तकलीफ उठानी पड़ती है। सरकार इस पर ध्यान दे और सरकार की जो योजना है उसके ऊपर विचार करके उसके ठीक भाव मुकर्रर कर, इस पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, आज अपने सारे विभागों में कोई विभाग अपनी उपयोगिता सिद्ध करने में असफल रहा है, तो मैं समझता हूँ अपना उद्योग विभाग है। इसका नम्बर सबसे प्रथम आता है। जिस समय माननीय वित्त मन्त्री जी अपना बजट भाषण दे रहे थे उस समय किसी के नम्बर सबसे अच्छे आये थे योग्यता के नाम पर तो वह है वित्त विभाग। वह इस-

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

लिए कि जो कटौतियां की गई हैं, उन कटौतियों के अन्दर हमारे वित्त विभाग ने हमारे माननीय वित्त मन्त्री की सहायता की है और जो कटौतियां की गई हैं वे वित्त विभाग में कटौतियां की गई हैं। उसमें वित्त विभाग सबसे आगे था। यही कारण था कि जितनी माननीय सदस्यों ने तालियां बजाई और तालियों की गड़गड़ाहट में भाषण हुआ, उन्होंने कहा इतनी कटौतियां कर दी हैं, इतनी कटौतियां कर दी हैं, उसमें सबसे ज्यादा नम्बर आये तो उद्योग विभाग के नम्बर थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचवर्षीय योजना में विभाग कटौतियां करते हैं, जहां तक मितव्ययता का प्रश्न है, उसमें कटौतियां करनी चाहिए। लेकिन किस विभाग में कटौतियां करनी चाहिए, मैं समझता हूं उद्योग विभाग में कटौती उचित नहीं होती। इस सम्बन्ध में सबसे ज्यादा गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर द्वारा कुछ कागज़ देखने के कारण मौन)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहें तो बाद में बोल सकते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : नहीं साहब,

(पुनः कुछ क्षण मौन)

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि उद्योग विभाग का आज का बजट देखें तो ५४ लाख का आता है। पिछले साल का ६६ लाख का बजट था तो यह ११, १२ लाख काटा कैसे गया? पहले ५८ लाख का बजट था। तो ये कटौतियां किन कारणों से किन किन मदों में की गई हैं?

कुटीर उद्योग का मद दिया है। उसमें ४ लाख का प्रावधान किया है, जब कि पिछले वर्ष में ११ लाख का प्रावधान था। ११ लाख से घटा कर एक दम ४ लाख कर दिये हैं, तो क्या हमारे यहां कुटीर उद्योगों की आवश्यकता नहीं है या हम पूरे के पूरे कुटीर उद्योग खोल चुके हैं?

सहायता के सम्बन्ध में विगत वर्ष में १८ लाख की रकम थी, उससे घट कर १७ लाख पर पहुँची है। अन्य विभागों को सहायता देनी थी उसमें भी कमी की है तो क्या इसके माने ये समझे जायं कि विभाग के पास योजना नहीं है?

५८ में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। हमारे यहां का वर्किंग ग्रुप बैठा हुआ था, जिसको बनाने में विभाग के डाइरेक्टर और सेक्रेटरी हैं, उन्होंने रिपोर्ट बनाई। उनके आधार पर उद्योग फलेंगे फूलेंगे और विभाग का बजट भी आगे बढ़ेगा, मन्त्री महोदय और विभाग के डाइरेक्टर ने वह चीज़ तैयार की थी कि बजट बढ़ेगा; बजट बढ़ता, पर कटौती करके वाह वाह लूटनी थी, इसलिये कटौती कर दी। हमारी संभावनाएं बहुत हैं। यदि हम यह सोचें कि हमारी संभावनाएं समाप्त हो गई हों, यह सही नहीं है। हमारे यहां संभावनाएं बहुत हैं। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूं कि हमारे यहां ऊन उद्योग में बड़ी संभावनाएं हैं। हमारे यहां ऊन होती है १४ पर्सेंट। सारे देश की नहीं है, उतनी यहां

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हमारे प्रान्त में होती है। इसका मुख्य भाग बाहर जाता है। यदि वह सारा का सारा भाग यहां रहता तो समझते कि विभाग के सामने काम नहीं है, पर हमारे यहां जितनी ऊन पैदा होती है, ६० प्रतिशत भाग विदेशों में जाता है, अपने देश के ही दूसरे भागों में जाता तो कोई बात नहीं थी पर विदेशों में जाता है। मन्त्री महोदय कहेंगे कि हमें इससे फोरिन एक्स्चेन्ज कमाने की आवश्यकता है, पर इससे तैयार हुआ माल बहुत बड़ी तादाद में हमारे देश में आता है। उसके लिये कितने गुना फोरिन एक्स्चेन्ज हमें विदेशों को देना पड़ता है, इसको भी ख्याल में रखना चाहिये। तो इस ऊन की इन्डस्ट्री को पनपाने के लिये क्या कोशिश होनी चाहिये, इसके बारे में दो—चार बातें कह कर विभाग और वर्किंग ग्रुप चुप हो गया। उसमें भी कोई इस प्रकार का सुझाव नहीं दिया कि ऊन के उद्योग के लिये हम यह करना चाहते हैं, न विभाग ने इस बारे में कुछ किया है। इसका मैं जीता जागता उदाहरण रखना चाहता हूँ। आज से लगभग चार वर्ष पहले से इस तरह की बात चल रही है कि सोल्जर्स एन्ड सेलर्स बोर्ड की तरफ से राज्य सरकार को कहा गया कि भूत-पूर्व सोल्जर्स और सेलर्स के लिये एक ऊन की इन्डस्ट्री खोली जाय। बोर्ड ने रकम भी निर्धा-रित कर दी कि इसके लिये हम इतनी रकम देंगे, और जगह भी निर्धारित कर दी गई थी कि सीकर में वूल इन्डस्ट्री खोली जायगी। पर राज्य सरकार द्वारा रोड़े अटकाने के कारण वह इन्डस्ट्री आज तक नहीं खुली है। सोल्जर्स बोर्ड ने कहा कि हमें जगह दो, हम यह इन्डस्ट्री स्थापित कर सकें; कलेक्टर ने इसके लिये जगह भी तजवीज कर दी, पर फिर इसके बाद पोलिटिकल प्रेशर पड़ा और यह वूल इन्डस्ट्री खटाई में पड़ गई। कलेक्टर ने कहा कि हम यह जमीन एक्वायर करना चाहते हैं। हमारे प्रान्त के मुख्य मन्त्री और चीफ सेक्रेटरी इस इन्डस्ट्री को शिफ्ट करके देवगढ़ या उदयपुर में ले जाना चाहते थे, सीकर में कलेक्टर थे वे भी मेहता ही थे तो दोनों मेहता मिले। एक चीफ मिनिस्टर सुखाड़िया मिल गये और तीनों ने मिल कर षड्यन्त्र किया कि वह जमीन स्टेशन के पास है उसको एक्वायर करना चाहते हैं। वह जमीन एक्वा-यर भी नहीं हुई और इस बात को टालते टालते ५ वर्ष हो गये हैं, उस वूल इन्डस्ट्री को सीकर में न रख कर और जगह रखना चाहते हैं। सीकर मेरा स्थान है, इसलिये वहीं पर यह इन्डस्ट्री खुले, यह मोह मुझे नहीं। सीकर से अधिक उपयुक्त स्थान और कोई है तो वहां पर यह इन्डस्ट्री खोली जाय, उदयपुर में खोली जाय, देवगढ़ में खोली जाय, चाहे यह है नाथद्वारा में खोली जाय या कोटा में खोली जाय, कहीं भी खोलिये, पर खोलिये तो सही। प्रश्न यह कि इतने साल से अपने प्रान्त के भूतपूर्व सैनिकों को इन्डस्ट्री खोलने हेतु पैसा सोल्जर्स बोर्ड द्वारा देना तय हुआ था, वह क्यों नहीं लगाया गया? कहीं भी लगाइये, पर उस पैसे को जो सोल्जर्स बोर्ड से मिल रहा है उसे लगाइये। वह पैसा नहीं लग रहा है, यही मूल आपत्ति है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि सोल्जर्स बोर्ड से सम्बन्ध स्थापित करके यह इन्डस्ट्री जल्दी से जल्दी चलानी चाहिये। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगा कि मुख्य मंत्री या चीफ सेक्रेटरी जिस स्थान को फायदा

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

दिलाना चाहते हैं दिलायें, पर मुख्य रूप से भूतपूर्व सैनिकों के लिये जिनको कि देश में उद्योग देने की बड़ी आवश्यकता है उनको काम-धंधा देने के लिये जो सैंक्शन्ड स्कीम वूल इन्डस्ट्री की है उसको जरूर जल्दी से जल्दी खोलना चाहिये ।

दूसरा, जिस चीज़ का उद्योग ज्यादा खुल सकता है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और वह है चमड़े का उद्योग । वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है, लगभग तीन करोड़ के कैटल हैं और उस कारण से वहां पर इतना ज्यादा चमड़ा उत्पन्न होता है कि यदि हम उसका उपयोग करें तो सारे देश में इस इन्डस्ट्री के द्वारा देश की बहुत बड़ी कमी को पूरा कर सकते हैं । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बजट में काम करने वाले विभाग इसको प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं । उसी का यह कारण है कि हमारे यहां का कच्चा चमड़ा आगरा और कानपुर जाता है जहां चमड़े के बड़े बड़े उद्योग हैं । मैं यह कहूँगा कि वहां पर केवल चमड़ा ही नहीं जाता, बल्कि श्रमिक भी वहां जाते हैं । मैं लखनऊ गया था वहां पर मैंने हमारे यहां के कई श्रमिकों को वहां पर देखा । हमारे यहां के हजारों श्रमिक आज चमड़े की फैक्ट्रीज़ में आगरा, कानपुर, लखनऊ और बम्बई में दिखाई देंगे । हमारे यहां के श्रमिक बाहर इसीलिये जाते हैं कि हमारे यहां पर कोई रोजगार नहीं है । इसलिये मैं यह कहूँगा कि हमारा उद्योग विभाग इस कार्य को करने में असफल रहा है, इसलिये यह कट मोशन रखा है ।

यह नहीं है कि उसके सामने कोई योजना नहीं हो । ऐसी बात नहीं है कि विभाग इसको जानता नहीं हो । विभाग के पास योजना है और विभाग इस बात को जानता है और विभाग के सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारियों ने योजना बनाई कि इस प्रकार के धन्धे यहां हो सकते हैं । वे स्वयं दुनिया को बताते हैं कि इस प्रकार की योजना होनी चाहिये । मगर अपने यहां पर उस योजना को लागू नहीं करते, यह सबसे बड़ी शर्म की बात है । इससे भी ज्यादा शर्म की बात तब होगी जब यह ग्रुप की रिपोर्ट अन्य प्रान्तों में जावेगी और दूसरे प्रान्तों के लोग देखेंगे कि जो लोग स्वयं इस प्रकार की बातें कहते हैं और जिनके पास इस प्रकार का उद्योग बनाने का स्कोप है और नहीं बना रहे हैं और हमारा सारा चमड़ा बाहर जाता है । मैं हमारे सेट–अप को इसके लिये धन्यवाद दूं कि हमारे इस विभाग ने सबसे बड़ी कटौती की है ?

दूसरी बात हड्डियों की है । जब तीन करोड़ कैटल हैं तो उनकी कितनी हड्डियें होती हैं ? उसका उपयोग भी, जयपुर में चूरा बनाने की इन्डस्ट्री खोली है उसके यहां होता है, लेकिन इसके अलावा जितनी हड्डियें हैं वे एक्सपोर्ट होती हैं । मैं यह कहूँगा कि हमारे इन्डस्ट्री विभाग के जो मंत्री हैं उनको अच्छा काम करने के लिये तीन मेडल दिये जावें, एक खून का, दूसरा हड्डियों का और तीसरा चमड़े का । तो मैं यह कहूँगा कि वे तीनों प्रकार की इन्डस्ट्रीज में असफल रहे हैं ।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-मु०) : आप भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़

(श्री हरिप्रसाद यादव)

बना कर चर्म उद्योग को प्रोत्साहन दीजिये ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां तीन प्रकार के रॉ-मैटीरियल्स ज्यादा मिलते हैं और उन तीनों प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन देने में हमारी सरकार का उद्योग विभाग असफल रहा है। आपने जो प्रावधान बजट में किया है वह १७ लाख का किया है, लेकिन जब हमें अनुदान देंगे जिससे यह कार्य खुले तो मैं यह कहूँगा कि यह कम है । अगर उसको आप ५० लाख या एक करोड़ तक पहुंचा देते तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सदस्य इसका एतराज नहीं करता। अगर कोई किसी प्रकार का एतराज उठाता तो जिस प्रकार से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया कि जो धन रखा जावे उसका सदुपयोग होना चाहिये; अगर उस धन-राशि का ठीक उपयोग होगा तो वह धन लोगों की आमदनी को बढ़ावेगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारा इन्डस्ट्री विभाग लोगों को लोन देता है। उसके बाद में विभाग के पास कोई मशीनरी नहीं है कि जिससे वे इस बात की जांच कर सकें कि जिसको लोन दिया गया है उस जगह उतना उत्पादन भी हुआ या नहीं । इसकी जांच करनी चाहिये। आखिर रुपया जो हम लोन के रूप में देते हैं उसका सदुपयोग होना चाहिये। एक साल में १७ लाख या १८ लाख या १६ लाख जो भी आप रखते हैं, आपको यह देखना चाहिये कि जिसको रुपया दिया जाता है उसका उस प्रोपोर्शन में आउटपुट बढ़ता है या नहीं। इस बात को देखने के लिये आपके पास कोई मशीनरी नहीं है। पिछली बार हमने सीकर जिला परिषद् में कमेटी बनाई और कुछ को लोन दिया और कई जातियों को दिया । हमने उसके लिये पूछा कि जो लोन दिया जाता है उसका सदुपयोग होता है या नहीं ? तब उन्होंने कहा कि हम इसको देखने के लिये नहीं हैं; इसलिये कि हमारे विभाग के पास इस प्रकार देखने के लिये कोई मशीनरी नहीं है ।

मैं आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूँ कि शेखावाटी फर्नीचर हाउस है। वे कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उनको इसके लिये १० या १५ हजार रुपये जयपुर डिस्ट्रिक्ट से दिये गये हैं। वहां के स्थानीय लोगों ने नहीं दिये। उनका समय ज्यादातर राजनीति में जाता है । तो उन्होंने इस विभाग को धोखा देकर क्या किया है कि अगर कोई आए तो मालूम होता रहे कि काम हो रहा है; इसलिये उन्होंने वहां पर खाती को बैठा रखा है। राजस्थान में जिस प्रकार इन्डस्ट्रियल एस्टेट बना कर शेड बनाने के लिये कर्जा दिया उस समय सेठ साहब ने भी सोचा कि मैं भी शेड बना दूं और उन्होंने शेखावाटी फर्नीचर हाउस पर शेड बनाया। वहां पर उन्होंने शेड को किराये पर दे रखा है और १५ हजार का इन्वेस्टमेंट लोन के रूप में सरकार से ले रखा है। वह इसलिये कि नेता राजनैतिक कार्य में भाग लेते रहें और उनका काम चलता रहे। मैंने इस प्रकार की यह एक एग्ज़ाम्पल दी है कि लोग बैंकों में रुपया जमा करा लेते हैं और ब्याज से उनको आमदनी होती है और मकान के

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

किराये से उससे काम चलाते हैं और राजनीति में काम करते हैं । इसलिये यह देखना जरूरी है कि जो कर्जा लिया गया है उसको ठीक तरह से काम में लिया गया है या नहीं और उससे क्या आउट-पुट होता है ? इसको जांच करने के लिये मशीनरी होनी चाहिये । मगर जांच नहीं होती और वह इसलिए नहीं होती कि लोग अपने भाई-भतीजों को रुपया दे देते हैं । किसी को राजनैतिक कार्य को चलाने के लिये दे देते हैं । इसकी हमारे विभाग को चिन्ता नहीं कि जो रुपया लोन के रूप में दिया जाता है या सब्सिडी के रूप में दिया जाता है उसका सदुपयोग होता है या नहीं । मैं यह निवेदन करूंगा कि यह विभाग इन कार्यों को करने में असफल रहा है । इसलिये कटौती प्रस्ताव रखा है । असफल इसलिये रहा है कि फैक्ट्रीज़ बढ़ाई नहीं जिससे बेकारी मिट सकती थी । जर्मीन से तो आप कह सकते हैं कि पोटेन्शियेलिटी बढ़ नहीं सकती, लेकिन इन्डस्ट्री में तो इसके लिये स्कोप है । इसलिये माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह विभाग इसमें असफल रहा है; इसलिये मंत्री महोदय को इस्तीफा दे देना चाहिये या बजट में इसके लिये प्रोविज़न बढ़ाना चाहिये । अगर वे इसके लिये बजट में कमी करते हैं तो मैं यह कहूँगा कि वे इस पद के अयोग्य हैं और उनको इस्तीफा देना चाहिये ।

श्री हरिप्रसाद यादव : केवल इस्तीफा देने से क्या होगा ? समय का सदुपयोग कीजिये । इस्तीफे से क्या होगा ? काम में सुधार करिये ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैंने सुधार करने के लिये ही सुझाव दिये हैं । वे माननीय मंत्री महोदय मानें ।

अध्यक्ष महोदय, खादी बोर्ड के बारे में बहुत बातें कही गई हैं । मैं किसी प्रकार की आलोचना नहीं करना चाहता । हमारे सर्वमान्य नेता हैं श्री विनोबा भावेजी, उनसे खादी के कार्यकर्त्ता मिले जिस समय वे राजस्थान में पधारे । उस समय उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो खादी को अनुदान देती है वह इस प्रकार का है कि कोई आदमी मर गया हो और उसको इन्जेक्शन दे देकर उसमें बाद में जान डाली जाए । मैं कहूँगा कि जिस खादी को महात्मा गांधी ने जिस देश में आजादी को प्राप्त करने के लिये पवित्र साधन बनाया उसको संत विनोबाजी कहते हैं कि राजस्थान का खादी उद्योग इस प्रकार का है कि जैसे कोई आदमी मर गया हो और राज्य सरकार उसको जिलाने के लिये इन्जेक्शन देती है । इस प्रकार की बातें खादी के लोगों के लिये बड़े शर्म की बातें हैं । जब संत विनोबाजी इस प्रकार की बातें कहते हैं जिससे साफ जाहिर है कि खादी की क्या पोज़िशन है ।

इन सारी बातों को कहते हुए माननीय मन्त्री महोदय से और विभाग के सभी अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें । इतना ही मैं निवेदन करता हूँ ।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु.) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दो कटौती प्रस्ताव मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३ में प्रस्तुत किये हैं और जो पहला कटौती प्रस्ताव है वह खास कर बीकानेर क्षेत्र में औद्योगिक विकास की जो संभावनायें हैं उसके प्रति सरकार की किस प्रकार से उपेक्षित नीति रही, उस पर कुछ प्रकाश डालने के लिए और दूसरा कटौती प्रस्ताव भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल्स में जो अव्यवस्था है उसके बारे में है।

(१. ३० म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने उद्योग मन्त्री महोदय, के लिए कहा कि वे अयोग्य हैं, उनको त्याग-पत्र दे देना चाहिये। मैं उसके विपरीत मान्यता रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारे उद्योग मन्त्रीजी जहां तक उद्योगों का मामला है उनमें काफी निपुण हैं और उसके साथ साथ वे इस चीज़ के सम्बन्ध में काफी जानकार भी हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि वें राजस्थान का विकास किस प्रकार से करें। मैंने खास कर बीकानेर क्षेत्र की बात को इसलिए लिया है कि एक बड़े शहर की वस्तु-स्थिति किस प्रकार की होती है उससे सारे शहरों की तुलना की जा सकती है और वहां विकास की स्थिति क्या हो सकती है उस पर सोचा जा सकता है। इसलिए इस क्षेत्र को ही ले लेने से कोई इसका यह मतलब न समझें कि क्षेत्रीय दृष्टिकोण से मैंने यह रखा है। लेकिन जो इसके पीछे मेरी भावना है वह यह है कि जो बातें उस क्षेत्र के लिए जुड़ेंगी वे सारे क्षेत्रों के लिए जुड़ेंगी।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब सन् ५२ में पहली पंचवर्षीय योजना शुरु हुई तो उसके प्रारम्भ से ही सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए धारणा जनता के सामने रखी कि राजस्थान में किस प्रकार से औद्योगिक विकास करना चाहते हैं; पहली योजना में कितना काम कर लेंगे और दूसरी में कितना ? इस प्रकार की घोषणा सरकार ने हमेशा से की है और बीकानेर की बात इसलिए कह रहा हूँ कि उससे आपको यह अन्दाज लगेगा कि दूसरी जगह के लिए कितनी २ घोषणायें की गई और उनमें से कितना काम कर पाये हैं और कितना क्यों नहीं कर पाये।

मैं बीकानेर क्षेत्र के लिए कहना चाहता हूँ कि उसके आसपास जितनी संभावनायें थीं, चाहे बीकानेर की ऊन इन्डस्ट्री हो, चाहे वह बीकानेर के पास पलाना की खान के सम्बन्ध में हो, चाहे वह जिप्सम की इन्डस्ट्री के सम्बन्ध में हो, इसी प्रकार से कोलायतजी के पास खड़िया मिट्टी, मुलतानी मिट्टी के विकास के सम्बन्ध में हो, और इसके साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस के सम्बन्ध की, बाकी जितने भी खनिज पदार्थ थे उनके लिए पहली योजना में कहा कि यह काम कर देंगे, खड़िया मिट्टी का कारखाना खोल देंगे। ये बातें सन् ५२ से कही हैं और यदि ये बातें गलत हों तो स्वयम् आप योजनाओं में देख लीजिये कि उस क्षेत्र के लिए राजस्थान सरकार ने कहा या नहीं। खेद इस बात का है कि उनमें से एक भी, नौ साल समाप्त हो गये, काम को पूरा नहीं कर सके। इससे अन्दाज लगाया जा सकता है

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की बातें इस प्रकार से दूसरे स्थानों पर भी कही गई होंगी। अभी सीकर से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने कहा कि पांच साल पहले जमीन आदि के बारे में कहा था लेकिन वे काम बिल्कुल साफ हो गये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन सारी चीजों के लिए वहां पर कोई काम नहीं हुआ। ८ साल के बाद में जब पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कारखाना सरकारी योजना में था, सरकार ही उसको शुरु कर रही थी और कहा गया था कि बहुत जल्दी इस प्रकार की इन्डस्ट्री खुलेगी, लेकिन आज तक वह क्यों नहीं हुआ ? उसका उत्तर शायद वे यह दे सकते हैं कि कुछ साधन नहीं जुटे। इतना ही नहीं, सरकार ने इसको आवश्यक समझा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कारखाना खोलना चाहते हैं, लूणकरणसर खान में कच्चे माल का उत्पादन होता था, सरकार खोलना चाहती थी, उसकी योजना थी। लेकिन सरकार ने खान बन्द की और जो वहां पर मजदूर काम करते थे उनको भी समाप्त किया। उसके बाद में न तो उन्होंने खोला और न सरकार ने। अगर उसने एग्रीमेंट किया था तो उसको तोड़ते हैं, सरकार को पता करना चाहिये। लेकिन सरकार का यह पहला काम था कि थोड़ी लागत में भी सरकार उसको खोलती। सरकार ने नहीं खोला। इसी प्रकार से खड़िया मिट्टी के बारे में कोलायतजी में पूरी संभावनायें थीं। जब जब मन्त्री लोग बीकानेर आये उन्होंने हर समय घोषणा की, ५२ से लेकर जब जब मन्त्री लोग बीकानेर में आए उन्होंने बार बार घोषणा की, या तो जनता को खुश करने के लिए ही कहा हो कि उद्योग यहां पर खुलेगा लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। पलाना के लिए ओपन कास्ट माइनिंग के लिए काफी कहा गया। खटाई में पड़ा है। अब कह दिया कि दो करोड़ रुपया लगेगा। ग्लास फैक्ट्री राज्य के जमाने में भी चलती थी। उत्पादन भी था। किसी झगड़े की वजह से बन्द हुई थी और सरकार की भी उसमें पूंजी थी और उसके बन्द होने के बाद आज उस पूंजी का कितना ब्याज हो गया ? ग्लास फैक्ट्री के बारे में कितने ही सवाल मैंने यहां रखे, कोई देखने वाला नहीं। माल की चोरी हो रही है; आखिर उसमें सरकार का रुपया है। समझते थे कि वह भी चलायी जायगी लेकिन आखिर में सरकार ने कोई ख्याल नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि वह बन्द पड़ी है और बेकारी दूर करने के लिए कोई गुन्जाइश नहीं है। यह जो वस्तु स्थिति है, योजना में बेकारी दूर करने के लिए बात की थी, यदि उसके पीछे लगन रखते और काम करते तो बेकारी की समस्या हल होती, लेकिन औद्योगिक विकास जिस तरीके से होना चाहिये था, उन्नति होनी चाहिये उस प्रकार से हमने नहीं की। और उस ओर अब तक ख्याल नहीं किया। पहले हमने सोचा था कि उद्योग मन्त्रीजी निपुण हैं, सोचेंगे, विचारेंगे और विकास के सम्बन्ध में कोई योजना बना कर रखेंगे और कम से कम तीसरी पंचवर्षीय योजना में वहां के विकास के सम्बन्ध में कोई बात आवेगी। परन्तु मुझे दुख है कि इतने साधन होते हुए भी इसके सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है। एक किताब तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में सम्पर्क कार्यालय से निकाली गई थी। उसमें लिखा था कि बीकानेर में इनकी इतनी गुन्जाइश है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात प्रकाशित

(श्री मुरलीधर व्यास)

हुई थी, लेकिन जब दूसरी प्रतिलिपि आई तो फिर उसमें से वह बात हट गई। मैंने वह देखी है। आखिर ये परिस्थितियां इस प्रकार से क्यों पैदा होती हैं? यह तो हो गई बात बड़े उद्योगों के बारे में।

छोटे उद्योगों का जहां तक सवाल है उसके सम्बन्ध में मैं यह समझता था विकास के दृष्टिकोण से कि वहां पर भी कुछ काम होंगे। यद्यपि अभी केन्द्रीय सरकार के जरिये बीकानेर में ऊन के उद्योग के लिए कुछ योजनायें बन रही हैं, ऊन की कताई में कुछ रुपया लगाने की बात आई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वहां पर ऊन की कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ हैं, उस आधार पर जो वहां पर काम होंगे, गांवों के जो बेकार लोग हैं उनको काम भी मिलेगा और कुछ साधन भी उपलब्ध होंगे। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ खास कर बीकानेर क्षेत्र के आसपास में जो लोग लकड़ी का काम करते हैं, कपड़े बनाने का काम करते हैं। उनको आधुनिक साधन, पॉवर मिलना चाहिये जिससे हैन्ड लूम द्वारा जो कपड़ा बनता है वह यदि पॉवर लूम द्वारा बनने लग जाता है तो उसके उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकती है और थोड़े से समय में ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इसमें कोई विकास नहीं किया गया। इसी सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं बीकानेर में एक गांव हरदेसर है जहां बिजली नहीं मिलती, वहां हैन्डलूम के कपड़े का उत्पादन बहुत होता है उसके पास ही बिजली है, उससे उनको लाभ पहुँचाया जा सकता है। इसी प्रकार नापासर गांव, सिंथल गांव है, जिसके दो मील पर बिजली है और बिजली भी काफी तादाद में है अगर वहां से प्रबन्ध किया जा सकता है तो लोगों को बहुत लाभ मिल सकता है। भाखरा की बिजली मिल गई है लेकिन इन गांवों में पहुँचाने के बारे में कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। हम तीसरी योजना में चाहते हैं कि गांव गांव में बिजली मिल जाय, लेकिन जो बिजली बहुत कम दूरी पर है और जिसको आसानी से इन गांवों में पहुँचाया जा सकता है, लेकिन पहुँचाया नहीं जाता। इससे उद्योग के विकास के सम्बन्ध में क्या स्थिति हो सकती है, यह देखने लायक है। माननीय मंत्री महोदय से जहां तक कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ का सवाल है, चाहे दूसरी इन्डस्ट्रीज़ का सवाल है मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन दोनों क्षेत्रों में यहां काफी गुंजाइश है। वास्तव में अब सवाल यह आता है इसके लिये कौन कितनी कितनी पूंजी लगावे? यहां पर सवाल यह आता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का। इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि आज पब्लिक सेक्टर में काम करने की और प्राइवेट सेक्टर में काम करने की संभावना को देखना चाहिये। मैं तो यह कहूंगा कि हर क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में बड़े उद्योग खुलने चाहिये। इसका व्यवहारिक अनुभव लेते हुए और यह देखते हुए कि हमें इस ओर कौन कौन से साधन लेने चाहिये जिससे हमारे प्रांत का विकास हो सके, वे सारे के सारे सुधार हमें उपलब्ध कराने चाहिये। प्राइवेट सेक्टर वालों को भी वही सुविधा मिलनी चाहिये। हो सकता है, इसमें हमारी कुछ खामियां हों लेकिन इससे दूसरे लाभ उठा सकते हैं। कम से कम औद्योगिक विकास में शिथिलता जो व्याप्त है उसे हमें रोक देनी चाहिये। पब्लिक सेक्टर में

(श्री मुरलीधर व्यास)

इन्डस्ट्रीज़ खोलें और जो कठिनाइयां इसमें अगर सामने आती हैं तो उसमें रिलीफ देना चाहिये ।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह है बीकानेर शहर के दृष्टिकोण से वहां पर औद्योगिक विकास में कितनी अड़चनें बनी रहीं । सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित करना । कुछ व्यापारियों ने इस प्रकार की बात की कि यहां पर उद्योग-धन्धे खोलना चाहते हैं, लाइसेन्स लेना चाहते हैं । इस बारे में वहां कलेक्टर के सामने एप्रोच किया तो वहां से यही उत्तर मिला की हम इन्डस्ट्रीज़ के लिए इस प्रकार से जमीन नहीं दे सकते। हमारे यहां इन्डस्ट्रियल एरिया सरकार द्वारा घोषित नहीं किया है ; जब इस प्रकार का एरिया घोषित हो जायगा उसके बाद इन्डस्ट्रीज़ आदि के लिए जमीन दी जायगी । बड़े आश्चर्य की बात है कि जब इन्डस्ट्रीज़ खोलने के लिये जमीन मांगते हैं तो सरकार कहती है कि अभी तक इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित नहीं किया गया, दूसरी ओर स्टेट इम्प्रूवमेंट एक्ट के अन्तर्गत किसी दूसरी जमीन को देने का अधिकार नहीं । ऐसी परिस्थिति के अन्दर कोई यह चाहे कि इन्डस्ट्री खोली जाय तो इस प्रकार से उसको साधन नहीं मिलते । पहले इस बुनियादी चीज के लिये कि सब जगह इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया जाय उसके बिना प्रारम्भिक योजना भी पूरी नहीं होती कभी आपने औद्योगिक विकास के लिए इस प्रकार की बातें सोची हैं ? मैं मानता हूं माननीय मंत्री महोदय वाकई में इस मामले में काफी योग्य हैं । वे हमारे यहां आकर वहां की वस्तुस्थिति को देखें और यह देखें कि यहां पर किन किन प्रकार के उद्योगों की संभावनायें हैं। हमारे यहां अनेक चीजों की संभावनायें हैं। बीकानेर शहर के अन्दर काफी तादाद में दूध होता है । वहां डैयरीज़ अच्छी प्रकार से चल सकती हैं बिस्कुट फैक्टरी अच्छी चल सकती हैं । ग्वालियर में एक ही बिस्कुट फैक्टरी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है । अगर वहां बिस्कुट फैक्टरी खोली जाय तो उसके लिये गंगानगर का गेहूं जो भारतवर्ष में सबसे अच्छा गेहूं माना जाता वह भी आसानी से मिल सकता है, अच्छी से अच्छी चीजें वहां उपलब्ध हो सकती है; लेकिन आखिर सवाल आता है इसको करें कौन ? आज के पूंजीपतियों की स्थिति यह हो गई है, इन्कम टैक्स और दूसरे टैक्सेज़ के मामलों के कारण डर चुके हैं इसलिये वे तो खोलने की हिम्मत नहीं करते और सरकार भी इस ओर प्रयत्न नहीं करती । तो हमारे यहां बेकारी की समस्या जो है वह बढ़ती जायगी । आखिर हमें इस समस्या का हल करना चाहिये । अगर हम नहीं करेंगे तो बीकानेर शहर और आसपास के गांवों में कितनी एक्यूट यह बेकारी की समस्या है इसको आप जांच करके देख सकते हैं । अगर हमने उनके लिये किसी प्रकार के रोजगार की व्यवस्था नहीं की तो मैं समझता हूं इसका नतीजा यह होगा कि वहां बेकारों की संख्या बढ़ती ही जायगी । एक तो वहां हर साल अकाल पड़ता है और दूसरी तरफ वहां के लोगों के पास काम नहीं है । अगर वहां इन्डस्ट्रीज कुछ खुल जाती हैं तो उससे वहां के लोगों को काफी फायदा हो सकता है । मेरा तो यही निवेदन है कि जब तक हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही

Page No.60

(श्री मुरलीधर व्यास)

ज्यादा उद्योग धन्धे नहीं खोलते हैं तो बेकारी की समस्या और ज्यादा बढ़ती जायगी और जिस प्रकार हम योजना का विकास करना चाहते हैं वह भी नहीं हो सकेगा ।

दूसरा जो कटौती का मेरा प्रस्ताव है, उस पर मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता । भीलवाड़ा में मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स के बारे में और वहां की अव्यवस्था के बारे में विचार करने के लिये यह प्रस्ताव रखा है । मैंने इस सम्बन्ध में पहले भी कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये थे, लेकिन उस पर माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था कि वे गलत आंकड़े हैं । बात तो ब्यावर की कर जाते हैं और बताते हैं कि भीलवाड़ा के जो आंकड़े है वे गलत हैं । मैंने भी इस पर देखा कि हो सकता है कि मेरी इसमें कोई गलती हो । इसकी जानकारी मैंने दुबारा करवाई । मैं यह कह सकता हूँ कि भीलवाड़े के बारे में जो आंकड़े मैंने प्रस्तुत किये हैं वे गलत नहीं हैं । मुझे ऐसा भ्रम है कि आपके पास जो रिपोर्ट आई है वह गलत है । वहां पर तीन सौ आदमियों की छंटनी की गई । इसी के साथ साथ वीविंग और स्पिनिंग आदि जो पहले पर्सेन्टेज उत्पादन का था उसमें कमी हुई है, यार्ड्स के अन्दर कमी हुई है, बनियान वगैरह जो बनते हैं उनके उत्पादन में भी कमी हुई है ।

आप इसकी फिर से छानबीन करें । हो सकता है कहीं गलती हो ।

लाभ की बात आपने कही । ठीक है, ब्यावर ने लाभ की बात जरूर मालूम पड़ी । पर मेरे पास की रिपोर्ट के अनुसार लाभ तो कुदरतन ही मिल गया । जो आपके पास कॉटन पड़ा था उसकी रेटें बढ़ जाने से, उसे रेटों का लाभ कह सकते हैं, आपकी व्यवस्था से लाभ हुआ हो, ऐसा नहीं कह सकते ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मन्त्री) : जिस वक्त हमने चार्ज लिया उस वक्त न एक पैसे का कॉटन था न कपड़ा था ।

श्री मुरलीधर व्यास : ब्यावर में या भीलवाड़ा में ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : भीलवाड़ा में भी कुछ था तो तनख्वा चुकाने के लिये भी काफी नहीं था, हम तो मजदूरों को रोक रहे थे किसी तरह ।

श्री मुरलीधर व्यास : रूई खरीदी हुई थी क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं ।

श्री मुरलीधर व्यास : कुछ माल खरीदा हुआ था ?

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member will now please conclude.

श्री मुरलीधर व्यास : अब दो यूनियनें हों और उनमें से एक को ही प्रोमोशन न मिले, उनकी ही छंटनी हो और अच्छे काम करने वालों को यूनियन के कारण निकाला जावे और नये आदमी को भरती किया जावे तो आखिर यह टैक्निकल वर्क है । नये को आप रखेंगे तो उससे उत्पादन नहीं बढ़ेगा । अगर ऐसा हुआ हो तो आप इसकी भी जांच करें ताकि पुराने आदमी आपके उत्पादन बढ़ाने में मदद कर सकें ।

(श्री मुरलीधर व्यास)

इस सम्बन्ध में आपका ध्यान खींचता हूँ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री उपाध्यक्ष : चार आपके प्रस्ताव हैं और समय को देखते हुए आप चारों पर प्रकाश डालेंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द : मेरे चार कटौती के प्रस्तावों को एक साथ ही मैं प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सप्लाइज़ विभाग में इस किस्म की अव्यवस्था है कि किसी बात का पता ही नहीं लगता। कोई अपना क्लेम लेकर जावे तो वहां से कोई सूचना नहीं दी जाती। मैं यहां तक कहने को तैयार हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस विभाग में सन् ५० से कई लोगों के क्लेम्स बकाया हैं जो आज तक भी फाइनेलाइज़ नहीं किये जाते। क्या कारण है ? यह सब प्रशासन की अव्यवस्था के कारण है। ढांचे में अगर खराबी आती है तो सरकार की खराबी साफ जाहिर होती है। इसका परिणाम क्या होगा ? जनता को इसका खमियाजा भुगतना होगा। किसी बात का समय पर जवाब नहीं दिया जाता।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग-मंत्री) : यहां मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक सप्लाइज़ के क्लेम्स का सवाल है वह इन्डस्ट्री विभाग से ताल्लुक नहीं रखते। सिविल सप्लाइज़ विभाग कभी का वाइन्ड-अप किया जाकर क्लेम्स फाइनेन्स विभाग से डील होते हैं। ये पुराने हिसाबों से ताल्लुक रखते हैं और इसलिये कोई इन्डस्ट्री विभाग में चला गया हो तो मुमकिन है उसको जवाब नहीं मिल पाया हो इसी वजह से।

श्री लक्ष्मीचन्द : मेरे कट मोशन्स एक्सेप्ट हुए हैं इसी विभाग के नाम से।

श्री उपाध्यक्ष : You will speak. To whomsoever it concerns, they will reply. Continue your debdate.

श्री लक्ष्मीचन्द : जालोर के काफी क्लेम्स बकाया हैं। उनकी लिस्ट अगर मन्त्रीजी चाहें तो मैं उनको देने को तैयार हूँ। उनको समय पर जवाब तक नहीं दिया जाता।

एक ट्रक ड्राइवर था। उसको ५) रु० अलाउन्स के देने का एक नोटिफिकेशन ५४ में जारी किया गया। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसे पढ़ कर सुना दूं :

"A special pay of Rs. 50/-will be admissible to the truck drivers."

यह आज्ञा २२ सितम्बर, १९५४ को जारी की गई थी, जिसका इम्प्लीमेन्टेशन १ अप्रेल, ५० से किया जाना था। इसके अन्तर्गत जोधपुर डिविज़न में कितने ही ट्रक व ट्रैक्टर ड्राइवर्स थे वे आज दूसरे विभागों में चले गये हैं, पर उनके अलाउन्स के बारे में आज तक भी सरकार कुम्भकरण की नींद में सोई हुई है। कई उनमें से रिटायर हो गये, पर अलाउन्स नहीं दिया गया अभी तक। तो क्या उस नोटिफिकेशन को चाटा जावे या इसके अन्दर मसाला भर कर बाजार में बेचा

(श्री लक्ष्मीचन्द)

जावे ? इसका मतलब क्या ? प्रशासन के ढांचे में खराबी है। सरकारी हुक्मों का इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होता। इससे विभाग के कर्मचारियों के दिलों में भी यह वहम घर कर गया है कि न मालूम सरकार हमें एब्जोर्ब भी करेगी या नहीं। कइयों को इस विभाग के टूटने पर अन्य विभागों में रखा गया है और कुछ को इसमें रखा गया है पुराना एरियर का काम पूरा करने के लिये। उनके सामने यह परिस्थिति पैदा हो गई है कि न मालूम हमें किस वक्त निकाल दिया जावेगा। तो जब उनको इन्डस्ट्री में रखा है और १२—१३ सालों से काम कर रहे हैं तो मैं मन्त्रीजी से कहना चाहूँगा कि वे इस बारे में सदन के अन्दर इस प्रकार का विश्वास दिलावें कि उनको एब्ज़ोर्ब करेंगे और इनका फिक्सेशन सीनियोरिटी लिस्ट-डेट ऑफ अपोइन्टमेन्ट से मानेंगे। आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में? जब तक आप अपना दृष्टिकोण उनके मामले में स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक लोगों के दिलों में भावना रहेगी और भावना का सवाल भी है। हर एक आदमी पेट भर कर रोटी मांगता है और जब सरकार का काम करते हैं तो वे भी वैसा ही सरकार का काम करते हैं, उनके अधिकार भी उनको मिलने चाहिये। आप उनको सन्तोष नहीं देंगे तो उनका भी दिल नहीं बढ़ेगा। आखिर उनसे भी आपको काम लेना है। अकेला एन्जिन काम नहीं कर सकता, अगर एक भी पुर्जे में खराबी हो तो। आप इस पुर्जे की दुरुस्ती करें, नहीं तो एन्जिन भी ठप्प हो जावेगा, मशीन काम नहीं देगी।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, लोहे का कोटा हर जिले को अलॉट किया जाता है। मैं विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि जालोर जिले का कोटा हमारे जिले को पूरी तरह नहीं मिलता है। आखिर आपने यह कोटा किस क्राइटेरिया पर तय किया है? अगर पोपुलेशन के बेसिस पर किया है तो आप हमारा भी इसी बेसिस पर तैय करें और समय पर हमारा कोटा हमें दें। समय पर सप्लाई होता नहीं और होती भी है तो ऐसे मौके पर कि जिसकी सूचना हमें मिलती नहीं, क्लेक्टर के पास आती नहीं और दो महीने यों ही निकल जाते हैं और इस बीच दो महीने खत्म हुए नहीं कि व्यापारी उसे ब्लैक मार्केट में भेज देते हैं। एक तरीका आपने यह बता दिया कि दो महीने में अगर कोई खरीदेगा नहीं तो डीलर ब्लैक मार्केट में बेच सकता है। मैं स्पष्ट कर दूं कि लोगों की इतनी संख्या है मांगने वालों की कि अगर वितरण की ठीक व्यवस्था हो तो सारा माल एक दिन में बिक सकता है, दो महीने तो क्या पड़ा रहे, दो घंटे भी नहीं रह सकता, इतनी मांग है। तो आप पहले तो हमारा कोटा मुकर्रर करें। जन-संख्या के बेसिस पर अगर हमें कम मिलता है तो हम सन्तोष कर लेंगे कि हमारे जिले की पोपुलेशन कम है, पर वह कोटा समय पर पहुंचाया जावे और वितरण की समुचित व्यवस्था की जावे। ऐसा नहीं कि व्यापारी के पास सामान पहुंचा और क्लेक्टर के पास सूचना दो महीने बाद आए और तब तक व्यापारी दो महीने बीतते ही ब्लेक में बेच दे। जनता को समय पर सूचना नहीं मिलती और फिर उनको ब्लेक से खरीदना पड़ता है।

(२.०० म. प)

(श्री विशम्भरनाथ जोशी, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, जालोर जिले के उद्योग के बारे में किसी भी विभाग ने इसकी तरफ

Page No.63

(श्री लक्ष्मीचन्द)

आंख उठा कर नहीं देखा है। मैं यहां तक कहूँगा कि इस जिले के अन्दर कई उद्योग-धंधे पनप सकते हैं। मेरे सांचोर तहसील के अन्दर पहले एक्साइज़ विभाग के द्वारा सॉल्ट की आमदनी होती थी। अगर आज वहां पर सॉल्ट की कोई इन्डस्ट्री लगाई जाये तो हो सकता है उससे जनता का फायदा हो और उससे आपका उद्योग भी पनपेगा और सॉल्ट के जरिये काफी आमदनी हो सकती है और लोगों को रोटी भी मिल सकती है। दूसरे, वहां पर सब्जी भी पैदा हो सकती है, क्योंकि उस जमीन में खार है। काफी मैदान पड़ा हुआ है और वहां पर काफी जमीन बंजर पड़ी हुई है जहां पानी भरा हुआ है। अगर उस जगह नमक की या सब्जी की इन्डस्ट्री लगायें तो सभी को फायदा हो सकता है। आप वहां के लोगों को उत्साहित करें तो हो सकता है आपका उद्योग-धंधा पनप सके। वहां पर चमड़े की भी इन्डस्ट्री काफी सक्सेसफुल हो सकती है। मैं तो यहां तक उद्योग मंत्री महोदय से कहूँगा कि जब कभी उद्योगों के बारे में आप प्रदर्शनी लगायें तो भीनमाल और सांचोर की जूतियां, जो बहुत ही सुन्दर होती हैं उनको भी प्रदर्शनी में रखें और जूतियां बनाने वाले मोचियों को आप उत्साहित करने के लिए उनको लोन दें, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें और जितनी अच्छी अच्छी जूतियां हैं उनको विदेश या बाहर भेजने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था सरकार द्वारा करायें। सरकार का ध्यान अभी तक इस जिले की ओर नहीं गया है। यहां तक मैं कहूँगा कि जो उद्योग विभाग के डाइरेक्टर हैं वे पहले वहां पर कलेक्टर रह चुके हैं और उनको उस जिले से बहुत जानकारी है और वे पर्सनली कई चीजों के बारे में जानते हैं। एक एक विलेज उनका देखा हुआ है कि कौन कौन सी जगह कौन कौन से उद्योग पनप सकते हैं। मुझे आशा है कि सरकार ने आज दिन तक उद्योगों को पनपाने के लिए जो सहयोग नहीं दिया है अब वह विशेष सहयोग देकर उस जिले के उद्योग को पनपाने की कोशिश करेगी।

इन चारों बातों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे ४ कटौती के प्रस्ताव हैं। सबसे पहला कटौती का प्रस्ताव है लूणकरणसर में........

श्री सभापति : Only two cut-motions stand in your name.

श्री भीमसेन : सभापति महोदय, ४ कट-मोशन्स थे और शायद सेक्रेटेरियट में रह गये होंगे।

श्री सभापति : When were they given ?

श्री भीमसेन : दो-तीन दिन पहले दिये गये हैं।

श्री सभापति : They have not been circulated. You have to speak, therefore, only on those which have been circulated. I cannot permit others.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Whether those cut-motions were actually disallowed? If they were not disallowed they should have been circulated.

Page No.64

श्री सभापति : That is a matter which can be cleared up with the Secretariat.

श्री श्रीभानसिंह : That is not my duty to go to the Secretariat. It is the duty of the Secretariat to write to me if it has been rejected.

श्री सभापति : This motion does not relate to you......

श्री श्रीभानसिंह : I can also raise an objection because I may also be treated with the same attitude.

श्री सभापति : It does not relate to you...

श्री श्रीभानसिंह : This is a matter which concerns all and this sort of treatment may have been done to others as well...

श्री सभापति : Gentleman, you are trying to . . .

(व्यवधान)

श्री श्रीभानसिंह : May I request that there is no gentleman or gentle-lady here in this House?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : Is the Hon'ble member not a gentleman ?

श्री सभापति : If it has been circulated, you can move it.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योगमंत्री): मेरा ऐसा ख्याल है कि माननीय सदस्य को गलतफहमी मालूम होती है, वैसे यह सर्कुलेट हो गई हैं। इनके कटमोशन लिस्ट नं० ३ में हैं।

श्री पी.के.चौधरी (फुलेरा): Third list has not been circulated to the members. It is a serious matter. If a member gives a cut-motion in due time and within notice time and if that motion is not disallowed, the Secretariat is responsible for this...

श्री सभापति : Certainly.

श्री पी० के० चौधरी : So you must enquire whether the Hon'ble members motion has been rejected ? If it has been rejected the Hon'ble member cannot move. If it has not been rejected the Secrectariat is responsible for it and it must be enquired into and then the Hon'ble member should be allowed to move it.

श्री सभापति : You can move...

श्री पी० के० चौधरी : Then why they have not been circulated to us? These things happen again and again.

श्री सभापति : They will not happen in future. The Hon'ble member must feel...

श्री पी० के० चौधरी : We take a serious exception to it.

Page No.65

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि लिस्ट नम्बर ३ में इसके दो कटौती के प्रस्ताव और हैं। वह सर्कुलेट हो गई है

श्री पी० के० चौधरी : We have not received it. It might have been received by the Hon'ble Minister.]

श्री रिखबचन्द धारीवाल : You should bear that it has been circulated. Probably it is not named as list 3 but as 63.

श्री सभापति : So you may move them.

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : लिस्ट कहां सर्कुलेट हुई है ?

श्री सभापति : रह गई है, अब हो जायेगी सर्कुलेट

(व्यवधान)

Order ! Order !! It is a matter which should not be made a subject of discussion on the floor of this House. If this is an ommission on the part of the Secretariat it will not occur in future. The Hon'ble members should be rest assured and satisfied.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, मेरे द्वारा ४ कटौती प्रस्तावों की सूचना दी गई थी। लेकिन दो प्रस्ताव ही केवल सर्कुलेट किये गये हैं, बाकी के बारे में मैं अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहूँगा, अगर आप आज्ञा दें तो। लेकिन सबसे पहले मेरे दो प्रस्ताव हैं उनके सम्बन्ध में बोलना चाहूँगा।

सभापति महोदय, हमारा बीकानेर जिला खनिज उत्पादन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जिला है। वहां सबसे बड़ी जिप्सम की खान है और हिन्दुस्तान के सारे लोग जानते हैं कि हमारे यहां जिप्सम का भण्डार है और उससे जो बंगाल में फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है उसको फीड किया जाता है। इसके साथ ही साथ कोल, प्लास्टर ऑफ पेरिस और चाइना क्ले और इसी तरह के दूसरे पदार्थ हैं जिनके द्वारा हमारे जिले का विकास किया जा सकता है। सबसे पहले मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारे यहां पर सरकार द्वारा जिप्सम कम्पनी को मिनरल निकालने का ठेका दिया हुआ है। उनकी कन्डीशन में था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की इन्डस्ट्री स्थापित करेंगे और आज लीज़ दिये कई साल हो गए, पर कोई इन्डस्ट्री स्थापित नहीं की गई। सरकार ने इसके लिये कोई सक्रिय कदम भी नहीं उठाये। इसके द्वारा, मैं कटौती के प्रस्तावों द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि यह जो शर्त है लीज़ होल्डर्स के साथ उसकी पूर्ति कराई जाये जिससे वहां पर फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो सके और वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव लूणकरणसर में औद्योगीकरण में मन्द गति के सम्बन्ध में है। सभापति महोदय, अगर हम हिन्दुस्तान के दूसरे स्टेट्स के आंकड़ों को देखें तो उनसे मालूम होगा कि हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स का टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितना परिवर्तन हुआ है और

(श्री भीमसेन)

स्टेट्स का टैक्स स्ट्रक्चर जो टैक्स से आमदनी होती है उससे मालूम होता है कि किस तरह से दूसरी स्टेट्स किस गति से इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन की तरह बढ़ रही हैं। लेकिन हमारे राजस्थान की जो टैक्सों से आमदनी है उसको देखने से मालूम होता है कि हम पिछड़ी अवस्था में अब भी हैं। हमारे यहां सबसे मोटी रकम जो हमारे राज्य कोष को मिलती है वह लैंड रेवेन्यू से

(२. १०. म० प०)

(श्री निरंजनाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मिलती है। इससे मालूम होता है कि जो राज्य लैंड रेवेन्यू की इन्कम पर निर्भर करता है उसकी इकोनोमी को पिछड़ी हुई इकोनोमी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य की प्रगति के लिये यह आवश्यक है कि उसमें इन्डस्ट्रियलाइजेशन हो और जमीन पर जितना भार कम कर सकें उतना ही राज्य की प्रगति का द्योतक होगा। हमारे राजस्थान में जो कुल इन्कम होती है वह लैंड रेवेन्यू में सबसे हाई इन्कम होती है। टैक्स से जितनी इन्कम होती है उसका ५ प्रतिशत केवल लैंड रेवेन्यू से मिलता है और दूसरी स्टेट्स के फिगर्स देखें तो लैंड रेवेन्यू से होने वाली इन्कम दूसरी स्टेट्स में कहीं ३ प्रसेन्ट है, कहीं २ पर्सेन्ट है तो कहीं १ पर्सेन्ट ही है और राजस्थान में वह ५ पर्सेंट आती है सबसे हाइएस्ट। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप करने की काफी गुंजाइश है।

हमारे राजस्थान में पहले बिजली या पॉवर की बहुत कमी थी, लेकिन अब उसकी पूर्ति हो गई है और यह उम्मीद करनी चाहिये और सरकार को यह कोशिश करनी चाहिये कि हमारे यहां इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हो ताकि लोगों को अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट मिल सके।

कई माननीय सदस्यों ने खादी के बारे में बहुत सी बातें कहीं थीं; खादी संस्थाओं द्वारा उचित रुपये—पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है और कई लोगों ने मांग की थी कि सरकारी खर्चे से इस प्रकार की संस्थाएं चलाई जाती हैं उनको बंद करना चाहिये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, खादी संस्थाएं कैसी हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। इससे लाखों आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और यही एक ऐसी इन्डस्ट्री है जिससे हाइएस्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है और इसी तरह की संस्थाओं को राज्य द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाता है या ऋण देने की व्यवस्था की जाती है। तो मैं समझता हूं, यहां के ८० प्रतिशत आदमी जो कृषि पर निर्भर करते हैं और उनकी यह हालत है कि काफी लोगों को सीज़नल एम्प्लॉयमेंट मिलती है। चार महीनों तक उनके पास काम है, ८ महीनों तक वे बेकार बैठते हैं, ऐसे आदमियों को क्या आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं? मैं समझता हूँ, खादी से बढ़ कर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते।

आज बीकानेर या पश्चिमी राजस्थान में अकाल है। वहां पर ऊन की कताई का काम अच्छी तरह से होता है। यदि उनको यह काम दिया जाय और वित्तीय सहायता दी जाय तो ऊन की कताई से एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो खादी की बात कही गई

(श्री भीमसेन)

है वह उचित नहीं है। खादी से मिलने वाले एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए मैं समझता हूँ इसको जितना प्रोत्साहन दिया जाय वह दिया जाना चाहिये। यह दूसरी बात है कि यदि किसी संस्था द्वारा दुरुपयोग किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये।

इसके अलावा हमारे राज्य में टीन और सीमेन्ट की व्यवस्था के बारे में सभी ज़िलों का यह हाल है, खास करके बीकानेर में पिछले डेढ़ साल से टीन वहां के लोगों को नहीं दिये गये। सरकार की किस प्रकार की व्यवस्था है, यह समझ में नहीं आती। लेकिन लोगों की शिकायत है कि उनको टीन नहीं मिले, न काश्तकारों को और न इन्डस्ट्रीज़ को सप्लाई किया गया और सीमेन्ट के बारे में भी ऐसी ही व्यवस्था है कि लोगों को ठीक समय पर काम के लिये सीमेन्ट नहीं मिल पाती। यह सरकार के देखने की बात है कि टीन की सप्लाई और सीमेन्ट की सप्लाई ठीक तरह से मिले, जिससे उद्योग का विकास हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव रखता हूँ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे करीब एक दर्जन कटौती प्रस्ताव हैं, लेकिन उन पर बोलने के पहले मैं खादी के सम्बन्ध में दो-चार शब्द कहना चाहूँगा....

श्री उपाध्यक्ष: एक दर्जन कटौती प्रस्ताव हैं, पर समय नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, आज दो दिन से खादी और खादी संस्थाओं के खिलाफ एक प्रकार का क्रूसेड इस सदन में चल रहा है। सवाल यह पैदा होता है कि आया खादी के साथ या खादी संस्थाओं के साथ what is wrong with it और यदि कुछ रोंग नहीं है तो whether khadi has outlived its utility, यह सवाल मन में पैदा होता है। और तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि खादी जो है या खादी संस्थाएं हैं वे एक नोन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन हैं। उसके बारे में जब हम इस सदन में चर्चा करते हैं तो हम एक हद तक ही उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, इससे आगे नहीं कर सकते। मैं खादी संस्थाओं के डिटेल्ड वर्किंग के संबंध में यहां चर्चा करना उचित नहीं समझता। हम सदन में एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा करते हैं क्योंकि डिमान्ड मंजूर करते हैं, इसलिये उसकी चर्चा करने का अधिकार है। लेकिन वहां जाकर खादी संस्थाएं डिटेल्ड वर्किंग करती हैं उस पर चर्चा करना मैं समझता हूँ वह आउट-साइड लिमिट है।

दूसरी बात यह है कि इस सदन का जो फोरम है उसका जो उपयोग करते हैं उसका उद्देश्य कोई रहता है। उद्देश्य यह रहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई गलती हो तो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको टोन-अप करते हैं ताकि एग्ज़ीक्युटिव एलाइव हो जाय। पॉलिसी मैटर्स पर हम राय देते हैं और वह अगर पर्सुएडिंग हो, कन्विन्सिंग हो तो गवर्नमेन्ट उसके मुताबिक रूप बदलने की कोशिश करती है।

तीसरी बात के लिये जो सदन का उपयोग करते हैं वह पब्लिक ओपीनियन के लिये

(श्री पी. के. चौधरी)

सदन का उपयोग करते हैं। आज खादी के संबंध में दो दिन से बहस चल रही है। मुझे यह महसूस हो रहा है कि खादी आर्गेनाइजेशन के खिलाफ पब्लिक ओपीनियन क्रिएट हो जाय, ऐसा-वातावरण बना रहे हैं। जो माननीय सदस्य समर्थन करते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप इस बात के लिये कन्विन्स हो जावें कि इसकी युटिलिटी नहीं रही तो इसे छोड़ देना चाहिये, इसे प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये, खत्म होना चाहिये, फिर तो जो वातावरण या पब्लिक ओपीनियन बनाया वह बना सकते हैं, वाजिब है इसलिये बना सकते हैं। लेकिन जब यह स्वीकार करें कि खादी की आज भी युटिलिटी है, उससे इकोनोमीक है और टीम बातों में सजेशन देना है तो किसी सेक्रेटरी या किसी ट्रेजरार द्वारा यदि गलत काम होता है, हमको यह महसूस हो कि खादी की इकोनोमी गलत है, उसकी युटिलिटी नहीं है, अच्छा काम नहीं हो रहा है तो राय दें और वातावरण पैदा करें ताकि सरकार मदद करना छोड़ दे। जहां तक खादी का संबंध है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि Khadi was the livery of our freedm. इस जमाने में जो आज इस तरह से माननीय सदस्य सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं,लेकिन that was a Government sponnsored institution, लेकिन इस टाइम में हम इसे अपनी एक किस्म की लिवरी मानते हैं....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : It was the livery of the fourth class servants.

श्री पी० के० चौधरी : Prime Minister has told it very proudly.

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इकोनोमिस्ट्स हैं, वे आज इस बात को मानते हैं, माननीय सदस्य कहते हैं कि देश में अनएम्प्लायमेंट है, अन्डर एम्प्लायमेंट है। आज हमारी एग्रीकल्चर इकोनोमी है, वहां पर एग्रीकल्चर के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा छः महीने काम करते हैं और छः महीने आदमी को काम करने को नहीं रहता है, वह बेकार रहता है। उसका स्पेअर टाइम है, अनयूज्ड टाइम है, वह गोसिप में, गपशप में व्यर्थ करता है। इस समय के लिए खादी एक तरह का प्रोफेशन होता है, एक इन्स्ट्रमेंट होता है, जिसको समझ लें in addition to their income. तो इस तरह हमारे पास खादी को सब्स्टीट्यूट करने का, अगर खादी को खत्म कर दें, खादी संस्थाओं को खत्म कर दें, उसके बाद इस प्रकार का कोई जरिया नहीं है, कोई इन्डस्ट्री हमारे सामने नहीं है जिसको गांव गांव में पहुंचा सकें, घर घर में पहुंचा सकें और जिसके साथ लोग परिचित हों, होम का ट्रेडीशन हो; people know how to weave and spin in villages. आज जाकर उनको कोई टैक्निक या इन्स्ट्रूमेंट दिला कर काम में लेंगे तो मिलियन ऑफ पीपल्स के लिए यह पोसिबल नहीं है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, जो मेकेनाइज्ड इन्डस्ट्री है, जो स्पीनिंग मिल्स हैं, उसमें एक हजार आदमियों को एम्प्लॉय करके जितना कपड़ा बना सकते हैं, उसके अन्दर हम कम से कम टेन टाइम्स, फिफ्टीन टाइम्स ह्यूमन लेबर एम्प्लॉय कर सकते हैं। यह

(श्री पी. के. चौधरी)

खादी की इकोनोमिक्स होती है । इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो माननीय सदस्य इस पर क्रुसेडर स्प्रिट लेकर आक्रमण करते हैं, उसके अधिकारियों पर आक्रमण करते हैं, मैं समझता हूँ उनका आउट लुक रोंग है ।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूँ कि कोआॅपरेटिव सोसाइटी पर सदन में कई सवाल आते हैं, इस प्रकार के सवाल आते हैं किसी सोसाइटी में एम्बेजलमेंट हो गया, कोई कोआॅपरेटिव सोसाइटी बोगस बन गई, लेकिन वे कोआॅपरेटिव मूवमेंट को खराब नहीं कहते । हम मानते हैं कि हिन्दुस्तान के विकास के लिए Co-opeartive is a 'must' thing. जब इस बात को स्वीकार करते हैं, हम कोआॅपरेटिव मूवमेंट की खिलाफत नहीं करते हैं, हम उसके खिलाफ पब्लिक ओपीनियन क्रियेट नहीं करते, किसी कोआॅपरेटिव सोसाइटी के या किसी कोआॅपरेटिव डिपार्टमेंट के एक आॅफिसर में गलती है तो उस सारे मूवमेंट को गलत नहीं बताते; on the same analogy there are organisations in Khadi, उसमें पर्टिक्युलर आॅर्गेनाइजेशन, पर्टिक्युलर इन्डीविजुअल या किसी व्यक्ति की एरर आॅफ जस्टिस हो सकती है, एरर आॅफ एप्रोच हो सकता है, बोनाफाइडी लैप्स हो सकती है, उसके लिए मूवमेंट को हर्जाना दे देना, कल से पीछा करते रहना, खिलाफ वातावरण क्रियेट करते रहना, मैं मानता हूँ उचित नहीं होता है कि आप पीछा करते रहें । किसी को अटेक करने जाय तो उसका जो एटीट्यूड है it becomes an anti-national attitude. तो जो खादी की युटीलिटी है, जो इम्पोर्टेन्स है, खादी क्या चीज है, उसको देख नहीं पाते ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ । एक व्यक्ति गया था जंगल देखने के लिए, but he came back disappointed because he could not see the wood because of the trees. तो जो माननीय सदस्य खादी की चर्चा करते हैं, उसके खिलाफ वातावरण क्रियेट करते हैं their position is such. They had gone to see the wood but came back disappointed because they could not see the wood because of the trees. तो वे जब मोनोकॉल लगा कर देखते हैं I don't want to defend any individual.

उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आता हूँ अपने कट मोशन के ऊपर । सबसे पहले मैं इस डिपार्टमेंट के रीआॅर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ । वॉल्यूम दो में देखते हैं कि इस डिपार्टमेंट के कई हिस्से हैं। एक तो डाइरेक्शन एण्ड सुपरिन्टेंडेंस, दूसरा है इन्डस्ट्रियल एजुकेशन, एक है इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक है मिसलेनियस, एक है रीआॅर्गेनाइजेशन आॅफ कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ । इस प्रकार चार पांच हिस्से किये हैं और उनमें हर एक हेडिंग में मैं देखता हूँ कि कुछ सेन्टर्स गवर्नमेंट चलाती है, कोई कार्पेन्टरी का है, कोई ब्लेक स्मिथी का है, कोई किस प्रकार का सेन्टर है। जहां तक उनके रीआॅर्गेनाइजेशन का सवाल है उनका रीआॅर्गेनाइजेशन किस प्रकार होना चाहिए, यह देखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है; उसके सम्बन्ध में कि हम किस पर्पज़ के लिए रीआॅर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं, आया इस इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के काम के लिए रीआॅर्गेनाइजेशन to achieve the objective

Page No.70

(श्री पी. के. चौधरी)

किस वक्त रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो किसी प्रोब्लम को टेकल करने के लिए करते हैं। जैसे लड़ाई में जाना है, कहीं जाकर लड़ना है, दरिया में लड़ना है तो सबमेरिन देते हैं, एयर क्राफ्ट देते हैं और अगर पहाड़ पर जाकर लड़ना है तो उस तरह के साधन देते हैं। इस डिपार्टमेंट के रीऑर्गेनाइजेशन करने के पहले यह देखना है कि ऑब्जेक्टिव्ज़ से रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं, आया रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं कार्पेन्टरी चलाने के लिए, ब्लैक स्मिथी चलाने के लिए, फर्नीचर मेकिंग हाउस चलाने के लिए। इसका ढांचा एक तरह का होता है। अगर डिपार्टमेंट का रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, इस प्रान्त में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए तो उसका ढांचा दूसरे तरीके का हो सकता है। मुझे महसूस होता है, इसका स्ट्रक्चर देखते हुए, गवर्नमेंट के सामने डिपार्टमेंट का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्ज़ क्या है, फक्शन्स क्या हैं, उसका नक्शा दिमाग में साफ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि आप जैसा देखेंगे कि कई सेन्टर्स वे लोग चलाते हैं, वूल कार्डिंग एण्ड फिनिशिंग सेन्टर, सेन्ट्रल मार्केटिंग सेक्शन, सोडियम सल्फेट सेन्टर, सॉल्ट पीटर इन्डस्ट्रीज़ सेन्टर, फर्नीचर मेकिंग सेन्टर, कटलरी एन्ड पैरापेटिक सेन्टर, क्वालिटी मार्किंग, हैंडी क्राफ्ट सेन्टर-इस प्रकार अलग अलग सेन्टर्स हैं। मैं समझता हूँ, इतने ज्यादा सेन्टर्स चलाने की जरूरत नहीं है। इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट की जो सबसे बड़ी चीज़ है वह है कि प्रोपर वर्क किस इन्डस्ट्री से पूरा हो सकता है, पब्लिक सेक्टर से चलाने पर हो सकता है या अलग इन्डस्ट्री चला कर हो सकता है। जहां तक स्माल स्केल इन्डस्ट्री का सवाल है वह कार्पेन्टरी सेन्टर, ब्लेक स्मिथी सेन्टर, कार्ड बोर्ड टॉयेज सेन्टर्स, लेदर टेनिंग सेन्टर्स चलाने का काम उसमें नहीं होता। उसका एक्चुअल काम है कि जो लोग काम करते हैं उनको एडीशनल ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की है। वह अच्छा काम है, आपने अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन जो अलग अलग सेन्टर्स चलाते हैं, वह गलत तरीका है। ये सेन्टर्स चला कर आप लोगों को प्रोत्साहन नहीं दे सकते। इसकी तरक्की हो सकती है जब लोन एडवान्स किये जायं, डिज़ाइन जो करते हैं, उसके लिए गाइडेन्स हो। आपका फर्नीचर मेकिंग हाउस चलता है। फर्नीचर मेकिंग हाउस, उपाध्यक्ष महोदय, चलता है, वह डवेलपमेंट ऑफ स्माल एण्ड अदर इन्डस्ट्रीज़ इन कॉम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स में फर्नीचर मेकिंग हाउस चलता है, उसका हैड क्वार्टर है वह जयपुर में है। उसका ढांचा आप देखेंगे। उसमें डिप्टी डाइरेक्टर की ग्रेड का एक जनरल मैनेजर है। उसका स्टाफ कितना है? एक फोरमैन है, छः टैक्निशियन्स हैं, दो अपर डिवीज़नल क्लर्क्स हैं, और दो लोअर डिवीजनल क्लर्क्स हैं, इतना स्टाफ एक फर्नीचर मेकिंग सेन्टर में होता है, जिसका डिप्टी डाइरेक्टर की ग्रेड का, ५००-६०० की ग्रेड का जनरल मैनेजर रहता है, जिस तरह वैस्टर्न रेल्वे में जनरल मैनेजर होता है और टैक्निशियन ६ में से ५, ११०-५-१३५-१०-२२५ की ग्रेड के हैं। मैं समझता हूँ किसी भी सेन्टर, इस मेग्नीट्यूड के सेन्टर को चलाने के लिए ५००-६०० की ग्रेड के जनरल मैनेजर की जरूरत नहीं

(श्री पी. के. चौधरी)

पड़ती है। यह उनका रीऑर्गेनाइजेशन का ढांचा बता रहा हूँ।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली साल का ढांचा देखा क्योंकि इस साल उन्होंने कहा है कि यह जो कटौती की है, जो रिकमन्डेशन्स हैं, at the recommendations of the Committee set up for the re-organisation of the Department, उससे यह हुआ है। अब पिछली साल का मैंने उनके डिपार्टमेंट का ढांचा देखा। उसमें, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले दिन बतलाया था कि पिछली साल के मुकाबले में इस साल जोइन्ट डाइरेक्टर तीन तो ८००-१२०० की ग्रेड में हैं और दो १३००-१६०० की ग्रेड में हैं। चार जोइन्ट डाइरेक्टर बढ़ गये। इसी तरह से डिप्टी डाइरेक्टर ५००-६०० की ग्रेड में दो थे, वे अब छः हो गये। उनका काम धन्धा क्या है, उनके फंक्शन्स क्या हैं, यह समझ में नहीं आता।

सबसे मजाक की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, कि पिछली साल गोडाउन ऑफिसर था १९६०-६१ में, वह गोडाउन ऑफिसर १५०-१०-२५० की ग्रेड में था, वे चार ऑफिसर हो गये। अब जो फर्नीचर मेकिंग हाउस है इसका जो बिगिनिंग है उसको भी एग्ज़ामिन करें। इसकी स्थापना १९५९-६० में हुई थी। उस वक्त दो टेक्निशियन्स, एक यू. डी. सी. और एक एल. डी. सी. थे। नेक्स्ट ईयर १९६०-६१ में ५००-६०० की ग्रेड के जनरल मैनेजर की जरूरत पड़ गई। यह रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार प्लाटून ऑफ जोइन्ट डाइरेक्टर्स, प्लाटून ऑफ डिप्टी डाइरेक्टर्स की जरूरत नहीं है। We can run the Department with one Director and at the most with two Joint Directors or two Deputy Directors.

हर एक काम के लिये जो उन्होंने सेंक्शन किया है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्डस्ट्रीज़ में, मैं समझता हूँ सब आ सकता था। आपकी इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की फैक्ट्रीज़ के लिये एक पियोन रखा है। इससे इस डिपार्टमेंट का ढांचा मिलता है, फैक्ट्रीज़ के लिये एक पियान, फर्नीचर मेकिंग के लिये एक जनरल मैनेजर और वूल कार्डिंग को उनको खुद को चलाने की जरूरत मैं महसूस नहीं करता। ट्रेनिंग दे सकते हैं पर वूल कार्डिंग के लिये I don't think it is an efficient job.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की मिसाल देना चाहता हूँ। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वह सुबह ७ बजे से शाम को ७ बजे तक काम करता है और घर पर भी फाइलें ले जाता है; लेकिन he has no control over his subordinates. उसका नीचे के सबोर्डिनेन्ट्स पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। I do not call that administrator a good administrator. He may be working for day and night. दूसरा एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर है वह खुद कुछ भी काम नहीं करता, but he sees that all the people under him, they function properly, तो यह मिसाल है। I call that officer as a good administrator, जो यह निगाह रखता है कि उसके नीचे के

Page No.72

(श्री पी. के. चौधरी)

एस्टेब्लिशमेंट में सब अच्छा काम करते हैं ; he is a good administrator,' not the one who works for the whole day and allows his subordinates to loiter about.

तो इसी तरह से यह इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट वूल कार्डिंग करके your Government agencies will not be in a position to supply the needs of the State. तो आपका काम नहीं है वूल कार्डिंग करना; प्रोडक्टिंग क्राफ्टिंग सेंटर चलाना, फर्नीचर मेकिंग हाउस चलाना । आपका काम है देश में फर्नीचर मेकिंग क्राफ्टस डवेलप हों । इसके लिये जरूरी है कि उन लोगों के लिये फंड्स हों। प्राइवेट इन्डस्ट्रीज़, कम्पनीज़ चलाना चाहें तो उनको पैसे से मदद दें, लोन दें, क्राफ्ट की ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट चलाते हैं। इसके लिये मैं सराहना करता हूँ । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पहले रीऑर्गेनाइज़ेशन कमेटी थी उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं, दुबारा इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज़ करना चाहिये फैक्टरीज़ को बन्द करने के लिये, स्टाफ में कमी करने के लिये और डिप्टी डाइरेक्टर्स वगैरह के कट के लिये विचार करना चाहिये । इसके लिये एक कमेटी अपोइन्ट करके सब बातों पर विचार करना चाहिये। आज हमारे सामने सदन के माननीय सदस्यों के सामने कोई नक्शा नहीं है कि हमारे यहां क्या क्या इन्डस्ट्रीज़ हैं, पब्लिक के सामने Census of Manufacturing Industries Act के अन्तर्गत गवर्नमेंट के पास सारे स्टेटिस्टिक्स आते हैं, जितनी रजिस्टर्ड फैक्टरीज़ हैं उनका स्टेटमेंट आता है कि कितना उनका प्रोडक्शन है, कितनी खपत है, किस किस तरह का माल तैयार किया जाता है, कहां कहां उसकी कितनी कितनी खपत होती है, every year they send a statement. उनके यहां कितने Labourers हैं, कितना प्रोडक्शन, सेल, कन्ज्यूमर्स हैं, ये सारे स्टेटमेंट आते हैं, वे हमारे पास नहीं आते हैं । ६ साल से वे स्टेटमेंट गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं, पर सरकार पब्लिश नहीं करती है, इसका कोई नकशा हमारे पास नहीं है । इन्डस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिये मेन्युफैक्चरिंग इन्डस्ट्रीज़ की रिपोर्ट आपके सामने आती है. उसको पब्लिश करना चाहिये कि इतनी रजिस्टर्ड फैक्टरीज़ हैं, इस प्रकार का उनका प्रोडक्शन है ।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कन्ज्यूमर्स गुड्स हैं, उनके लिये राजस्थान में किस किस की डिमान्ड किस किस जगह है, इन सब की जांच करके इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को पब्लिश करवा कर पब्लिक और सदन के माननीय सदस्यों को अवेलेबल कराना चाहिये। That is the proper work of the Industries Department and not the furniture making or any other manufacture.

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, अब मेरी डिमान्ड पर आ जाता हूँ । इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य रखूंगा, मन्त्री महोदय उस पर विचार करेंगे । सांभर सोडा एश की फैक्ट्री के सम्बन्ध में विचार करें । पांच, चार करोड़ रुपया उस पर खर्च करना पड़ेगा । हिन्दुस्तान सोडा एश कम्पनी बनाई है । एक करोड़ रुपया खर्च करके भी उसका कोई असर नहीं हुआ है । उससे कोई मतलब हल नहीं होगा । तो यह सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवानी चाहिये ।

Page No.73

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (डूडू) : डॉ० गोडबोले की बनाई हुई रिपोर्ट तैयार है ।

श्री पी. के. चौधरी : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि रिपोर्ट तैयार है तो बहुत अच्छी बात है ।

स्टील प्लान्ट्स के लिये रखा है । मद्रास में जो शेल्ड स्टील प्लान्ट है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के इन्डस्ट्रियल सर्वे के लिये २ साल से मांग कर रहा हूँ, क्योंकि जयपुर डिविज़न की पिक्यूलेरिटी है कि यहां एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का स्कोप नहीं है, क्योंकि यहां ट्यूब वैल वगैरह की स्कीम्स कामयाब नहीं हो सकतीं....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

One minute more, Sir.

पॉवर हाउस के सम्बन्ध में मेरा फर्स्ट कट मोशन था । उसके बारे में २ पॉवर लूम्स का है । चम्बल की बिजली गांवों में देना है, पर लोग शिकायत कर रहे थे कि बिजली आई है पर डिमान्ड पूरी नहीं हो रही है । There is not sufficient demand in the local area. तो पॉवर लूम्स का ट्रेडिशन है उसको लोग समझे हुए हैं, तो पॉवर लूम्स का दो का रखा है यह ठीक नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीभानसिंह ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : My name is first in the order.

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry, it will be taken after Shri Sribhan Singh concludes.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : His name is not legible.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरे कट मोशन्स हैं, उनमें से एक पहला मेरे माननीय सदस्य का पुनर्गठन पर है और मैं सदन का ज्यादा समय पुनर्गठन पर न लेकर, क्योंकि अभी माननीय सदस्य जो फुलेरा से आते हैं, उन्होंने काफी विस्तार में इस पर प्रकाश डाला है और जैसे कि माननीय सदस्य कहते हैं कि मेरी मेहनत भी उन्होंने कुछ खराब कर दी । फिर भी माननीय सदस्य ने बताया उसमें यह नहीं कहा कि रीऑर्गेनाइज़ेशन के अन्दर इस डिपार्टमेंट को एक टोप हेवी डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है और मेरी यह मान्यता है कि इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट का ज्यादातर फील्ड वर्क है । जब हम फील्ड वर्कर्स को ही कम कर देंगे तो ऑफिस में बैठे हुए ५ जोइन्ट डाइरेक्टर्स, चार डिप्टी डाइरेक्टर्स और एक डाइरेक्टर क्या उद्योग के लिये प्रगति राजस्थान में कर सकते हैं, सिवाय कागजों के ? मैं यह भी कहूँ कि अब तक जो इस डिपार्टमेंट की हालत रही है, उसको हम कह सकते हैं कि यह डिपार्टमेंट के अन्दर एक मेस रहा है और वह मेस रिफलेक्टेड रहा है । राजस्थान में जो इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ वह इस विभाग की इस बात की तारीफ करता है कि उसने अब तक कोई कार्य नहीं किया और फिर भी नहीं कर सकता; क्योंकि जिन व्यक्तियों को जिस जगह लगाना चाहिये था, जिन व्यक्तियों को काम सौंपना चाहिये था

(श्री श्रीमानसिंह)

उनको वह काम नहीं दिया गया। मैं जानना चाहूँगा कि इसके क्या कारण हैं? जैसे कि एक जोइन्ट डाइरेक्टर हैं भूटानी हैं, और मैं उनकी प्रगति को इसलिये दिलचस्पी से देख रहा हूँ कि जिस समय माननीय मंत्री उपमंत्री थे तब उन्होंने सदन में आश्वासन दिया था कि डिप्टी डाइरेक्टर हैन्डलूम लूम्स और हैन्डीक्रैफ्ट एक्सपर्ट को रखेंगे। उसके बाद उन्होंने पोस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन से एडवर्टाइज़ कराई। मगर इससे पहले कि पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई पोस्ट का एडवर्टाइज़मेंट हो और पोस्ट पर किसी का नाम आए इसके पहले ही इनको एज़ जोइन्ट डाइरेक्टर प्रोमोट कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि सदन में आश्वासन क्यों दिये जाते हैं और फिर क्यों बदले जाते हैं? जो व्यक्ति टैक्निकल एक्सपर्ट नहीं उसको क्यों रखा जाता है? जैसा कि अभी बताया कि ८०० से १२०० के ग्रेड में उनको रख दिया है।

यही नहीं, पहले हमको इस बात को देखना होगा कि वे पहले किस लाइन पर थे और ओरीजिनल किस सर्विस में आये? वे सी. पी. ओ. बन कर आये थे। वे आर. ए. एस. केडर के थे और आर. ए. एस. में भी सबसे जूनियर थे। अब ऐसा सुना जाता है कि वे आई. ए. एस. हो गये हैं। आई. ए. एस. का टैक्निकल वर्क से कोई सम्बन्ध नहीं। वे एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक हो सकते हैं लेकिन टैक्निकल और हैन्डीक्रैफ्ट का जहां तक प्रश्न है आई. ए. एस. से कोई मतलब नहीं है। जब वे सी. पी. ओ. से यहां आये तो उनको ७५) रुपये एलाउन्स दिये गये, जब डिप्टी डाइरेक्टर बनाया उनको तो १००)रु. एलाउन्स के दिये और जब पब्लिक सर्विस कमीशन में पोस्ट एडवर्टाइज़ करने के लिये लिखा तो उनको जोइन्ट डाइरेक्टर बनाया और १५०)रु. एलाउन्स के मिल रहे हैं। एक तरफ हम इकोनॉमिक कट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम एक व्यक्ति को ७५) रुपये पहले जो एलाउन्स मिलता था और जो नॉन टैक्निकल मैन है उनको ८०० से १२०० के ग्रेड में रख कर १५०) रु. एलाउन्स तक देते हैं। यही कारण है कि राजस्थान के इन्डस्ट्रीज़ विभाग के लिये मैं कॉन्फीडेन्टली कह सकता हूँ कि कोई कार्य नहीं हो सकता और नहीं होगा। एक केस हो तो इग्नोर कर सकते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि वर्सेटाइल जीनियस (vesatile genius) हो तो उसको प्रोमोशन दिया जावे।

एक ऑफिसर को जब हम अमेरिका भेजते हैं और जिसका जिक्र फर्नीचर में किया गया है, इसलिये टैक्निकल में आता है और ओरीजिनली उनको देखा जाये तो वह सुप्रिन्टेन्डेन्ट कॉटेज़ इन्डस्ट्रीज ग्रेड २०० से ४०० में थे। जब वे क्वालिफाई करके लौटे हैन्डीक्रैफ्ट में उसको ऑफिसर बनाया और डिपार्टमेंट ने उसका ग्रेड ३०० से ६०० का कर दिया। यह भी काम टैक्नोलोजी में आता है। अगर वूल में कोई जगह नहीं थी तो उसको हैन्डीक्रैफ्ट में लगाना चाहिये था वह वहां फिट हो सकता था। फिर उनको जनरल मैनेजर फर्नीचर वर्कशोप में ग्रेड ५०० से ६०० का किया। आज जिस समय कटौती करते हैं, उस समय एक व्यक्ति को जिसका ओरीजिनल ग्रेड देखें तो उसे आप ५०० से ६०० के ग्रेड में प्रोमोशन देते हैं। आज

(श्री श्रीभानसिंह)

उनसे यह पूछा जाए कि उन्होंने कितने फर्नीचर बनाये, कितने न्यू डिज़ाइन के फर्नीचर बनाये; तो जैसा माननीय सदस्य, डॉ. बहादुरसिंह, ने बताया कि अमेरिका से फर्नीचर्स डिज़ाइन की एक किताब आती है उसमें से, अगर कोई बनाये भी होंगे तो बनाये होंगे। उनमें नये डिज़ाइन के फर्नीचर्स बनाने की योग्यता नहीं है। मगर सरकार ने फिर भी उनको प्रोमोशन दिया और ५०० से ९०० का ग्रेड किया। फिर हम कहते हैं कि क्लॉस फोर्थ में ९ लाख की कटौती करेंगे।

इसके अलावा मैं यह कहूँगा कि एक ए. डी. आई. वूल है। उसका पोस्टिंग कहां होता है? उसका पोस्टिंग किया जाता है कोटा में, क्योंकि कोटा ही वूल का सबसे बड़ा सेन्टर है और राजस्थान के स्टेटिस्टिक्स के आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। राजस्थान की जितनी वूल कोटा में होती है दूसरी जगह नहीं होती है या कोटा में उसके लिये जितनी मशीनरी है उतनी दूसरे स्थानों पर नहीं है, जोधपुर और बीकानेर में नहीं है। इन्डस्ट्रीज़ के मिनिस्टर महोदय को मालूम है कि सबसे ज्यादा ऊन कोटा में होती है। ऐसी बात नहीं, लेकिन सबसे जूनियर इन्सपेक्टर को ए.डी. आई. वूल बनाना था इसलिये बनाया। आज तक तो हम यह सुनते आये थे कि बीकानेर में सबसे ज्यादा ऊन होती है। मगर चूंकि उनको लगाना था इसलिये उसको ए.डी. आई. वूल बना कर कोटा लगा दिया। इस तरह के मामले एक नहीं, कई हैं।

एक लैदर एक्सपर्ट का मामला आया। उनकी जो पहले ओरीजिनल पोस्ट थी वह सुपरवाइज़र लैदर की थी और वे १२० से २०० के ग्रेड में थे। उनको ट्रेनिंग में भेजा गया। अच्छा हो कि यह उद्योग भी राजस्थान में पनपे। मगर जब वे लौट कर आये तो उनको ए. डी. सी. प्रोजेक्ट्स बनाया और १० एडवान्स इन्क्रीमेन्ट्स दिये। मुझे कोई एतराज नहीं, अगर राजस्थान का एक्सचेकर इतना मालदार है कि वह १० एडवान्स इन्क्रीमेंट्स दे सकें तो दें। मगर एक तरफ आप कटौती कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार को १०–१० एडवान्स इन्क्रीमेंट्स देते हैं। फिर उनका अपोइन्टमेंट भी हुआ तो in the grade of 500-900. १२० से २०० का उनका पहले ग्रेड था उससे ५०० से ९०० के ग्रेड में आप एपोइन्टमेंट देते हैं। अगर उनसे टर्न ओवर ऑफ वर्क के लिये पूछें तो आपको मालूम होगा कि टर्न ओवर ऑफ दी वर्क वही १२० से २०० के ग्रेड में थे वही अब भी है। वर्क के आउट टर्न के लिये कोई नहीं पूछता, लेकिन हमको ग्रेड देना था दे दिया। अगर इसी तरह से काम करते रहे तो मेरा तो नम्र निवेदन है कि इस री–ऑर्गेनाइज़ेशन को बन्द कर दिया जावे। इसका बहाना लेकर फोर्थ क्लॉस सर्वेन्ट्स को मत हटाइये। आप टोप हेवी एडमिनिस्ट्रेशन इन्डस्ट्री का कर सकते हैं तो करें। मगर मैं यह बताना चाहता हूं कि जो आदमी जिसमें क्वालिफाइड है उसको उसी टैक्निकल पोस्ट पर ठीक तरह से लगाने की व्यवस्था करेंगे तो आपका काम ठीक तरह से चलेगा, अन्यथा इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट का काम चलने का है नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आता हूँ एक बात पर। पहले मैं दो–एक मिनट में इस बात को

(श्री श्रीमानसिंह)

डिस्पोज़ ऑफ कर देना चाहता हूँ। पहले कहते थे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कमी सीमेन्ट की है। चूंकि माननीय मुख्य मन्त्रीजी यहां बिराजे हुए हैं, मुझे याद है कि किसी साल में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि ६०—७० लाख रुपया सीमेन्ट फैक्टरी सवाई माधोपुर को दिया गया क्योंकि राजस्थान में सवाई माधोपुर में जो सीमेन्ट फैक्टरी है वह एशिया की बिगेस्ट सीमेन्ट फैक्टरी वहां लगी है। आज मुझे दुःख होता है यह कहते हुए कि वह एशिया की बिगेस्ट सीमेन्ट फैक्टरी एशिया की है तो क्या हिन्दुस्तान की भी जरूरत को पूरा नहीं कर सकी, राजस्थान का भी पूरा नहीं पड़ रहा है। उस सीमेन्ट फैक्टरी को ६० लाख रुपया दे दिया। वह राजस्थान की सीमेन्ट की डिमान्ड को भी फीड नहीं कर सकी। किस वजह से प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, प्रगति नहीं कर रही है ? राजस्थान की जनता की मांग पूरी क्यों नहीं होती है ? यदि मांग पूरी कर रही है सरकार तो डिस्ट्रिब्युशन में गड़बड़ी होगी। लेकिन आज ओपन मार्केट में सीमेन्ट नहीं मिलता। इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट में सीमेन्ट है, जिसको दिया जाता है राजस्थान इन्डस्ट्रियल वर्क्स के लिए। मगर अब तो राजस्थान के इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट ने एक काम और ले लिया है कि इन्डस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देने के लिए वह उनको सीमेन्ट न दे, हाउसेज़ के लिए वह सीमेन्ट न दे, शेड्स बनाने के लिए इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट अलॉट नहीं करेगा, लेकिन जो अगर गोलेछा और अनिल मोटर्स को राजस्थान और जयपुर में सिनेमा बनाने हों तो १००—८० टन सीमेन्ट अलॉट कर दिया जावेगा इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट की तरफ से। मुझे समझ में नहीं आता है कि सिनेमा ऐसी कौनसी एसेन्शियल इन्डस्ट्री है कि उसको इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट सीमेन्ट अलॉट कर देता है। शायद मैं गलत भी होऊं कि अभी उसको मंजूर न किया हो, लेकिन इन दी प्रोसेस ऑफ रिकमन्डेशन तो जरूर है और इन्डस्ट्रीज़ सेक्रेटरी महोदय ने यह लिखा है कि अलॉट कर दिया जाय। मुझे ताज्जुब होता है कि इन्डस्ट्रीज़ के पर्पज़ के लिए यदि सीमेन्ट चाहिये तो इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट अलॉट नहीं करता है, ऑर्डर कर देता है कि अलॉट न हो लेकिन सिनेमाज़ के लिए सीमेन्ट इश्यू हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक एसेन्शियल सर्टिफिकेट का मामला आता है और वह ऐसा है कि सदन को भी मालूम है कि सर्टिफिकेट गलत इश्यू हो जाते हैं और गलत इश्यू हो जाने के बाद यह जरूरी नहीं है कि वह आदमी कोटा लेकर चाहे उसका सामान बनाये या नहीं। मगर मेरे को अभी तक यह समझ में नहीं आया कि आखिर सर्टिफिकेट इश्यू करने के बाद यह नहीं देखा जाता है कमी की पार्टीज़ की क्या स्टेन्डिंग हैं, क्यों चाहिये और किस तरह का सर्टिफिकेट उसको चाहिये ? इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में एक दफा माननीय सदस्य जो जनसंघ के हैं, उन्होंने कोई शारदा इन्डस्ट्रीज़ का प्रश्न यहां पर उठाया था और शारदा इन्डस्ट्रीज़ को कोई ३३ लाख का ई. सी. इश्यू कर दिया गया था। मारे राजस्थान के ई. सीज़ मांगने वाले थे उनको नहीं हुआ और कहते हैं कि एक व्यक्ति को इश्यू हो गया। उनकी मशीनरी जितनी होनी चाहिये और अन्य जो टर्म्स एन्ड कन्डीशन्स

(श्री श्रीमानसिंह)

प्रेस्काइब कर रखी थीं, वे सारी की सारी टर्म्स एन्ड कन्डीशन्स कागजों में ही रह गई। क्यों इश्यू हुआ ? हो सकता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो, लेकिन मैंने सुना यह था कि इन्डस्ट्रीज़ सेक्रेटरी जो थे, उन्होंने स्पेश्यली जो यह चीज़ इश्यू करते थे उनको लैटर लिखा कि उनके केस को फेवरेबली कन्सीडर किया जाय। जब सेक्रेटरी यह लैटर लिख देता है कि उनके केस को फेवरेबली कन्सीडर किया जाय तो फिर नीचे के ऑफिसर्स की क्या हिम्मत हो सकती है कि इश्यू न करें ? कुछ नहीं, ३०–४० लेक्स का ई० सी० इश्यू कर दिया।

एक माननीय सदस्य : कौन सेक्रेटरी थे ?

श्री श्रीमानसिंह : यह तो आप जान लें।

वह राजस्थान की पार्टी नहीं; कलकत्ता की पार्टी है। उसको ३६ लैक्स का ई. सी. इश्यू किस प्रकार हुआ ? क्या राजस्थान में कोई भी इन्डस्ट्रियलिस्ट नहीं था कि जो ३६ लैक्स का ई. सी. नहीं चाहता होगा ? लेकिन वह हुआ है और उस टाइम पर शायद मन्त्री महोदय ने स्क्रुटिनी कमेटी बैठाकर उसको केन्सल कर दिया। यह होने पर भी इन्डस्ट्रिल एरिया झोटवाड़ा में कायम किया है, ३६ लैक्स का ई. सी. इशू कर दिया। लैंड किस तरह से पर्चेज करते हैं और किस तरह से उसको कन्वर्ट करा दिया जाता है ? एग्रीकल्चर लैंड थी उसको इन्डस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट कराया गया। पांच साल तक जब तक काश्तकारी न कर ले, खातेदारी राइट्स एक्र नहीं होते हैं, उसको पर्चेज़ कर लिया गया, कन्वर्ट भी कराया गया और वहां बिल्डिंग्स खड़ी हो गई। ई. सी. इश्यू हो गया, शायद स्क्रुटिनी न हुई हो।

इसी तरह से एक सिवायका इन्डस्ट्रीज़ का है। उनको कोपरा एन्ड टेलो का ई. सी. इश्यू हो गया। गुड्स की डिलीवरी ले ली, मशीनरी आई नहीं। डिलीवरी इश्यू होने के बाद मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या सकता है सिवाय ब्लैक मार्केट करने के ? इन्होंने राजस्थान सरकार को यह अन्डरटेकिंग्स दीं कि उनकी तीन-चार इन्डस्ट्रीज़ दूसरी जगह लग रही हैं उनमें से वे एक की मशीनरी लाकर लगा देंगे और इसी अन्डरटेकिंग्ज़ पर उनको ई० सी० मिल गया। इतने इन्डस्ट्रीस डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स हैं, टैक्निकल एक्सपर्ट्स बैठे हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि चार मशीनरीज़ स्टेट में लगी हुई हैं तो उन जगहों पर उनके लिए वे रॉ मेटिरियल ड्रॉ कर रहे होंगे, जहां उनकी इफरात होगी। उनमें से एक मशीनरी लगायेंगे तो लायेंगे कैसे ? एक को रिड्यूस करके लावें और चार का रॉ मेटीरियल वहां ले रहे थे, बना हुआ था, अब पांच के लिए रॉ मेटिरियल लेंगे। जब कि चार ही हैं। यह क्लियर कट ब्लैक मार्केट का केस है। उनकी रिकमन्डेशन हो गई सेक्रेटरी के लैटर पर। टैक्निकल एक्सपर्ट्स का भी कमाल है। वे आउट ऑफ वे जाकर करना चाहते हैं। यही मि० सिवायका हैं। ये चाहते थे कि इन्डस्ट्रियल शेड लगे वहां पर। एप्लीकेशन

(श्री श्रीभानसिंह)

दी होगी बाद में जब कि पहले ही अलॉट हो गया। माइका कन्डूस पाइप के नाम पर एप्लीकेशन दी। शेड एलॉट हो गया। मैं जानना चाहता हूँ कि यह माइका कन्डूस पाइप की क्या इन्डस्ट्री हो सकती है? कन्डूस पाइप इन्डस्ट्री तो होती है। मैं ले-मैन हूँ, जानता नहीं हूँ कि माइका कंडूस पाइप की कोई इन्डस्ट्री हो सकती है, जिसके लिए शेड मंजूर किया गया है इन्डस्ट्रियल एरियां में।

एक हैं मि० सोमानी। २५ हजार का बर्नर्स काल इसेन्स दिया गया इसलिए कि हीटर्स बनायेंगे। ई० सी० इश्यू हो गया। बर्नर्स राजस्थान में आये नहीं और हीटर्स भी आज तक नहीं बने। इस तरह की कार्यवाही इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट के अधिकारी लोग कर रहे हैं, ई० सीज़० इस तरह इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट रात के समय इश्यू कर रहा है। हो सकता है कि इसका स्टेट के एक्सचेकर पर भार न पड़ता हो। पर्सनल एक्सचेकर हो सकता है, जिन ऑफिसर्स ने इश्यू किये हैं। हमें इसके साथ यह ध्यान रखना होगा कि आखिर इसका भार गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के ऊपर पड़ता है, देश की वित्तीय स्थिति पर पड़ता है, क्योंकि आखिर फॉरिन एक्सचेन्ज का प्रश्न आता है और आपकी रिकमन्डेशन पर फॉरिन एक्सचेन्ज देना पड़ता है। ये चीजें देते जावेंगे और रॉ-मेटीरियल्स मंगाते चले जावेंगे और उनकी चीजें बनेंगी नहीं और ब्लैक मार्केट होता जावेगा तो किस तरह से प्रगति कर रहे हैं, यह सोचना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अगर यह होता कि इन पार्टीज़ को, यह सब नॉलेज में होते हुए भी ब्लैक मार्केट करते हैं, चीजें उनके द्वारा ब्लैक में चली जाती हैं, राजस्थान में उनको फर्दर ई० सीज़० इश्यू नहीं किये जावेंगे, ऐसा हो जाता तो इस बात के लिए सदन और राजस्थान के आदमी प्रसन्न होते। अभी अभी तीन तीन आदमियों को, जिनमें से एक श्री सोमानी हैं, तीन लाख का फिर ई० सी० इश्यू कर दिया। उनको तीन लाख का रिकमन्ड कर दिया है और बाकी ३७ आदमियों को ६ लाख का किया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि ३७ आदमियों को तो ६ लाख का ई० सी० इश्यू किया और एक को तीन लाख का, जो व्यक्ति कन्फार्ड ब्लैक मार्केटियर्स हैं और जिनमें से एक सोमानी भी हैं, उनको तीन लाख का रिकमन्ड कर दिया। क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? ये चीजें क्यों ओवर लुक की जाती हैं, मैं नहीं जानता।

इसका उत्तर तो माननीय मंत्री महोदय देंगे। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय भी घंटी बजाने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मन ही मन सोच रहा हूँ।

(३.०० म० प०)

श्री श्रीभानसिंह : You will appreciate my reading, Sir.

अन्त में मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूँ। इसी सदन के माननीय सदस्य श्री अनूपसिंहजी ने एक प्रश्न पूछा था

(श्री श्रीभानसिंह)

मिल्क पाउडर के बारे में। मैं उस सम्बन्ध में कुछ कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मिल्क पाउडर का जो प्रश्न आया था वहां एक अजमेर की कोई कम्पनी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अजमेर की कोई कम्पनी नहीं, वहां तो ब्लैक मार्केट करते हुए पकड़े गये।

श्री उपाध्यक्ष : He is in better possession of the facts.

श्री श्रीभानसिंह : वहां कम्पनी नहीं होगी, लेकिन वहां से ले जाते हुए पकड़े गये थे। उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर के अन्दर ओरीजिनल कम्पनी, यह उनका नाम है, अजमेर में जिनको बेचा था। इसका जो अलॉटमेंट होता है वह इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। अलॉटमेंट हुआ २६ हजार और ४० हजार का; उनको जो अलॉट हुआ उसका ब्लैक मार्केटिंग करते हुए अजमेर में पकड़ा है, यह ठीक है। मगर एक मिस्टर 'झुंझुनू वाला' है, इनको हुआ ४०० टन मिल्क पाउडर। किस जगह के लिए हुआ, यह तो माननीय मंत्री महोदय, बतायेंगे। कम से कम मैं इतना ही कह सकता हूँ, यह जो मिल्क पाउडर का अलॉटमेंट तीन पार्टीज़ को हुआ वह ब्लैक मार्केट करने के लिए हुआ। एक तो एवर ग्रीन ट्रेडर्स कम्पनी है जो देहली की है, राजस्थान में मिल्क पाउडर के डिस्ट्रिब्यूशन के लिए देहली की कम्पनी को मिल्क पाउडर का अलॉटमेंट होता है। राजस्थान में मिल्क पाउडर लेने के लिये कोई तैयार नहीं था क्या? लेकिन जैसा सुनते हैं मिल्क पाउडर का ब्लैक करने वालों की क्या राजस्थान में कमी थी? कह नहीं सकता कि यह देहली की कम्पनी को क्यों दिया गया?

श्री उपाध्यक्ष : As amongst the black marketeers, preference ought to have been given to the blackmarketeers of Rajasthan over other blackmarketeers.

श्री श्रीभानसिंह : I have already named those persons who have drawn the E. C. here. What they were doing? They are doing blackmarketing, nothing else.

उपाध्यक्ष महोदय, वे हैं पूरणचन्द्र सूद जो इसी एवर ग्रीन ट्रेडर्स के हैं। इनको शायद १०० टन मिल्क पाउडर अलॉट हुआ था और शायद वे एक पार्टी को देते हुये अकोला के अन्दर पकड़े गये। अकोला के अन्दर पकड़े जाने के बाद सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने लिखा कि जिन जिन पार्टीज़ को अलॉट किया गया और जिन्होंने ब्लैक मार्केट किया है उनको राजस्थान गवर्नमेंट प्रोसीक्यूट करे। राजस्थान के अन्दर मैं इस बात का दुर्भाग्य समझता हूँ कि एक अफसर ने इनको पकड़ा, उसने अपनी ईमानदारी का सुबूत दिया जब कि इस चीज़ में सेन्ट परसेन्ट ब्लैक हो रहा है। वैसी हालत में एक अधिकारी ने एक पार्टी को पकड़ा। उस समय वह पार्टी न मालूम कितना उसको देने को तैयार हुई होगी, लेकिन उन सर्कमस्टान्सेज़ के अन्दर भी उसको पकड़ा। उस अफसर की तारीफ की जानी चाहिये। मगर यह जो पार्टी है जिसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इसको प्रोसीक्यूट किया

(श्री श्रीमानसिंह)

जाना चाहिये, लेकिन होता क्या है कि इसका जो अलॉटमेंट हुआ था मिल्क पाउडर का उसकी डिलीवरी आई नहीं, यह सुनते हैं। उसने मद्रास में ही उसकी डिलीवरी ले ली या बम्बई में डिलीवरी ले ली और वहीं डिस्पोज़ ऑफ कर दिया। इस सम्बन्ध में जब राजस्थान सरकार को अधिकार है कि वह अपना डिस्क्रीशन यूज़ करके किसी को अलॉट कर सकती है, लेकिन इसमें ऐसा मालूम पड़ता है उन्होंने अपना डिस्क्रीशन यूज़ नहीं किया। जहां तक मेरी सूचना है इस कम्पनी को ब्लैक लिस्ट में लेना चाहिये, लेकिन अभी तक नहीं किया और इसी प्रकार की एडवर्स रिपोर्ट के आधार पर एस० टी० सी० ने पाउडर देना ही बन्द कर दिया। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था कि एस० टी० सी० ने इम्पोर्ट करना ही बन्द कर दिया है। मैं इस बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर एस० टी० सी० इस मिल्क पाउडर का एक्सपोर्ट बन्द कर दे तो देहली और साउथ का जो कन्ज़म्शन है वहां की हालत क्या होगी? मगर यह हो सकता है कि एस०-टी० सी० ने राजस्थान को देना बन्द कर दिया हो। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि हमारे पास एस० टी० सी० का लैटर मौजूद है, यदि उनके पास है तो यह लैटर सदन के सामने रखेंगे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस प्रकार का लैटर है....

श्री श्रीमानसिंह : आप जवाब के समय जवाब दे देना, अगर है तो आप पढ़ देना।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं इस बारे में आपको साफ कह देना चाहता हूँ कि वह लैटर है जो इस प्रकार का है :—

"In this connection we have to inform you that there will be no further import of skimmed milk powder under P. L. 480 Programme for the present."

This is the letter. So the Hon'ble Member should have taken my word...

श्री श्रीमानसिंह : यह कौनसी डेट का है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : 16th march, 1960. We had written a letter that they should give us more.

श्री श्रीमानसिंह : मार्च १९६० तक यह अलॉटमेन्ट हुआ है और जैसा कि कहा गया मार्च १९६० को यह मिल्क पाउडर आना बन्द किया गया। इस बीच के समय में जो केसेज़ हुए, जो मिल्क पाउडर आया उसका वितरण किस प्रकार से हुआ, यह भी आपने देखा है या नहीं? इस लैटर के साथ साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूँगा कि क्या स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का यह लैटर नहीं कि इनको प्रोसीक्यूट किया जाय? जिन तीनों पार्टीज़ ने ब्लैक मार्केट किया, उन्हीं को अलॉटमेंट होता है। क्या आप

(श्री श्रीमानसिंह)

उनसे पूछ नहीं सकते कि आपको जो मिल्क पाउडर दिया गया वह किस तहसील में, किस जिले में आपने डिस्ट्रिब्यूट किया ? यह जिम्मेवारी आप पर आ जाती है। आपने जहां एवर ग्रीन ट्रेडर्स कम्पनी को अलॉट किया वहां आपने उसको ब्लैक मार्केट करने के लिये प्रोत्साहन दिया है ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय उपाध्यक्षजी, बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मेरे और उनके कॉमन कट मोशन्स हैं उन पर विचार व्यक्त किया, उन पर मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता । मैं केवल उन्हीं बातों पर अर्ज करूंगा जो बातें उनके द्वारा नहीं कही गई हैं। इससे पहले कि मैं अपने कट मोशन्स पर अपने विचार प्रगट करूं एक चीज़ की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा । पिछले दो दिनों से इस सदन में इस बात की कोशिश की गई कि खादी के नाम को बदनाम किया जाय । इस सदन में कुछ माननीय सदस्यों की यह इच्छा रहती है कि कोई भी जरा सी बात हो उसी बात को लेकर सारी की सारी चीज़ को बदनाम किया जाय । इससे पहले भी इस प्रकार के मौके आये हैं जिसमें एक पुलिस अफसर या पुलिस हैड कॉन्सटेबल की गलती के कारण सारी की सारी पुलिस को राक्षस बताया गया । ऐसे ही मौके पर सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन को दिवालिया घोषित करने की बात कह कर बदनाम करने की कोशिश की गई है....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय सदस्य ने भी अपने नेता को डाकू बतलाया था ।

श्री चन्दनमल वैद : ऐसी ही एक कोशिश माननीय सदस्य ने खादी के बारे में भी बता कर उसको नाकामयाब बताने की कोशिश की, जिसमें वे नाकामयाब ही रहे ।

एक तरफ तो श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य अखबारों के कटिंग में से यह पढ़ कर सुनाते हैं कि खादी देश के लिये कितनी जरूरी है, देहातों के कितने लोग अन्डर एम्प्लॉयड हैं, उनके लिये इसका होना कितना जरूरी है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक सदस्य, जो जौहरी बाजार से आते हैं, खादी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जिनका खादी से कोई प्रेम नहीं, लगाव नहीं। मैं समझता हूँ इस तरह की बातें माननीय सदस्यों ने कहीं । उनके फायदे के लिये मैं खादी के बारे में अर्ज कर देना चाहता हूँ कि खादी देश के लिये कितनी जरूरी है । यह इस बात से पता लग जावेगा कि जहां खादी की इन्डस्ट्री में आज एक करोड़....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : खादी के औचित्य को सभी मानते हैं । आप तो यह साबित करिये....

श्री चन्दनमल वैद : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य मानते हैं इसका औचित्य, यह मुझे मालूम है, पर जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य नहीं मानते । उनके फायदे के लिये अगर मैं कुछ बताऊं तो नसीराबाद से आने वालों को आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : इसका महत्व हम भी मानते हैं ।

श्री चन्दनमल वैद : आप मानते नहीं हैं, इस बात को आप कहते हैं ।

Page No.82

श्री भैरोंसिंह : सदन का समय व्यर्थ की बहस से बचाने के लिये कह दूं मैं कि हम भी खादी का महत्व मानते हैं। खादी अच्छी है। खादी के पहिनने वाले....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आज आप सुधर गये, इसके लिये मुझे खुशी है।

श्री चन्दनमल वैद : खुद ८०-६० मिनट तक सरकार को दिवालिया बतावें, खादी के घोटाले गिनावें, एडमिनिस्ट्रेशन को गालियां दें और नीचे से नीचे स्तर पर आकर बातें कहें और दूसरा सदस्य बोल कर दो शब्द भी कहना चाहें तो आप सुनना नहीं चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि यह किस परम्परा की बात हम कर रहे हैं? यह मेरी समझ में नहीं आता। अगर यही टेन्डेन्सी जारी रही कि आप तो डेढ़-दो घंटे बोलते शान्ति से सुनते रहें और दूसरा सदस्य एक मिनट भी बोले तो उसे शान्ति से नहीं सुनें, प्रिविलेज की ऊंची ऊंची बातें करें और दूसरों से कहें कि हम नीची बातें करें....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : ऊंचा बोलने से माइक में आवाज भर्राती है और सुनने में कम आती है।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस पर इससे अच्छा असर होता है।

श्री चन्दनमल वैद : प्रान्त में ५२ खादी की संस्थाएं चल रही हैं। यह जरूरी नहीं कि जितने कार्यकर्त्ता इसमें हैं वे सारे के सारे दूध के धोये हों, टोप ऑनेस्ट हों। हो सकता है, कहीं किसी कार्यकर्त्ता ने कुछ गलती की हो। खादी के कार्य क्षेत्र में कोई आइरन डोर नहीं लगा है कि इसमें उन्हीं को एन्टर करने दिया जावे जो इसके प्रेमी हों। सम्भव है, जैसा सदन में कहा गया कि खादी से उनको प्रेम नहीं है, ऐसे व्यक्ति इन संस्थाओं में घुस आये हों और वे उसे बदनाम करना चाहते हों। दस साल के दौरान में ऐसे दो केस इन संस्थाओं में हो गये और इन दो केसों के नाम पर अगर सारी खादी की संस्थाओं को बदनाम करना चाहते हों और कहते हों कि खादी में तो बुराई ही बुराई है, पान की दूकान पर खड़े बातें करते हों तो इस तरह की बातें करना खादी के क्षेत्र में काम करने वालों के ही प्रति न केवल अन्याय होगा, देश के साथ भी अन्याय होगा और सारा का सारा उनका यह एटीट्यूड एन्टी-नेशनल है। अगर कुल प्रान्त की ५२ संस्थाओं में से दो का उदाहरण दिया है, एक तो सन् ५० की है। कोई लेले साहब ५० में आये। उन्होंने कोई रिपोर्ट दी, उस पर कार्यवाही हुई। ऐसे व्यक्ति उस संस्था से निकाल भी दिये गये। जिस अजमेर के साथ नाम लिया, उसका पुनर्गठन ५६ में हुआ। ऐसे सारे कार्यकर्त्ताओं को सजाएं मिल चुकीं, निकाले जा चुके और उसका पुनर्गठन हुआ और इसके बावजूद भी....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of information, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please!!

श्री चन्दनमल वैद : I don't want to get any information. I refuse to get information.

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please!!

श्री चन्दनमल वैद : इसके बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा केस करौली का बताते हैं ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : If anything..

Page No.83

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon'ble member not to interrupt the debate.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I am not interrupting.

श्री चन्दनमल वैद : सन् ५७–५८ का दूसरा करौली का केस बताते हैं। दस सालों में ५२ खादी संस्थाओं में केवल दो खादी संस्थाओं के गड़बड़–घोटाले की बात बताते हैं और उनके आधार पर आज इस खादी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि खादी एक पवित्र चीज़ है। इसके साथ राष्ट्रीय भावनाएं जुड़ी हुई हैं। खादी वह चीज़ है जिसको पहिन कर देशवासियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। जो राजनीति के मैदान में आजादी के बाद आये वे आज घोटाले की बातें ही महसूस करते हैं, पर जिन्होंने खादी पहिन कर आजादी की लड़ाई लड़ी है वे उसे पवित्र चीज़ मानते हैं और खादी इकोनोमिकली भी देश के लिये जरूरी चीज़ है। इसके बिना देश आगे बढ़ नहीं सकता। उनकी समझ में यह बात आ नहीं सकती। मैं मानता हूँ, कुछ गल्तियां हुई। पर इस वास्ते इनी–गिनी, छुट–पुट घटनाओं को लेकर देश में और प्रान्त में खादी को बदनाम करने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं है। राजस्थान में आज एक करोड़ गज से ज्यादा खादी का उत्पादन होता है। ६० लाख, सौरी, ६० हजार आदमियों को यह पार्श्यल या फुल एम्प्लॉयमेन्ट देता है। वे इसे महसूस नहीं करते। वे तो चाहते हैं किसी तरह से एक-दो घटनाओं से बदनाम कर दिया जावे और इस तरह से इसे बन्द करके उन लोगों को जो एम्प्लॉयमेन्ट मिल रहा है उसको बन्द कर दिया जावे।

(विराम)

उनकी मंशा राजस्थान के इस बजट को दिवालिया बजट कहने के पीछे भी यही है कि किसी तरह से इनको बदनाम किया जाय ताकि उनको लोन न मिल सके कहीं से और लोन न मिल सके तो ये अपनी योजनाओं में इन्वेस्टमेन्ट न कर सकें और इस तरह इन्वेस्टमेन्ट न मिले तो डेवलपमेन्ट प्रान्त का न हो और तब वे सदन में शान से कह सकें कि इस सरकार ने कोई डेवलपमेन्ट नहीं किया। इस तरह से हर चीज़ के निगेटिव एप्रोच का प्रदर्शन करते हैं।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव के बारे में कहना चाहूँगा....

श्री उपाध्यक्ष : अब तक कट मोशन पर नहीं थे आप ?

You will please conclude as early as possible.

श्री चन्दनमल वैद : बयाना से आने वाले माननीय सदस्य को मुझसे पहले मौका देकर मेरी बहुत बड़ी मदद की है और मेरी बहुत बड़ी लेबर बचा दी है।

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि मैं सब्जेक्ट के इम्पोर्टेन्स को पहचाने हुए था पहले से।

श्री चन्दनमल वैद : मैं अर्ज करना चाहूँगा कि जैसा बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी सीमेन्ट फैक्टरी है और वह जयपुर से ८० मील की दूरी पर है। पर आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज किसी को एक बोरी सीमेन्ट चाहिये तो उसको जयपुर में नहीं मिल सकती और माननीय मन्त्री महोदय को इसका विश्वास न हो तो अभी

(श्री चन्दनमल वैद)

मेरे साथ वे चलें और मैं साबित करने को तैयार हूँ।

दूसरी बात है जी. आई. शीट्स को। कई बार शिकायत की गई कि जब खुले आम बाजार में, चौड़े रास्ते में, एक दूकान में नहीं आधी दर्जन दूकानों में जी. आई. शीट्स दूने दामों में मिल सकते हैं। तो फिर मैं पूछता हूँ कि आपके पर्मिट से क्यों नहीं मिलते? मन्त्री महोदय जाहिर करते हैं, हमारी मजबूरी है। भारत सरकार का आइरन कन्ट्रोलर इसका कारण है। हमारा कोई कन्ट्रोल नहीं उन पर। मैं पूछना यह चाहता हूँ कि जब आपके पर्मिट से लोगों को नहीं मिलता तो उन दूकानदारों के पास आता कहां से है? इसका शायद आप यह घिसा-पिटा सा जवाब देंगे कि ६० दिन के बाद जी. आई. शीट्स फ्री होती है और तब दूकानदार फ्री बेच सकता है। मैं पूछता हूँ कि जब दो-दो साल से लोगों की दरख्वास्तें आपके पास आ रही हैं, उनकी दरख्वास्तें मौजूद हैं, दो-दो साल से आपके दफ्तर में पड़ी हैं। दो साल से लगातार मांगने वालों को आपके पर्मिट से नहीं मिले और दो महीने पहले आने वाली जी. आई. शीट्स फ्री होकर बाजार में बिकने लग जावे, इसकी आप क्या सफाई दे सकते हैं? इसका आपके पास क्या जवाब है, सिवाय इसके कि आपके यहां के व्यवस्थापक, जो पर्मिट देने की व्यवस्था करते हैं वे अयोग्य हैं या तो, या ईमानदार नहीं हैं। मैं अपने इस कथन के सुबूत में आपको निमन्त्रण देता हूँ, आप अपना सारा अमला लेकर मेरे साथ चलिये। अगर आपको विश्वास न हो तो चौड़ा रास्ते के दूकानदारों से मैं आपको अभी इसी समय पांच हजार जी. आई. शीट्स आपके पर्मिट की रेट से दुगुने दामों में दिला सकता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके कथनानुसार जब ये कम आती हैं तो फिर खुले आम बेचने के लिये उन दूकानदारों को कहां से मिल जाते हैं, जब कि दो सालों से लोगों की दरख्वास्तें आपके पास पर्मिट लेने के लिये पड़ी हैं? मुझे जानकारी है इसकी कि लोगों की दो-दो सालों से दरख्वास्तें आपके यहां पड़ी हैं। उनको यह कह दिया जाता है कि माल है नहीं, बिक गया। अब अगर इसमें आप यह कहें कि आइरन स्टील कन्ट्रोलर का ही कुसूर है, वह आपकी बात नहीं मानता तो नहीं चाहिये, ऐसी जी. आई. शीट्स हमें। हम नहीं चाहते कि वह अपने कारनामों से हमें बदनाम करे। यह कोई तुक नहीं है कि वह हमें बदनाम करता रहे और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। एक तरफ तो कहते हैं आप वितरण करें, पर आप दे नहीं सकते और दूसरी ओर खुले आम बाजार में दूनी कीमत पर बिके और आप सब यह जानते होते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री इस बात को ओर ध्यान देंगे और कम से कम इसका तो ऐसा कुछ स्पष्टीकरण देंगे कि जिससे कुछ सन्तोष हो सके। इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे इतना समय दिया, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सूबेदारसिंह (बाडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव को पेश करते हुए आपके समक्ष यह कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रान्त की बहबूदी के लिये हमारी सरकार ने यह सोचा कि हम अपने औद्योगीकरण को दिन दूना और रात चौगुना बढ़ाकर देश की बेकारी को दूर करें और अपने प्रान्त को भी आर्थिक समस्याओं को सुलझा सकें।

Page No.85

(श्री सूबेदारसिंह)

इसके साथ अपनी सरकार हर प्रकार की पेसिलिटी अपने प्रान्त के और बाहर के औद्योगिकों को उद्योग यहां खोलने के लिये देने को तैयार हैं; लोन, जगह, रॉ मैटीरियल, आदि लेकिन यदि मैं यह कहना चाहूँ कि जहां हमारी यह सरकार इतनी उत्साहपूर्वक अपने प्रान्त को औद्योगीकरण के उच्च शिखर पर ले जाना चाहती है वहां हमारी सरकार की मशीनरी की ओर से इस प्रकार की ढ़िलाई देखने को मिलती है कि जो व्यापारी या जो जनता उद्योग की स्थापना करके उसे फला—फूलता देखना चाहती है और अपने प्रान्त की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठा देखना चाहती है। वे उसकी सारी आशाएं इस सरकारी मशीनरी की अकर्मण्यता से और ढिलाई से व्यर्थ जाती हैं, वे इस तरक्की को देखने से महरूम रह जाते हैं।

मैं आपका ध्यान इसी प्रकार से अपने भरतपुर जिले की ओर ले जाना चाहता हूँ। वहां पर पिछले दो—तीन साल से कुछ इन्डस्ट्रीज़ शुरू हुई, क्योंकि जब हम देश के व्यापारियों की यह चर्चा सुनते हैं कि राजस्थान सरकार अपने राजस्थान को उद्योग की दृष्टि से बहुत ऊंचा करने जा रही है; यह कोई कहने की बात नहीं, माननीय सदस्य सभी जानते हैं कि कोटा में जिस प्रकार से इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा है, धीरे धीरे लोगों की यह भावना है कि कोटा कानपुर की तरह से औद्योगिक सेन्टर हो जायेगा। तो हमारे व्यापारियों ने धौलपुर और भरतपुर में जो कारखाने खोले उसके लिए सरकार ने रॉ—मैटीरियल के लिये काफी परमिट दिये। वहां लोहे के कारखाने थे, किसी के साइकिल बनाने के नाम से, कोई बालटी और सन्दूक बनाने के नाम से कारखाने खोले हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा कि उन कारखानों में अब सिर्फ इतना ही रह गया है कि उनकी बिल्डिंग या कमरों के सामने उनके नाम का बोर्ड लिखा हुआ है और वहां एक भी नौकर नहीं होता है। उनकी छोटी-मोटी दो-तीन हॉर्स पॉवर की मोटर खाली चला करती है वह भी सिर्फ बिजली का कन्ज़म्पशन दिखाने के लिए। उनको जो रॉ—मेटीरियल मिलता है वह लोहा धौलपुर और भरतपुर तक नहीं आता है वह बॉम्बे और कलकत्ता, जहां से इनको माल मिलता है, वह वहीं का वहीं बेच दिया जाता है। क्या यही अच्छा होता कि जहां लोगों को माल मिल रहा है वहां हमारी सरकार इस बात का भी ज्ञान करे कि हम जो इतना लोहा देते हैं उससे कितना माल बन कर तैयार होगा और इतना माल उन लोगों ने तैयार भी किया या नहीं किया? अगर नहीं हुआ तो वह कहां कन्ज़्यूम हो गया? जब तक इसकी नॉलेज हमारी मशीनरी को नहीं होगी तब तक हमारे व्यापारी भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्योंकि व्यापारी तो हमारे यहां पर पैसा कमाने की गरज से, कारखाना खोलने के लिए आये हुए हैं। अगर इसके ऊपर इतनी निगाह रखी जाये कि जितना मेटीरियल मिलता है उतने का उतना हमारे यहां पर इन्डस्ट्री में काम आये तो जो बेकारी हमारे यहां पर फैली हुई है वह दूर हो जाय और लोगों को एम्पलॉयमेंट भी मिल जाय, बाजार में जो चीजें महंगी हैं वे भी सस्ती हो जायें। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे वह इ

(श्री सूबेदारसिंह)

प्रकार से परमिट और लोन देती है उनको चाहिये कि उसकी तरफ कड़ाई से ध्यान रखे कि वह सामान भी बनता है या नहीं और अगर नहीं बनता है तो यह इन्डस्ट्री किसी प्रकार से पनप नहीं सकती।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ। आज अभी यहां सदन में बहस जब कटौती के प्रस्ताव पर हो रही थी उसमें जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रकार की बात कही कि खादी से आज घृणा सार्वजनिक दृष्टि से उतनी हो गई है कि पान खाने वालों की दूकान पर भी खादी पहिने हुए कोई आदमी मिले तो लोग उससे घृणा करते हैं, मानों इस खादी में पाप छिपा हुआ हो। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, जरा भी नहीं चूकता कि आज से ५० साल पहले जब कि खादी शुरू हुई थी तभी से लोगों ने घृणा करना शुरू किया था। उस समय खादी पहिनने वाले लोगों ने नारा लगाया कि प्रजातंत्र देश में लेंगे उसी समय से खादी को बुरी निगाह से देखने लगे। धीरे२ समय-परिवर्तन हुआ और ज्यों ज्यों लोगों में जागृति बढ़ी देश आजाद हुआ। आजादी के साथ साथ हमारे माननीय मित्र जो कि खादी को बुरी तरह से कोसते थे वे नहीं कहते; बल्कि जो सरकारी मशीनरी में हैं उन्होंने भी प्रजातंत्र बनने के बाद खादी पहिनने वालों को 'थ्री नॉट थ्री' कह कर पुकारा। वे जानते हैं कि ये वही लोग हैं जिनसे अन्याय समूल नष्ट हो जायेगा। दूसरे समाजवादी पार्टी या जनसंघ या दूसरी संस्थाओं ने जब देखा कि टोपी में यह गुण हैं तो उन्होंने सफेद की जगह काली, लाल और पीली टोपी पहिननी शुरू कर दी। क्योंकि सफेद पर तो फौरन दाग नजर आता है और काली, नीली, पीली रंग की टोपी में सब दोष छिप जायेंगे।

एक माननीय सदस्य ने करौली की खादी के बारे में कहा। मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि करौली की और धौलपुर की खादी की संस्थायें मेरी अच्छी तरह देखी हुई हैं। मैं आज भी गांवों में जाता हूँ। वहां की जनता किस प्रकार से उत्सुक है कि खादी का काम हमारे यहां पर जल्दी से जल्दी बढ़े। आज उनमें मुसलमानों के एक हजार के करीब परिवार ऐसे हैं कि जिनके घर में चूल्हा तब सुलगता है जब कि खादी से रोजी मिलती है। यह छिपी हुई बात नहीं है कि जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनकी स्त्रियां घरों में बैठ कर पार्ट टाइम में चर्खा कातती हैं। इससे उनको इतना एम्प्लॉयमेंट मिलता है कि धीरे धीरे वे आज भी अपना जीवन निर्वाह करते हुए चले जा रहे हैं। अगर आप खादी के आंकड़ों को देखें, जो माननीय मंत्री महोदय प्रस्तुत करेंगे, कि हमारे यहां पर १९५३ में ३ लाख और कुछ हजार की खादी बिकती थी जब कि १९५९-६० के आंकड़ों से मालूम होता है कि ६७ लाख ६८ हजार की खादी की राजस्थान में बिक्री हो रही है। यह हमारे प्रान्त से बाहर भी बिक्री के लिए जाती है; बम्बई जाती है, बिहार जाती है। हमारे राजस्थान की खादी में दुसूती और गाढ़ा आज हिन्दुस्तान में मशहूर है।

(समय—समाप्ति-सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य ने तो कुछ इस प्रकार की रंगीन भावना में कह दिया कि खादी में क्या ही रंगीन डिज़ाइन आते हैं कि रामनिवास बाग में जायें तो छींट ही छींट नजर आती हैं। मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आज अच्छी से अच्छी फेमिलीज़

Page No.87

(श्री सूबेदारसिंह)

जितनी भी हैं, टूरिस्ट्स जितने भी आते हैं उनको आप खादी घर के एम्पोरियम में देखें कि वे अच्छी से अच्छी डिज़ाइन की छींट खरीदते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : पर्याप्त है आपका भाषण ।

(विराम)

श्री हीराभाई ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कटमोशन है : "मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग और प्रदाय में एक रुपये की कटौती की जाये (छोटे उद्योगों को पनपाने पर विचार करने हेतु) ।"

श्री उपाध्यक्ष : वह पढ़ा जा चुका है, आप आरम्भ करिये ।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा देश उद्योग और कृषि पर निर्भर है । हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और अन्न अधिक संख्या बढ़ने से ज्यादातर हमारे यहां उद्योग की जरूरत है, ताकि यहां के लोगों का पालन—पोषण का जरिया पूरा हो सके । इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक हमारी सरकार का ध्यान बड़ी बड़ी मिलों और कारखानों पर रहा है । छोटा वर्ग वहां पर पहुँच नहीं सके और पोषण का जरिया प्राप्त नहीं कर सके, इतनी दूर वे साधन हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि बड़े उद्योगों की तरफ ज्यादा ध्यान न देकर छोटे उद्योगों की तरफ ध्यान ज्यादा दिया जाये । कारण यह है कि बड़े बड़े उद्योगों में तो बड़े बड़े लखपति लोगों का गरीबों पर शोषण करने का तरीका है और छोटे उद्योगों में स्थानीय मजदूरों के पोषण करने का तरीका है । तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर हमारे देश में है क्या ? बड़े उद्योगों की तरफ हमेशा हम ध्यान रखें और छोटे छोटे उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं दें ? नाम मात्र के लिये उद्योग प्रसार अधिकारी कायम कर दिये और जिला उद्योग कार्यालय कायम कर दिये लेकिन उद्योगों का कोई प्रसार नहीं होता और छोटे बड़े महकमे कायम होते जाते हैं और उनका खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं । छोटे वर्ग के लोगों के लिये आज तक नाम मात्र के लिये कोई ऐसी एजेन्सी कायम कर दी हो या नाम मात्र का वह भी कर दिया हो कि पंचायत समितियों को यह अधिकार दे दिया है । मंत्रीजी यह कहेंगे कि हमने पंचायत समितियों को यह काम सौंप दिया है ताकि वे अपने आधार पर कर सकें, लेकिन मैं कुशलगढ़ की एक मिसाल आपके सामने रखूं । वहां पर एक इन्डस्ट्री जिसे कहते हैं, वहां के स्थानीय लोगों को रोजी या धंधा दिलाने के लिये थी । वहां पर लकड़ी चीरी जाती थी और कई तरह के तेल जैसे इंडोली का तेल, तिल्ली का तेल निकलता था और वहां पर साबुन की फैक्ट्री चल सकती थी । वहां पर पहले १० महीनों के लिये सेन्टर खोला गया था और फिर सब को खत्म कर दिया । वहां पर छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़ थीं, आरे की मशीन थीं जिससे कई लोगों को फायदा होता था । पांच हाथ की लकड़ी भी ले आवे तो बेच देते थे और उनका धंधा चल सकता था । लेकिन न मालूम क्यों ? शायद उसमें कांग्रेसी सदस्य न होने के कारण २ साल से सरकार ने इसे बन्द कर दिया । एक आदमी तो नहीं कर सकता था लेकिन १०-१२ आदमियों ने मिल कर किया था । लेकिन

(श्री हीराभाई)

न मालूम किसके आदेश से इसको बिल्कुल ठप्प कर दिया। तो मैं इस ओर दुबारा माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा कि इस फैक्ट्री को, आरे की मशीन को वापिस कायम किया जाय और दूसरी इन्डस्ट्री जैसे सोप फैक्ट्री कायम की जाय, क्योंकि वहां पर इसके लिये साधन मौजूद हैं। सोप बन सकता है। साबुन बनाने के लिये इंडोली का तेल मिल सकता है, तिल्ली का तेल मिल सकता है, इनकी पिलाई भी वहां पर होती है। इसलिये साबुन बनाने की फैक्ट्री वहां शुरू करनी चाहिये। शायद उन लोगों से चली नहीं होगी परन्तु यह सरकारी रूप में हो सकती है। सरकार अपने हाथ में इसे लेकर इन्डस्ट्री चलाने की कोशिश करे ताकि लोगों को मजदूरी या धंधा मिल सके।

दूसरी बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा कि आज ५ साल हो गये, हमने सन् ५८ में एक वन-श्रमिक समिति कायम की थी ताकि वहां के मजदूरों को पूरी तरह से धंधा मिल सके और ठेकेदारों को दिये जाने वाले ठेकों को रोक कर इस समिति को दिये जा सकें ताकि वहां के आदमियों को पनपा सकें।

इसके लिये ५० आदमियों ने मिल कर वन-श्रमिक समिति कायम की थी। उसको सरकार ने कितनी ही बातों से खत्म करने की कोशिश की। वहां पर ठेके होते जा रहे थे। हमने सन् ५८ में इस समिति के ठेके दिये जाने के लिये जोर दिया, परन्तु ५९ के अन्त में हमको ठेका मिला। इस आर्डर से सरकार का गरीबों के साथ कैसा व्यवहार है; इसका पता चलता है। सन् ५८ में हमने सरकार से ठेका देने के लिये कहा और सन् ५९ की फरवरी में बड़ी मुश्किल से यह ठेका प्राप्त हुआ। फिर भी वह मिलने वाला नहीं था लेकिन वहां पर हमने शिकायत की कि हमारा काम पसन्द नहीं है तो पैसा वापिस दे दो, तब सिर्फ २ महीनों का टाइम दिया। अब मजदूर १०-१२ लाख बांस वैसे इकट्ठा करें और बीच में जितने लोगों ने शेयर भरे थे और दूसरे लोगों से कर्जा लेकर शुरुआत की थी वह फिजूल गया और ब्याज में डूब गये। ३१ मार्च को लेना बन्द कर दिया और हमने कंजर्वेटर से कहा था, वन मंत्रीजी से कहा था कि अप्रैल का महीना और दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। कहने के मुताबिक पेश किया था, लेकिन अब तक ध्यान नहीं दिया और वह ठप्प हो गई। उद्योग समिति वहां के लोगों के सिर पर पड़ गई और इस समिति को फिर ठेका इस साल आया, लेकिन उसको आज तक जिस सरकार ने नहीं दिया, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम छोटे उद्योगों को कैसे पनपा सकते हैं? हो सकता है कि वहां के लोग कांग्रेस विरोधी होंगे। लेकिन वहां के मजदूर ऐसे हैं जो सोशियलिस्ट या कांग्रेस का नाम तक नहीं जानते हैं। उनके लिये यह मतभेद किया है। यह पार्टीबाजी का नतीजा है। यदि कोई एक पार्टी का होता तो उसे दे दिया जाता, कारण कि बड़े बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देकर छोटे उद्योगों को ठप्प करना चाहते हैं। तो मैं इस कटौती प्रस्ताव के साथ मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इस इन्डस्ट्री को शुरू करें, दूसरी साबुन फैक्ट्री शुरू करें और चमड़ा उद्योग वहां शुरू हो सकता है उसको भी शुरू किया जावे। चमड़ा पकाने और रंगाने का काम ४ साल पहले वहां शुरू करना चाहते थे। इसके लिये मशीनरी बैठाने के लिये मदद

(श्री हीराभाई)

देने के लिये कहा। लेकिन सरकार की तरफ से लोन आज तक नहीं दिया गया। छोटे उद्योगों के साथ सरकार का इस तरह का रवैया रहा है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, इस शीर्षक के अन्तर्गत मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं। पहला है, उद्योग विभाग में नियन्त्रण के अभाव पर बहस करने हेतु। यह 'नियन्त्रण' शब्द का अर्थ इस प्रकार से कंट्रोल न समझें, जिसमें लोगों को परमिट हासिल करने पड़ते हैं। मेरा प्रस्ताव इस विभाग पर ठीक तरह से देख-रेख नहीं होने से संबंधित है। यह चीज़ इसलिये लानी पड़ी कि समय समय पर क्या पत्रों में और क्या हमारे सदन में और क्या दूसरे प्रकार से, आम तरीके से, यह चर्चा चलती है कि उद्योग विभाग के द्वारा कितने ही लोग कई प्रकार के परमिट, कई प्रकार के लाइसेन्स आदि प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग होता है। अभी कुछ दिन पूर्व ही इस सदन में एक प्रश्न उधर बैठने वाले माननीय सदस्य ने किया था, खास तौर से भरतपुर में बोगस फैक्ट्रीज़ के बारे में। मुझे याद है २०—२२ फैक्ट्रीज़ की सूची पढ़ी थी। कुछ शर्म महसूस होती है, किसी स्थान विशेष के बारे में यह बात सुन कर कि वहां के लोग इस प्रकार का देशद्रोह का काम करते हैं; ऐसी बोगस फैक्ट्रीज़ बना कर राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करके। यह तो एक ही स्थान की बात है, किन्तु यदि हर जिले में इस प्रकार से हुआ तो बड़ा भारी कलंक है हमारे विभाग के प्रबन्ध के ऊपर और मैंने यह समझा है शायद अभी उनका कंट्रोल या सुपरविज़न या देखरेख जितनी मजबूत होनी चाहिये उतनी नहीं है। क्यों इस तरह ब्लैक मार्केटियर्स पनप रहे हैं, क्यों इस प्रकार परमिट और लाइसेन्स मिल जाते हैं? उनकी ठीक देखरेख क्यों नहीं होती है? क्यों सुनने को मिलता है कि बम्बई की खरीदी हुई चीज़ बम्बई में ही बिक जाती है, कलकत्ते की खरीदी हुई चीज कलकत्ते में बिक जाती है और उस शहर या स्थान तक नहीं आ पाती जहां के लिए लोगों को परमिट देते हैं? यह विभाग की ढिलाई है; इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव के जरिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूँ कि वे विभाग को टाइट करें। मैं समझता हूँ, इसके डाइरेक्टर महोदय और सभी अधिकारी काफी कुशल प्रशासक हैं, वे इस ओर ध्यान देंगे, तो इस विभाग के सम्बन्ध में जो रोजमर्रा चर्चाएं सुनने को मिलती हैं वे नहीं सुन पायेंगे।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है औद्योगिक सम्पदाओं की उचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में। यह भी लगभग उसी ढंग की एक मेरी आशंका है। आज देश के अन्दर, खास तौर से औद्योगिक विकास के लिए, हमारी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की नीति है कि वे किन्हीं खास विशेष स्थानों पर कुछ इस तरह के औद्योगिक संस्थान कायम करें और वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं,

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

उनको विशेष सुविधाएं दी जायं, जिससे उद्योग को बढ़ा सकें। इस प्रकार की कई सम्पदायें राज्य में खुली हुई हैं, लेकिन उनके सम्बन्ध में आम तौर पर शिकायतें सुनी जा रही हैं कि वहां लोगों ने अपनी फैक्टरियां के नाम से जमीन ली है, फैक्टरियां भी बनी हैं, यह भी कहा जाता है कि कुछ माल वहां तैयार होता है। लेकिन आम तौर पर उनके बारे में शिकायत यह है कि वहां अगर लोहे की चीज़ बनाने की फैक्टरी बनाते हैं, तो वहां लोहे की चीजें नहीं बनती हैं, लेकिन कच्चा माल आता है, वह कच्चा माल चला जाता है। इसी तरह से जहां चमड़े की चीजें बनाने की फैक्टरी है वहां चमड़े की चीजें नहीं बनती हैं, लेकिन कच्चा चमड़ा चला जाता है। हर तरह की चीजें बनाने की फैक्टरी सम्पदाओं में बनती हैं कि वहां पर कच्चे माल का आयात निर्यात बाहर बाहर होता जाता है, इस तरह की बातें सम्पदाओं में होती हैं। हम लोग उत्साह से देखना चाहते हैं, जैसे किसी दिन देखने में आता था, हर चीज पर मेड-इन-इंगलैंड, मेड-इन-जर्मनी का नाम पाते थे, आज सौभाग्य से मेड-इन-इंडिया के नाम से बाजार में कई चीजें मिलती हैं, लेकिन इन सम्पदाओं में मेड-इन-जयपुर के नाम से कोई चीज देखने को नहीं मिलती है। हम समझ नहीं सकते कि तीन–चार साल के अर्से से सम्पदायें खुली हुई हैं, लेकिन इन सम्पदाओं के अन्दर क्या चीज़ बनती है, इनको कितना कच्चा माल मिलता है, किस तरह की चीज़ मेन्युफेक्चर करती हैं, किस तरह का आउट पुट होता है। इन सारी चीजों का नेट रिज़ल्ट देखते हैं तो विशेष प्रगति की ओर जाते दिखाई नहीं देते। इसलिए इस सम्बन्ध में मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है कि हमारे औद्योगिक संस्थान जिनको इन्डस्ट्रियल एस्टेट कहते हैं, की ओर विशेष ध्यान दिया जाय और वहां सच्चे और ईमानदार आदमी हों, जो चीजें लाते हैं, उनका उपयोग होता है, इस पर थोड़ा नियंत्रण की जरूरत है।

मेरा तीसरा कटौती का प्रस्ताव है, मैं उसे कुछ विशेष महत्वपूर्ण मानता हूँ, इस दृष्टि से कि कम से कम मैं और मेरे वर्ग के दूसरे लोग यह बहुत दिनों से आशा करते आये हैं कि इस देश की अगर बेकारी दूर हो सकती है, इस देश को सुखी और समृद्धिशाली बनाया जा सकता है, इस देश के अन्दर कुछ जीवनी शक्ति लाई जा सकती है तो वह कुटीर उद्योग के जरिये हो सकती है, गृह उद्योग के जरिये हो सकती है। आज संसार के अन्दर जो एक बहुत बड़ी हवा चल रही है, कम्पिटीशन चल रहा है चीजों के उत्पादन में, मैं मानता हूँ कि शायद उस हवा के अन्दर हमारे कुटीर उद्योग उसकी बराबरी न कर सकें, उसके लिए हमें विशालकाय फैक्टरियों की जरूरत होगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए फैक्टरियों की जरूरत हो सकती है, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि उससे देश की बेकारी दूर नहीं हो सकती। गांव गांव और दूर दूर के लोगों की रोजी-रोटी की समस्या, जो बड़ी बड़ी फैक्टरियां बड़े बड़े शहरों में लगाई जा सकती हैं उनसे दूर नहीं हो सकती। इससे गांव के किसान, गांव के आदमी स्वाभिमानपूर्वक गांवों में रह सकते हैं, अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, वहां न रह कर शहर में स्लम्स में जाकर बसें,

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

उनका वहां नैतिक पतन हो, शराबी कबाबी हो जायं और स्वाभिमानपूर्वक जीवन और गांव को खो बैठें, बड़ी बड़ी फैक्टरियों में जाकर और अहमदाबाद, बम्बई और ब्यावर में जाकर, लेकिन उनकी जो जीविका के साधन थे, सबसे बड़ी जरूरत, जो घर घर में होनी चाहिए, वह नहीं पहुंचा सके। इसलिए जरूरी है कि इन कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दें और प्रोत्साहन देने के लिए मैंने शब्द जो प्रयोग में लिया है, वह लोकप्रिय शब्द प्रयोग में लिया है। वह इसलिए लिया है कि इसकी ओर सबसे पहले ध्यान, मैं समझता हूँ, आज से चालीस पैंतालीस साल पहले राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी का गया था। महात्मा गांधीजी ने जिस समय कांग्रेस का सूत्र अपने हाथों में लिया था, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि जब तक देश की बेकारी को दूर नहीं करेंगे तब तक देश की आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर नहीं होंगे; केवल राजनैतिक स्वतंत्रता हमको हमारे लक्ष्य पर पर नहीं पहुंचायेगी। राजनैतिक स्वतंत्रता पाने के पहले महात्माजी ने विचार प्रकट किया था कि हमारे देश के हजारों लाखों निवासी, विधवा बहिनें, जिनका धन्धा अंग्रेजों के शासन काल में छूट चुका था, उनको रोजी–रोटी दी जाय। आज दुर्भाग्य से इस सदन में सुनने को मिलता है, खादी जैसी पवित्र चीज़ को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है मानो उसके ऊपर कोई एक राजनैतिक किसी प्रकार का कोई दबाव लगा दिया गया है। मैं कहता हूँ खादी को महात्मा गांधी ने, कुटीर उद्योग को महात्मा गांधी ने कभी राजनैतिक दलबन्दी में नहीं घसीटा और उसको राजनीति से ऊपर रखा। उसमें काम करने वाले लोगों को राजनीति से दूर रखने की सलाह दी और खादी की पवित्रता की ओर ध्यान दिया। हम खादी को सभी रूप में, जैसे मैं जनेऊ धारण करने वाला हूँ, जनेऊ की जो पवित्रता है उसके बराबर पवित्र खादी को मानता हूँ, क्योंकि एक युग था, उस समय विलायती कपड़े के लिए कहते थे कि इसमें मांस और चर्बी लगाई जाती है, जो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है उसको विलायती कपड़े को पहिनने से घृणा करनी चाहिए। मैं जो कहता हूँ, वह भावावेश में नहीं कह रहा हूँ, एन्साइक्लोपिडिया ब्रिटेनिका में लिखा हुआ मिलता है, जितना विलायती कपड़ा आता है उसमें चर्बी का प्रयोग होता है, कपड़े को साफ और मुलायम करने के लिए। उस समय महात्मा गांधीजी ने पवित्रता को रखने के लिए हाथ कती और हाथ बुनी खादी रखी थी, हजारों और लाखों विधवा बहिनों को स्वाभिमान पूर्वक जीने के लिए यह रखी थी। आज उसे समझ नहीं सकते, इसलिए हम राजनैतिक दल का चश्मा लगा कर इस तरह पेश करते हैं। मैं समझता हूँ खादी पवित्रता और खादी एक प्रतीक थी कुटीर उद्योग को, उन्होंने प्रतीक बनाई थी, उसके जरिये कुटीर उद्योग के जरिये देश में खुशहाली होगी। वे मानते थे कि बड़े बड़े शहरों के लोगों की खुशहाली होने से देश की खुशहाली नहीं होगी, बल्कि गांवों की खुशहाली से देश की खुशहाली होगी। वे ग्राम उद्योग पर ज्यादा जोर देते थे। वे इस बात पर जोर देते थे कि गांव की कती, गांव की बुनी खादी जो निकले उसका उपयोग गांव में हो जाय, कुम्हार जो बर्तन बनाये उसका उपयोग गांव में हो जाय, बढ़ई

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जो काठ की चीजें बनाये उनका उपयोग गांव में हो जाय, लोहार जो लोहे की चीजें बनाये उनका उपयोग गांव में हो जाय। इस तरह कुटीर उद्योगों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार देश में हो तो देश की समस्या हल हो सकती है। तो मैंने जो लोकप्रिय बनाने की बात कही है वह इसलिए कही है कि आज से ५० वर्ष पहले हर जगह कुछ न कुछ उद्योग थे। उदाहरण के लिए मैं बताऊं....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समय का ध्यान रखिये।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : भरतपुर में चन्दन का काम होता था, खस का काम होता था, हाथी दांत का काम होता था। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, डीग के अन्दर लोहे का काम होता था, तेल का काम होता था, चमड़े का काम होता था, लेकिन धीरे धीरे ये गांवों में से खत्म होती जा रही हैं। आज हजारों आदमी बेरोजगार होकर शहरों को भागते हैं, क्योंकि उनका धन्धा नष्ट हो गया। इस कारण उद्योग विभाग रुपया चाहे जितना देता हो, उसके लिए बड़े बड़े अधिकारी रखता हो, लेकिन उन कुटीर उद्योगों को लोकप्रिय नहीं बनाता गांवों में जाकर, जिस प्रकार किसी जमाने में खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रत्येक कांग्रेस मैन, जब खादी सप्ताह मनाया जाता था तब बुनकरों के पास जाता था और जितनी खादी तैयार होती थी उसको कन्धे पर लाद कर लोगों के पास, राजाओं के महलों में पहुँचता था। तो खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए जरूरत इस बात की है कि कुटीर उद्योग, गृह उद्योग को उद्योग विभाग पनपाये, आर्थिक सहायता दे, देख–भाल करे और इसके साथ ही लोकप्रिय बनाये। वह ऑफिशियल तरीके से लोकप्रिय नहीं बन सकती, इसके लिए मिशनरी स्पिरिट होनी चाहिए। उसमें काम करने वाले हैं, उनमें इस तरह की मिशनरी भावना होनी चाहिए, जो खादी के लिए कांग्रेसजन में थी। इसलिए कुटीर उद्योगों को लोकप्रिय बनाने के पीछे सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमें देश को अधिक से अधिक धन्धा देना चाहिए, शिक्षित और अशिक्षित लोगों को। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे मन्त्री महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव के द्वारा इस बात की आवश्यकता अनुभव करेंगे कि हम इन कुटीर उद्योगों के लिए बहुत पैसा दे रहे हैं, बहुत से अधिकारी दे रहे हैं, लेकिन खादी को किस तरह लोकप्रिय बनाया जाय, जन–जन के पास कैसे पहुँचायें, उन गृह उद्योगों को किस तरह उपयोग में लायें, उनका किस तरह काम आंकें और अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें ताकि इन उद्योगों की मन्शा पूरी हो सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पेश करता हूँ।

(३.५०. म० प०)

(श्री विशम्भरनाथ जोशी, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : In view of limitations of time I shall request all the

(श्री सभापति)

speakers that no speech on one cut-motion should exceed 5 minutes.

(विराम)

Rao Raja Shri Sardar Singh.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : ५ मिनट में तो काम नहीं चल सकेगा, मेरे दो कट मोशन्स हैं।

श्री सभापति : आप १० मिनट बोलें।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आप हम दो ही शख्सों के लिये यह रखते हैं ताकि हम नहीं बोलें। इसके लिये यदि रखते हैं कि मैं और रावराजा सरदारसिंहजी पांच पांच मिनट ही बोलें तो यह उचित होगा कि आप आज्ञा दे दें कि हम नहीं बोलें।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि एक घंटा और दस मिनट सदन के समय में बाकी रह गये हैं, १२ कट मोशन्स मूव होने हैं और उन पर बोलने वाले हैं। ६५ कट मोशन्स में से ५३ तक बिज़नेस ट्रान्जेक्ट हुआ है। गवर्नमेंट रिप्लाई भी होना है। अगर समय ज्यादा बच जाता है तो ४. ३० तक टाइम मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करूं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उन कट मोशन्स का विरोध भी होना है।

श्री सभापति : I would like in this direction to take the sense of the House, as well as I would like to know the view of the spokesmen of the Government.

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करूं, आखिर हमें १५ रुपये रोज के मिलते हैं तो इसलिये नहीं मिलते कि हम ५ बजे तक ही बैठे रहें, सदन का कार्य हो तो हमें रात को १२ बजे तक भी बैठने के लिये तैयार रहना चाहिये और मैं कहता हूँ कि विरोधी दल के किसी सदस्य को इससे विरोध नहीं होगा कि हम रात को १० बजे तक बैठें।

श्री सभापति : One at a time.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : इसके बारे में निवेदन है कि केवल भैरोंसिंहजी नहीं बोले हैं इसके लिये समय को बढ़ाया जाय, यह उचित नहीं होगा। कल भी बहुत से सदस्य नहीं बोले थे, क्योंकि टाइम खत्म हो गया था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सब को आधा-आधा घन्टा टाइम दिया है।

श्री सभापति : बाकी कट मोशन्स को मूव करने वालों में सदन के दोनों ओर के सदस्य शामिल हैं। तो यह प्रश्न पैदा नहीं होता कि विरोधी पक्ष के सदस्यों को नहीं बोलने देने के लिये यह व्यवस्था की जा रही है।

(विराम)

I would like to know the view of the spokesmen of the Government whe-

(श्री सभापति)

ther they would be prepared to sit beyond the prescribed time.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मन्त्री) : वैसे तो जो भी कट मोशन्स आये हैं, जो माननीय सदस्य बोलना चाहें, उनकी बातें सदन के सामने आ गई हैं। इसके अलावा मुझको भी उनका जवाब देने के लिये एक घन्टा चाहिये; क्योंकि आखिर जो बातें रखी गई हैं उनके बारे में मुझे भी जो विभाग का ढांचा है, नया ढांचा बनाया जा रहा है, ये सारी बातें समझानी पड़ेंगी, तो इसमें मुझे भी समय लगेगा। तो वैसी अवस्था में मैं समझता हूँ जल्दी खत्म कर दिया जायगा तो ठीक होगा।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : चार तो बज चुके हैं, और आप कहते हैं कि आप एक घंटा और लेंगे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : समय निर्धारित है।

श्री सभापति : I would like to take the sense of the House. Are the Hon'ble members prepared to sit beyond the normal time for a considerable longer period, say one or two hours?

(विरोधी दल की ओर से 'Yes' एवं राज्य पक्ष की ओर से 'No' की ध्वनियें)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जैसा कि अभी सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एक घंटा उन्हें चाहिये तो ऐसी दशा में यह तो संभव नहीं कि आधा घंटा या पौन घंटा एक एक माननीय सदस्य को दिया जा सके। इसलिये एक कट मोशन पर ५ मिनट तक ही सीमित रहें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह सिर्फ हमारे लिये ही क्यों रखा ?

श्री सभापति : There are so many others. You please move.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): सभापति महोदय, मुझे बड़ा भारी अफसोस है कि अब तक तो मैं अपना भाषण समाप्त ही कर देता पर जितना भी इस प्रकार का वातावरण पैदा होता है वह उधर से ही होता है, खादी के लिये भी उधर से ही हुआ है। यह स्वाभाविक बात है कि एक बाप के दो बेटे हों; उनमें से एक तो गुलछर्रे उड़ाये और दूसरे को भूखा रखा जाय....

श्री सभापति : Move your cut motion.

रावराजा श्री सरदारसिंह : खादी के जो हैं उनको राजनीति में नहीं पड़ना चाहिये। खादी के जो आरोप लगाये हैं तो उनको मिनिस्टरी छोड़ देनी चाहिये।

श्री सभापति : Please confine your speech to your own cut-motion.

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरा पहला कट मोशन है वह मेरी डिस्ट्रिक्ट में इन्डस्ट्रीज़ के एस्टेब्लिशमेंट के लिये है। माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां चार-पांच लाख की आबादी है। जब से भारत स्वतन्त्र हुआ,

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

राजाओं-महाराजाओं, नवाबों के राज्यों का विलीनीकरण हुआ तब से आज तक मेरी डिस्ट्रिक्ट में एक भी ऐसी इन्डस्ट्री स्थापित नहीं की गई है कि उन राजाओं-महाराजाओं और नवाबों के जो आश्रित थे उनको और जो बेकार बैठे हुए हैं उन बेकार लोगों को काम मिले। जहां तक हो सके वहां के रहने वालों को काम मिले। वे लोग सिर्फ खेती से गुजारा करते हैं, वह भी केवल वर्षा से होने वाली खेती पर गुजारा करते हैं। उस क्षेत्र की ५० हजार जनता बनास पर गुजर करती है। बनास का प्रोजेक्ट बनने वाला है, इससे यह साधन भी उन बेचारों का खत्म हो जायगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर. आप इन्डस्ट्रीज़ के बारे में बातें करते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ये इन्डस्ट्रीज़ के ही सोर्सेज़ हैं। तो वहां पर एक इन्डस्ट्री थी, बड़ी भारी जीनिंग फैक्ट्री थी, उसको भी सरकार ने उठा कर नीलाम करा दिया। टौंक में और कुछ नहीं है, लोग भूखों मर रहे हैं, आबादी दिन पर दिन कम होती जा रही है। जो नवाब के आश्रित थे वे लोग बहुत से भाग कर पाकिस्तान चले गये हैं क्योंकि वहां आस-पास के इलाके तक में इन्डस्ट्री नहीं है। उनियारा में बांध बन रहा है। वहां काफी शुगर केन पैदा होगा तो वहां शुगर की इन्डस्ट्री खोली जा सकती है, कॉटन भी खूब पैदा होगी तो कॉटन इन्डस्ट्री भी खोली जा सकती है।

न हमारे क्षेत्र में स्माल इन्डस्ट्री है; हां, मालपुरा में है····

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : वहां माल पूरा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यही तो कह रहा हूँ। एक को तो गेहूँ खिलाओ और दूसरे को भूखों मारो; यह कहां का न्याय है? अब समय आ गया है, नये चुनावों का आपको मौका दिया जा रहा है····

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): आप नहीं लड़ रहे हो क्या चुनाव ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसलिये जल्दी ही वहां इन्डस्ट्री स्टार्ट कीजिये, नहीं तो लोग कहेंगे कि राजाओं-महाराजाओं के समय से तो इससे ज्यादा काम किया जाता था। अगर नवाब साहब के टाइम में ब्रिज नहीं बनती तो टौंक डिस्ट्रिक्ट नहीं बनता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : नवाब साहब को बुला दें क्या आपके लिये ?

(४. ०० म० प०)

रावराजा श्री सरदारसिंह : उसके मुकाबले में आपने क्या किया ? न कोई आपने बांध बनाये, न कोई आपने इन्डस्ट्री खोली। आपने वहां कुछ नहीं किया। हां, मालपुरा में तो खोले हैं। कहीं दूसरे क्षेत्र में खोलते तो सही।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है कि आज-कल शहर में कोयले की इतनी कमी हो रही है कि लोग-बागों को खाना पकाने के लिए भी कोयला नहीं मिलता है। मैं मोर्निंग वॉकिंग को जाता हूँ तब देखता हूँ कि जहां चूना पकता है

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

वहां चूने की भट्टी है वहां लोगों को रोटी सेकते देखता हूँ । मैंने उनसे पूछा कि आप इस पर क्यों रोटी बनाते हैं तो उन्होंने कहा कि कोयला मिलता नहीं, यहां पर कोई कोयले का डिपो नहीं है, यहां तो कोयले की मोनोपोली है, क्रय–विक्रय को वही सब को कोयला देते हैं; कोई कोयले का डिपो नहीं है ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जब आगरा, बम्बई दिल्ली और अजमेर में कोयले के डिपो हैं और यहां पर कोई डिपो नहीं, सारी गाड़ियें आती हैं वे सब इनको दे देते हैं । अब मैं आपको कहूँ कि ७.१४ नये पैसों का कोयला आता है उसको ८.७४ पैसे के भाव से बेचते हैं । उनको सरकार धन राशि देती है । न उनका कभी ऑडिट होता है, न इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कितना कोयला किसको देते हैं । अभी नव-निर्वाचित सदस्य जो बूंदी से आये उन्होंने फरमाया कि लकड़ी का इतना अभाव है कि रोटियां नहीं बनतीं । इसलिए यदि लकड़ी न मिले तो कोयला तो देना ही चाहिये । मगर यह सब पार्टी बेसिस पर कर रहे हैं । इसलिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि इसके लिए अलग डिपो कायम होना चाहिये; जिस प्रकार से अजमेर, आगरा, दिल्ली में है ।

श्री सभापति : श्री अनूपसिंह ।

श्री अनूपसिंह : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : श्री भोगजी भाई ।

(अनुपस्थित)

श्री अनूपसिंह ।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : सभापति महोदय, यह पहली बार तो है नहीं कि मैं इन्डस्ट्री के बारे में अपने कटमोशन मूव कर रहा हूँ । मुझे अफसोस है कि तीन वर्ष पहले भी मैंने इसी प्रकार के कटमोशन्स पेश किये थे और वे के वे आज कर रहा हूँ । यह तीसरी बार है कि आज से तीन वर्ष पहले उठाये वही मुद्दे आज भी उठाने पड़ते हैं । इसका कारण यह है कि जो समय गुजरा है उसमें कोई अन्तर नहीं है ।

माननीय सभापति महोदय, हो सकता है कि यह मेरी गल्ती हो कि मैं इसमें अन्तर नहीं पा रहा हूँ या आपकी तरफ से कोई सुस्ती हो जिसकी वजह से अन्तर कोई पड़ता ही नहीं । मैं आपको अर्ज करूंगा कि मेरे तीन कट मोशन्स हैं । मेरे दो कट मोशन्स इस प्रकार हैं:—

(1) "That the Demand No XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Rs.100/-(to discuss the failure of the Government, in developing Cottage Industries in Balotra)"

(2) "That the Demand No. XXII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/-(to discuss the failure of the Government in developing modern Industries in Distt. Barmer)"

मैं इन दोनों कटमोशन्स को एक साथ प्रस्तुत करते हुये अर्ज करूंगा कि अभी बाडमेर के, मैं मानता हूँ कि आप से बाडमेर बहुत दूर है, लेकिन आपके नक्शे में दूर नहीं है । लेकिन ऐसा लगता है कि वह आपके नक्शे

(श्री अनूपसिंह)

से निकाल दिया हो। खास कर यहां पर इन्डस्ट्रीज़ के मामलों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तीन वर्षों से मैं बराबर इसके लिए निवेदन करता आ रहा हूँ, लेकिन आपके कार्य करने की प्रणाली जो है उसकी दिक्कत है। आपके शासन के पास बाडमेर के लिये न कोई फैक्ट्स हैं, न कोई फिगर्स हैं, न कोई कार्यकर्त्ता आपका वहां ऐसा है जो आपके पास बैठ कर आपसे यहां के लिये बातचीत करे और यहां की इन्फॉर्मेशन आपको दे। न आपके और उसके पास कोई फैक्ट्स-एन्ड फिगर्स का डेटा है। आप यह चाहते हैं कि आप कोटा को दूसरा कानपुर बनाकर बता दें। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप कोटा को दूसरा कानपुर बना कर दिखा देंगे, क्योंकि वह भी तो राजस्थान का एक पार्ट ही है। वह तो बढ़ेगा, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि एक जिले को आप कानपुर बनाने जा रहे हैं और दूसरे को ऐसा ही छोड़ देना चाहते हैं और जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहते। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री के लिये यह कोई प्रशंसा की चीज़ नहीं होगी और इसको मैं बार बार दोहराता आ रहा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह अर्ज करूं कि बाडमेर में आप पूछेंगे कि वहां पर इन्डस्ट्रीज़ की जरूरत क्या है जिससे कि वहां पर इन्डस्ट्री होनी चाहिये? इसके लिये मैं यह अर्ज करूंगा कि वह अकालग्रस्त एरिया है, इसलिये वहां पर लोगों को मजदूरी का चान्स बहुत कम मिलता है। वहां के लोगों को मानसून पर ही निर्भर रहना पड़ता है और जब मानसून फैल हो जाता है तो वहां के लोगों के पास कोई धन्धा नहीं रहता है। यह आपसे किसी से छिपा नहीं है। अगर वहां पर कोई इन्डस्ट्री खड़ी होती है तो वहां पर सस्ती लेबर मिल सकती है। इससे लोगों को कुछ मदद मिल जाती है और लोग अकाल ग्रस्त होते हुए भी वहां पर अपना काम चला सकते हैं, वैसी चीज आपके सामने रखता हूँ, मगर आप उस पर कोई ध्यान नहीं देते। तो इसका मतलब क्या निकलता है? जब आपके सामने एक चीज बार बार रखी जावे और आप उस पर कोई ध्यान नहीं दें तो इसका मतलब साफ यही निकलता है कि उसकी तरफ ध्यान देने की आपकी इच्छा नहीं है और हमारा बार बार आपके सामने कहना भैंस के सामने भागवत पढ़ना है, जो आपके कानों को जंचती नहीं।

अब आप मुझे यह यह पूछेंगे कि क्या आप प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में यह चाहते हैं? मैं यह कहूँगा कि आप जिस प्रकार चाहें वैसा करें। वहां पर जैसे जिप्सम काफी मात्रा में निकलता है मगर वहां पर कोई फैक्ट्री आदि नहीं होने से वह जिप्सम फर्टीलाइजर फैक्ट्री सिंदरी तक जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि वहां पर कोई फैक्ट्री नहीं होने से वहां के लोगों को जितना फायदा पहुँचना चाहिये नहीं मिलता। जिप्सम रॉ मेटीरियल की हालत में सिंदरी जा सकता है। सिंदरी में वह हजारों मजदूरों को मजदूरी दे सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि वह रॉ मेटीरियल आपके राजस्थान से ही जाता है जिसके लिए आपने कोई ध्यान नहीं दिया।

(श्री अनूपसिंह)

जिप्सम के साथ साथ और भी कई चीजें हैं, जैसे बोन्स की फैक्ट्री वहां पर खुल सकती है, क्योंकि वहां पर ऐसा एरिया है कि वर्षा कम होती है और वहां के लोग जानवरों को पालते हैं और अपना गुजर करते हैं। जहां पर ज्यादा जानवर होंगे वहां पर मरते भी हैं। वहां की हड्डियों से रीवां में बोन्स फैक्ट्री बनी है और जयपुर में भी बोन्स आती हैं, मगर वहां पर कोई उनके लिये फैक्ट्री नहीं।

उसके साथ hydes and skins निकलता है। इस पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया और अगर दिया है तो भी इनइफेक्टिव होगा जिसको पूरा करने के लिए आपने ध्यान नहीं दिया। अगर आपमें इतना साहस है कि आप अपनी गलती को मानते हो तो मैं समझूँगा कि आप में हिम्मत है। कोटा को कानपुर जब आप बनाना चाहते हैं तो इसकी उपेक्षा किस प्रकार से कर रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ वहां जानवर ज्यादा हैं। वहां पर भेड़े ज्यादा हैं और इसलिये वहां पर वूल इन्डस्ट्री हो सकती है। वहां पर जिस तरह की भेड़े हैं और उनसे ऊन निकलती है मैं समझता हूँ कि वैसी ऊन सिवाय बीकानेर के और कहीं नहीं निकलती है। वहां–बाड़मेर से बहुत ऊन बाहर जाती है लेकिन वहां पर कोई वूल प्रेसिंग की फैक्ट्री नहीं है। कुल बाहर जाती है उनसे वहां के लोगों को जो चार पैसे मिलते हैं उन्हीं से काम चलता है। मैं यह कहूँगा कि आप इतने बड़े इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट को लेकर बैठे हैं वह क्या 'नौ की तेरह' किया करता है?

इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि घी को ठीक करके गवर्नमेंट को फैक्ट्री से जो एगमार्का घी निकाला जा सकता है। मैं समझता हूँ कि बाड़मेर से घी एक्सपोर्ट होता है और राजस्थान के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाता है। फिर आपने वहां के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको किसी प्रकार से फायदा पहुँचाने का अपने दिमाग में नहीं सोचा।

मैंने जो कुछ भी आपके सामने रखा है, वह इलाका ग्रस्त होने से, कच्चा माल मिलने से और सस्ती मजदूरी मिलने के कारण वे चीजें मिल सकती हैं।

आप कह सकते हैं कि आपके यहां पानी नहीं है....

श्री सभापति : Come to your third cut motion please.

श्री अनूपसिंह : यह तो टाइम लेगा। तीन वर्ष में भी किसी ने ख्याल नहीं किया।

श्री सभापति : You can exhaust your 15 minutes either way as you like.

श्री अनूपसिंह : पानी की सिर्फ आप वहां कमी बता सकते हैं। वह भी सिर्फ आपकी वजह से। आपने सिनियरिटी से उसको नहीं देखा है कि वहां पर पानी निकल सकता है या नहीं। आप एक करोड़ रुपया भी खर्च करके बता देते कि हमने इतनी मेहनत की, लेकिन वहां पर पानी अवेलेबल

(श्री अनूपसिंह)

नहीं है। सोमेंज़ में आपको बताता हूँ। बालोतरा की लूनी नदी के किनारे पर यदि खुदवायें तो वहां जितना पानी चाहिये निकल सकेगा, इन्डस्ट्री के लिए और अन्य कामों के लिए आपको वहां पर पानी मिल सकता है। जहां पर हर साल मेला लगता है, लाखों लोग आते हैं, लाखों मवेशियां इकट्ठी होती हैं और वे उसी नदी से पानी पीती हैं। वह आता कहां से है? वह तो नदी में से ही आता है। आपने एक्सपर्ट्स करके वहां पर पानी के निकालने की कोशिश नहीं की। मान लिया कि आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप वहां करना चाहते हैं जहां कि आपका स्वार्थ निहित है। आप कहेंगे, हमने वहां पर काम किया है। क्या किया है? बालोतरा में कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ रखी हैं। बहुत सी इन्डस्ट्रीज़ हो सकती हैं; रंगाई-छपाई, चर्म उद्योग, हाथी दांत आदि। उन रंगाई के उद्योगों को नया नया डिज़ाइन देकर, नये ढंग देने से वे कम्पीटिशन में मार्केट में स्टेन्ड कर सकें, उनको इस प्रकार से लाने की आपने कोशिश नहीं की। सभापति महोदय, यह मानी हुई चीज़ है कि सैकड़ों वर्षों से जो उद्योग चलता आ रहा है, लोग अपने तरीके से काम करते हैं। अभी भी वहां पर वे ही चीजें निकलती हैं कि औरतों के घाघरे की छींटें वैसी ही निकलती हैं जो कि पचास वर्षों से निकलती चली आ रही हैं। आपने उनको मोडल और नवीन तरीके से बनाने के लिए कोई कोशिश नहीं की, ट्रेनिंग नहीं दी गई। जो नवीन स्टेन्डर्ड के लिए कोशिश आपकी ओर से होनी चाहिये थी वह नहीं की गई। आप कहते हैं कि सांगानेर की छपाई के मुकाबले में कोई दूसरी इन्डस्ट्री कम्पीटिशन में खड़ी नहीं हो सकती। बालोतरा हो सकता था। आपने कुछ नहीं किया उसके लिए। चर्म उद्योग का भी वहां पर अच्छा स्कोप है, हाइड एन्ड स्किन टेनिंग के लिए कुछ नहीं किया। बड़ा स्कोप है, फिर भी कुछ नहीं किया। बालोतरा में पर्याप्त पानी है, फिर भी किसी दिन उसको टेप-आउट नहीं किया गया।

आखिर में एक मुद्दा रखते हुए अर्ज करूंगा कि बाड़मेर में पता नहीं डिस्टेन्स है यहां से या और कोई चीज़ है और हम जहां हैं वहीं पर हैं और हमारी खबर भी नहीं आती। खबर आती नहीं और जाती नहीं। सीमेंट, लोहा, केरोगेटेड शीट्स वितरण करने का तरीका है वह इतना ज्यादा फॉल्टी है कि २७ लाख सीमेन्ट की प्रोडक्शन की जगह ८४ लाख टन हो गई है। ५२ में जो प्रोडक्शन था वह ६० में चार गुना बढ़ गया है। हम समझते थे कि सीमेन्ट ठीक मिलने लगेगा। चार गुना प्रोडक्शन बढ़ा है तो डिस्ट्रिब्युशन इतना फॉल्टी हुआ है कि गवर्नमेंट उन चीजों को मुहैया नहीं करती। सीमेन्ट की बोरी काश्तकार को नहीं मिलती, कोई काश्तकार कुंए के ऊपर मरम्मत करना चाहे और कोई जरूरी काम करना चाहे तो उनको नहीं मिलती। मंत्री महोदय के लिए यह फक्र की चीज़ हो सकती है, काश्तकार भूखे बैठे रहें, चाहे कुछ न कर सकें, सीमेंट नहीं मिलता उनको, लेकिन मंत्री महोदयों को चाहने वाले और उनके पीछे फिरने वाले आदमियों के लिये लाखों टन बोरे लिये बैठे

(श्री अनूपसिंह)

रहते हैं। यह मंत्री महोदय के लिए कोई फक्र की चीज़ नहीं है।

सवाई माधोपुर में सीमेंट निकलता है, अलग अलग कोटा वाले लेकर चले जाते हैं, खर्च कर सकते हैं या नहीं उनको पता नहीं। रिपोर्ट तो यह है कि बरसात में बोरियां सीमेंट की भीग जाती हैं और हमारे लिए काम में नहीं आतीं। इस तरह से काश्तकार बिना सीमेंट के बरबाद हो रहे हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार से लोग दबाये बैठे हैं या बरबाद कर रहे हैं।

सीमेंट के साथ साथ आइरन, स्टील और चद्दरें; इनका वितरण इतना फॉल्टी है, माननीय सदस्यों ने बताया....

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

श्री सभापति : Time is up please.

एक माननीय सदस्य : क्या ये जरूरी बातें हैं ?

श्री अनूपसिंह : कोटा किनको देते हैं ? पर्मिट वालों को। जिनको जरूरत है उनको मिलेगा नहीं, उनको मालूम नहीं पड़ता उसके पहले ही सीमेन्ट आदि समाप्त हो जाते हैं। अव्वल तो इत्तला ही नहीं मिलती और अगर इत्तला मिली और पहुंचे तो कह दिया गया कि माल समाप्त हो गया और बाद में वे लोग ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। हजारों एप्लीकेशन्स पड़ी हुई हैं, पर्मिट्स मिल गये हैं। दें किसको और ले किससे ? बाड़मेर में वैसे सीमेन्ट और आइरन शीट का एक टुकड़ा नहीं मिलता और यदि ब्लैक से लें तो हजारों शीट्स मिल सकती हैं। वे कहां से आये ? अगर डिस्ट्रिब्युशन फॉल्टी नहीं होता तो ब्लैक में ये चीजें नहीं मिलतीं। आप कहते हैं कि मैं असहाय हूँ....

श्री सभापति : You are supposed to be addressing the Chair please. not the Minister directly.

श्री अनूपसिंह : Through you, Sir.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : No question of 'supposed to'. He has actually to address the Chair.

श्री सभापति : That is what I say.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह बात बिल्कुल गलत है। आपकी मार्फत होना चाहिये।

श्री सभापति : That is why I had to warn him.

श्री अनूपसिंह : इसलिए अर्ज करूंगा कि ब्लैक मार्केट चल रहा है और आप कहते हैं कि ब्लैक मार्केट रोक नहीं सकता। राजस्थान के मन्त्री महोदय कहते हैं कि मैं ब्लैक मार्केट रोक नहीं सकता....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : आप फरमाते हैं। "आप" कह रहे हैं।

श्री सभापति : Yes, that is not permissible.

श्री चन्दनमल वैद : आपके ऊपर चार्ज लगा रहे हैं।

श्री सभापति : That is why I had to warn him on two previous occasions.

श्री अनूपसिंह : मेरे ये मुद्दे हैं । वे उनका जवाब दें । ब्लैक मार्केट को जब तक खत्म करके न बता दें तब तक मैं समझता हूँ कि यह डिपार्टमेन्ट किसी काम का नहीं है । वे नहीं कर सकते तो बैटर है, यदि चरित्र है तो उसको छोड़ दें ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir, I want your ruling on this. You encourage the moving of cut motions and give the movers a chance to speak. It is not the policy. Other members are also there. They must have their share also.

श्री सभापति : They have every right to move the cut motions.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I want to oppose the cut motions.

श्री सभापति : I am sorry, there will be no end to it, and the debate would not be completed within time. You may please take your seat.

Shri Sohan Lal to move his cut motion.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, लार्ज और मीडियम साइज़ की इन्डस्ट्रीज़ की राजस्थान में कमी रही है । इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है । दो पंचवर्षीय योजनायें हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मीडियम और लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज़ का सवाल है हम इस ओर आगे नहीं बढ़ पाये हैं । राजस्थान सरकार के अथक प्रयत्न के बावजूद भी हम इसकी देहली पर ही हैं । माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की केवल ६ प्रतिशत आबादी उद्योगों पर आश्रित है और ९१ प्रतिशत आबादी कृषि और दूसरे कामों पर आश्रित है । नियोजित अर्थ व्यवस्था के लिये यह बहुत आवश्यक है कि इतनी बड़ी आबादी कृषि और दूसरे क्षेत्र में लगी हुई है, उसके लिये किस प्रकार से व्यवसाय बढ़ाया जाय और इसी दृष्टिकोण को लेकर हमारे यहां पंचवर्षीय योजनायें बनाई गई हैं । यदि उसके अनुसार उद्योग बढ़ते हैं तो हमारी ६० प्रतिशत आबादी के उद्योग—धन्धे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिस गति से हम चल रहे हैं उस गति से उस लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना नजर नहीं आती ।

सभापति महोदय, सरकार ने बहुत प्रयत्न किया है निजी व्यवसाइयों को इस ओर आकर्षित करने के लिये, कई कन्सेशन्स भी दिये गये हैं । जब कि हमने समाजवादी समाज की व्यवस्था की नीति को सामने रखा है और उसी नीति को अपनाने के कारण हम यह भी चाहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र भी व्यापक हो । आज हम तृतीय योजना के प्रथम वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन जब हम पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति को देखते हैं तो हमें विदित होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कोई भी लार्ज और मीडियम उद्योग नजर नहीं आते; ६ लाख रुपया और ४ लाख रुपया डेवलपमेन्ट ऑफ इन्डस्ट्रियल एरिया के लिये रखा है । सोडियम सल्फेट के लिये

(श्री सोहनलाल भटनागर)

४ लाख रुपया रखा है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र से इसका कोई मतलब नहीं। जितने भी कल-कारखाने चल रहे हैं उनको ले लिया जाय, तो यह बात बिल्कुल निश्चित है कि भविष्य में जितने भी कारखाने हों उनको कहां कहां खोलना है, उसके काफी हद तक कौनसी जगह ठीक हो सकती है, इसको देखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की योजना उप-समिति ने जो नीति बताई है उसके अनुसार चलना चाहिये। मौजूदा निजी बड़े उद्योग निजी उद्योग क्षेत्र में चलते रहेंगे और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। जहां काफी गन्ना पैदा होता है, कपास पैदा होता है, स्मल्टिंग के लिये काफी अच्छी जगह हैं, इन सारे दृष्टिकोण को देखते हुए नये उद्योग-धन्धे खोलें और निजी क्षेत्र में खुलते हैं तो सरकार ७० प्रतिशत रुपया कर्जे के रूप में, सब्सिडी के रूप में, कन्सेशन के रूप में मदद कर सकती है। सभापति महोदय, जब बजट के सम्बन्ध में वाद-विवाद हो रहा था सदन के कतिपय सदस्यों ने यह कहा कि हमें नोन टैक्सेबल रेवेन्यू को भी बढ़ाना आवश्यक होगा, जब हम सार्वजनिक क्षेत्र के अन्दर ऐसे उद्योग खोलें। मैं मानता हूँ, कुछ उद्योग; जैसे सोडियम सल्फेट आदि ऐसे उद्योग हैं जिनके लिये कहा गया और घोषणा भी की गई। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने खुद ने कहा था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये। इसके बारे में जो राष्ट्र की नीति है उसी के अनुसार हमें चलना है। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि जितने भी बड़े उद्योग हों वे सार्वजनिक क्षेत्र में खुलें, लेकिन उसके साथ साथ निजी क्षेत्र में चलने वाले उद्योगों को भी हमें प्रोत्साहन देना चाहिये। मुझे खुशी है कि जिंक स्मेल्टिंग प्लान्ट के लिये फेरिन कोलोबोरेशन द्वारा, मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इन्डिया द्वारा यह उद्योग चलाया जायगा। अगर सार्वजनिक क्षेत्र में यह होता तो राजस्थान को काफी लाभ होता। वह निजी क्षेत्र में खोला जाए, इस ओर ध्यान जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिये।

इसके अलावा मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज हमें जिन जिन इन्डस्ट्रीज़ को खोलना है, जिस तरह से बिजली इन्डस्ट्री होनी चाहिये, मशीन्स के बारे में बातचीत चल रही है, राजस्थान इस बारे में प्रयत्नशील है कि इस प्रकार के उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में खुलें; तो ये चीजें राजस्थान के विकास के लिये काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं।

इसके अलावा एक बात जिस ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ; म्युनिसिपल एरियाज़ हैं। उनके लिये सीमेन्ट और चद्दरों का कोटा नहीं दिया जाता है। सीमेन्ट और लोहे के बारे में जो ब्लैक मार्केटिंग होता है उस बारे में माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है। मेरे ख्याल से इस बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। इस ओर माननीय मन्त्री महोदय ध्यान देंगे और इस समस्या को सुलझायेंगे। गये महिनों में पंचायत समितियों को अलग तौर से कोटा दिया गया। उसकी वजह से गांव के अन्दर कुछ मात्रा में सीमेन्ट और लोहे का

(श्री मोहनलाल भटनागर)

सामान उपलब्ध होने लगा है । इसके साथ साथ जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं जिनकी आबादी आठ हजार से ऊपर है उनको डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से कोटा मिलता है । इसके अलावा इनसे जो छोटी नगरपालिकायें हैं उनको वहां नहीं मिलता, उनको जिला हैडक्वार्टर पर जाना पड़ता है, चालीस–पचास मील का फासला तय करना पड़ता है । इससे काफी समय और असुविधा उनको होती है, इस ओर भी मन्त्री महोदय ध्यान देंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री सभापति : श्री लादूराम सुलाणिया ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह (श्रोमाधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, इस मांग पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं । एक प्रस्ताव तो इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट द्वारा जो कन्ट्रोल्ड आर्टिकल्स दिये जाते हैं उनके वितरण के सम्बन्ध में है । उनमें जो इस प्रकार की अनियमितता होती है उस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये है और दूसरा कटौती का प्रस्ताव खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के सम्बन्ध में है ।

सभापति महोदय, यह कुछ दुर्भाग्य है कि आज सदन के कतिपय माननीय सदस्यों ने खादी का प्रचार कर यह दर्शाने की चेष्टा की है, जैसे खादी के पहिनने का अधिकार, खादी के उद्योग पर विचार करने का अधिकार और खादी किस प्रकार से बनती है इसके विश्लेषण का अधिकार केवल उन्हीं को है । जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने खादी के सम्बन्ध में जिस प्रसंग को लेकर बात कही थी उसी प्रसंग से परे हट कर माननीय सदस्यों ने इस बात को बताने की चेष्टा की है कि हम सब खादी के विरोधी हैं । सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस जोश के साथ भाषण दिया उस आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि उनको छः महीने पहले की बात याद नहीं रहती है इसीलिये मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष बजट अभिभाषण पर बोलने का मुझे मौका मिला था, उस समय मैंने खादी की वकालत की थी....

श्री सभापति : Are you speaking on cut motion No. 64 or 65 ?

श्री भैरोंसिंह : On both, Sir. इस स्थिति में मैं आज कह सकता हूँ कि खादी को आप जिस स्थिति के अन्दर देखते हैं उससे भी बढ़ कर भगवान के रूप में हम खादी को मानते हैं और मैं उनको यह बता सकता हूँ कि जिस प्रकार से खादी के प्रति अनुराग है, खादी गरीबों का जीवन है; इन दोनों बातों को मेरा दल इसी प्रकार से स्वीकार करता है ।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : Except the member from Johri Bazar.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, जिस प्रकार से मैंने बताया, खादी भगवान है । वहां यह आवश्यक होता है कि भगवान के जो पुजारी हों वे पवित्र हों । यह हमारा दुर्भाग्य है कि इसकी पूजा करने का काम हमारे आज के सत्तारूढ़ दल को मिला है ।

(श्री भैरोंसिंह)

सभापति महोदय, आज से कुछ दिनों पहले हिन्दू ट्रस्ट बिल हमने पास किया था और उसकी पृष्ठभूमि में यह बताया था कि मन्दिर का पुजारी भगवान की पूजा में कोताई रखता है, इसलिये प्रबन्ध सरकार को लेना चाहिये। मैं आज कह सकता हूँ कि जिस मन्दिर में बैठे हुए भगवान की पूजा में कोतई करने वाले के लिये कानून बना रहे हैं आप, तो हम क्या इस बात को नहीं कह सकते कि खादी रूपी देवता को बदनाम करने वाले का चालान किया जावे? क्या हम यह नहीं कह सकते कि खादी गरीबों की रोजी है, उस पर हमला करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जावे और हमारे इस कथन को आप यह कहें कि खादी को हम टोर्चर कर रहे हैं, खादी के विरोध में बोल रहे हैं! हमें नहीं बता रहे हैं, खादी क्या है, इसका उत्पादन किस प्रकार से होता है, खादी से किस प्रकार से रोजगारी की समस्या का समाधान होता है, यह आपको जन-मानस में पहुंचाना पड़ेगा और इसके लिये पत्र छपवा कर नहीं, समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर नहीं, बल्कि हमारे जीवन में जो क्षण-क्षण निकलता है उसमें खादी के द्वारा जो भावनाएं हमारे मस्तिष्क में, हृदय में प्रेरणा होती हैं उनको हम किस प्रकार से कार्य रूप में परिणत करते हैं उससे प्रमाणित होगा।

एक ने कहा पान की दूकान पर जाने वाले लोग खादी की आलोचना करते हैं। मैं इस बात को गौरव समझता हूँ कि हमारा स्थान पान की दूकान हो सकता है, सड़क हो सकती है और गली और कूंचे हो सकते हैं और हम उन स्थानों से नफरत करते हैं जो महलों में बैठ कर पान की दूकानों की आलोचना करना चाहते हैं। पान की दुकान और खादी का सामंजस्य बैठ सकता है, पर खादी और महलों का सामंजस्य नहीं बैठ सकता। ऐसी स्थिति में एक माननीय सदस्य जिस आवेश में यहां आ गये और जो गाली दे गये, सभापति महोदय, मैं यह स्पष्ट कहूँगा कि आज इस दुनिया में इससे बड़ी गाली और कोई नहीं हो सकती कि कोई व्यक्ति एक दूसरे के बारे में यह कहे कि ये एन्टी—नेशनल हैं और वे ऐसा इल्जाम लगावें। इसके पहले मैं उनसे यही कहूँगा कि वे पहले अपना खुद का मुंह आइने में देखें और एन्टी-नेशनल किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा की जानकारी करें और उनके ख्याल से या फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य के ख्याल से हम एन्टी-नेशनल नहीं, वह सरकार एन्टी-नेशनल है जो उन गद्दारों को पकड़ कर रोक नहीं सकती, हमें जेल के सींखचों में नहीं रख सकती। तो मैं कहूँगा वह सरकार भी एन्टीनेशनल है। जैसे कोई गाजर-मूली की बात है उस तरह की बात मुंह से निकाल देना, यह छोटी बात नहीं है। आज भारत के नागरिक के लिए कोई गाली हो सकती है तो 'एन्टीनेशनल' सबसे बड़ी गाली हो सकती है और ऐसा कह कर कहने वाले ने नेशन के प्रति जो भावना होनी चाहिये उस भावना का तिरस्कार किया है।

मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो दो वर्ष पहले इन्हीं माननीय सदस्यों ने यहां कहीं। मैंने उनके दो वर्ष के पहले के भाषणों को सुना है जिन्होंने अपने नेता को 'डाकू' बताया था। पिछले वक्त के उनके भाषणों का हवाला नहीं देना चाहता जिनमें

(श्री भैरोंसिंह)

उन्होंने इस सरकार को दिवालिया बताया था और पुलिसको राक्षस इन्हीं सदस्यों में से कइयों ने बताया था।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यहां कट मोशन से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सभापति : Please confine yourself to the cut motions.

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : And not such vague and hypothetical allegations.

श्री सभापति : You say that you don't want to say something and still you are saying it.

श्री चन्दनमल वैद ; जिन्होंने राक्षस बताया उनकी कॉन्स्टीट्युएन्सी का नाम बताइये, केवल कह देना काफी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप इनमें नहीं समझते।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इतिहास नहीं बताना है आपका। आज सदन में कुछ कहते हैं, कल कुछ; इसका प्रभाव जन-मानस पर पड़ता है। छः महीने पहले कही बात के विपरीत जब कहते हैं और आज उससे उल्टी बात जन प्रतिनिधि के मुंह से निकलती है तो जनता पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। किसी हद तक, कहां तक हमारा डीमोरेलाइजेशन हो गया है, हम कहां तक गिर गये हैं, यह इसका द्योतक है। इससे आगे मैं नहीं कहना चाहता।

दूसरे प्रसंग में कहूँगा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। इस मन्दिर के महन्त और पुजारी कौन ? पुजारी अगर अयोग्य हैं और पुजारी पर अगर सन्देह है तो भगवान की पूजा करने का उनको अधिकार नहीं है और किस प्रकार से अयोग्य हैं, मैं दो मिनिट में बताना चाहूँगा कि आखिर खादी क्या है ? किस प्रकार से इससे लोगों को रोजगार मिलता है? मिलता भी है या नहीं, मिलता है तो वह रोजगार किनको, किस तरह से मिलता है ? खादी में सूत बदलना और स्वालम्बन ये दो शब्द कहे जाते हैं। ये दो शब्द इस प्रकार के हैं जिनके प्रति लोगों का अनुराग है। इन शब्दों के कारण से भयंकर घोटाले होते हैं सूत बदलने के नाम पर। सूत का जो सारा खाका खींचा गया वह मैं आपको बताता हूँ। जिस समय कपास काश्तकार ले जाकर जिस व्यक्ति को देता है उस समय से उस पर रिबेट शुरू होता है। जिस समय कपास बेचेगा तो रिबेट मिलेगा, कपास के बाद में जो उसको धुनेगा, उसको लोडेगा, जो बुनाई होगी, जो कताई होगी उस सारे पर रिबेट मिलता है और कताई के बाद बिक्री होगी तो उस पर फिर रिबेट मिलता है। आज खादी में एक व्यवस्था चलती है। खादी के अकाउन्ट में लिख दिया जाता है, भैरोंसिंहजी ने ५ मन कपास दी, फलां आदमी ने लुड़ाई की, फलां ने बुनाई की, फलां ने कताई की और फलां ने कपास का कपड़ा बनाया। बिक्री का जो रिबेट होता है उसको भी जोड़ कर रजिस्टर में एन्टर कर दिया जाता है। खादी बिकी नहीं, खादी बनी नहीं, सूत कता नहीं, न सूत को धुनाई हुई

(श्री भैरोंसिंह)

और बुनाई भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ और रिबेट सब का मिल गया। रजिस्टर में देखते हैं तो सब मिल गया। राजस्थान में इस तरह से कई संस्थाएं हैं जो इस महीने में आज खादी का ५०० गज कपड़ा बनाती हैं और रिबेट क्लेम करती हैं और दूसरे महीने में पांच हजार गज कपड़े पर जितना क्लेम हो सकता है रिबेट क्लेम करती हैं। आप अन्दाजा लगाइये एक सदन के माननीय सदस्य ने जो फुलेरा से आये हैं एक-दो सोसाइटियों का नाम लेकर कहा है, कि इस तरह से इतनी में एक-दो सोसाइटियों की गल्तियां हो सकती हैं, पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वे किसी एक भी ऐसी खादी संस्था का नाम लें जिसे वे यह समझते हैं कि उसमें इस तरह का घोटाला नहीं है? आप किसी भी खादी संस्था का नाम लें, मैं ऑडिट रिपोर्ट दिखाने की चेष्टा करूंगा कि किस प्रकार का घोटाला है; जिसको आप छिपाना चाहते हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि खादी के प्रति और खादी की जिस प्रकार की व्यवस्था है उसके प्रति हमें गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। व्यवस्था के कारण आज लोगों को भी इसके नाम पर टैक्स देना पड़ता है। हम भी चाहते हैं खादी पहनें। हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि हम सब खादी पहनें। पर इतनी ऊंची कीमतें हम नहीं दे सकते। उन कीमतों के आधार पर हम खादी नही ले पाते। रिबेट के बाद भी कीमतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। मैं आज अगर लेना चाहूँ तो ३०) के धोती जोड़े से कम पहन नहीं सकता। मेरे जैसा साधारण श्रेणी का आदमी चाहे तो भी पहन नहीं सकता। इसलिये मजबूर होकर थोड़ी बहुत किसी न किसी प्रकार से मजदूर का श्रम लगा है वह कपड़ा पहनते हैं।

इस स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूँगा, मोटे रूप में कह सकता हूँ कि राज्य में जितनी खादी बनी है जिसका रिबेट के हिसाब से अकाउन्ट मेन्टेन किया गया है, उस खादी के उत्पादन के सभी आंकड़े जोड़े जावें तो राजस्थान के ऊपर चार चद्दरें बिछा दें तो भी कम नहीं पड़ेगी। पर वास्तविक स्थिति यह है कि यह सारी खादी हिसाब में, किताबों में ही बनी है। लोगों को पहिनने को नहीं मिलेगी।

अब रहा ग्रामोद्योग बोर्ड के सम्बन्ध में। खुद हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने स्पष्टीकरण किया और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि उस स्पष्टीकरण के द्वारा स्वतः वित्त मन्त्री पर जो चार्ज लगाये गये थे उनको उन्होंने स्वीकार किया एक लहजे में, उनको बचाने की चेष्टा की, पर आज कोई यह नहीं कह सकता कि जितने जिस प्रकार के काम हुए हैं उन कामों में वह किसी भी प्रकार के दोषी नहीं हैं। वे दोष-मुक्त हैं। इस प्रकार की बात सदन में कोई नहीं कह सकता और अब तक जितने भी सदन में भाषण हुए उस पक्ष से भी उनमें भी किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं कही है, बल्कि विपरीत बातें कही हैं कि वे दोषी हैं। मैं कहूँगा कि खादी में जिस प्रकार के सिद्धान्त की भावना है, खादी में जिस प्रकार की पवित्रता है, खादी के पीछे जिस प्रकार गांधीजी का नाम बोलता है, वे सारी चीजें हमारे वित्तमन्त्री में बोलनी

Page No.107

(श्री भैरोंसिंह)

चाहिये। कोई उनकी ओर अंगुली उठाकर भी नहीं देख सके ऐसा होना चाहिये। बाकी के कामों के लिये भले ही अंगुली उठावें, पर खादी के नाम पर उन पर कलंक आता है जो अपने आपको धर्मावतार, गांधीवादी, सत्यवादी, परमहंस और सन्यासी कहते हैं। तो उस स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने उनको बचा लिया, यह समझ कर वे न चलें; मुख्य मन्त्रीजी की नजरों में वे ऊंचे हैं, यह समझकर वे न चलें। उन्होंने बहुत प्रकार की बातें कह कर उनको गिराने की चेष्टा की है और गिराया है।

श्री सभापति : Your time is up.

श्री भैरोंसिंह : इसलिये कहना चाहूँगा सभापति महोदय, माननीय वित्त मन्त्रीजी को खादी के बारे में सारा स्पष्टीकरण स्वयं को इस सदन में रखने की चेष्टा करनी चाहिये और मन्त्री महोदय पर सदन के प्रांगण में चार्जेज़ लगाये गये हैं इस कारण मुख्य मन्त्रीजी के शब्दों से स्पष्टीकरण नहीं चलेगा।

दूसरा कटमोशन मेरा था। उसमें था जितनी कन्ट्रोल कोमोडिटीज़ है उनके वितरण के सम्बन्ध में। मैं इस सम्बन्ध में उन सारी बातों का जिक्र नहीं करना चाहूँगा। मेरे पास कई प्रकार के आंकड़े हैं, कई फर्मों के नाम हैं जो बोगस हैं, जिनके नाम के केवल बोर्ड लगे हैं और उनको कन्ट्रोल्ड कोमोडिटीज़ मिलती है। बड़े–बड़े कोटे मिलते हैं, जिनमें डबल ब्लैक मार्केट की गुंजाइश है। के० डी० माथुर, कोई भारत फैक्टरी, शारदा फैक्टरी, मुरलीधर झुंझुनूवाला के नाम से और अन्य अन्य नामों से ये फैक्टरियां चल रही हैं। कई एक माणकचन्द एण्ड गुप्ता के नाम से चल रही हैं। मैं माननीय उद्योग मन्त्री से कहूंगा कि वे इनके प्रोडक्शन की जांच करें। रात-रात भर मीटर का खर्चा मीटर की सुई घुमाकर या किसी तरह बताकर लोगों को गुमराह करने की चेष्टा करते हैं ये कहना चाहते हैं कि सारी रात मीटर चला है। बाल्टी और बक्सों के लिए जितना लोहे का कोटा दिया गया है उसके अनुसार तो इतनी बाल्टियां और बक्से बन चुके हैं कि सारे राजस्थान की १॥। करोड़ जनता एक एक बाल्टी में पैर देकर खड़ी हो जावे तो सारी बाल्टियां उसमें नहीं आ सकतीं। इतनी बाल्टियों और बक्सों का काम हुआ है। इतने बन गये। वे बाल्टी और बक्से जितने भी आपके सामने आते हैं सारे किताबी आंकड़े हैं। उनके लिए जो लोहा दिया जाता है वह सारा सीधा बेच दिया जाता और वह ब्लैक का सामान जो ब्लैक में बेचा जाकर ब्लैक का सामान हो गया है आपके राजस्थान में नहीं रहता, बाहर चला जाता है। जिन हम लोगों को उद्योग-धन्धे मिलने चाहिये, उनको उद्योग धन्धे और काम नहीं मिलता। उनका धन्धा छीनकर आज के हमारे तथा कथित व्यापारी और उद्योगपति कलकत्ते–बम्बई ले जाते हैं और वहां उस रॉ मेटीरियल का ब्लैक करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अपने उद्योग मन्त्री से कि क्या इसी के बलबूते पर, इसी के बेसिस पर आप यहां उद्योग पनपा कर लोगों को सहायता और रोजी रोटी देना चाहते हैं? यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रोडक्शन के आंकड़े न बतावें। राजस्थान में कपड़ा ज्यादा हो रहा है, शुगर ज्यादा हो रही

(श्री भैरोंसिंह)

है पर वास्तव में ये फिगर्स आपके गलत साबित हुए हैं।

आप कहते हैं कि उद्योग पनप रहा है, जब कि तथ्य यह है कि आप इसे साबित नहीं कर सकते। आपके राजस्थान का गोटा उद्योग, बर्तन उद्योग, चूड़ी उद्योग मर रहे हैं ये सब उद्योग। हाथी दांत का आपका उद्योग मर गया और जो इनके एक्चुअल मैनुफेक्चरर्स हैं उनको रॉ मैटीरियल का कोटा नहीं देकर आज आप मिडल मैन को कोटा देते हैं।

आज जितनी भी चूड़ियां बनाने वाले हैं, खिलौने बनाने वाले और बाल्टी और बक्स बनाने वाले हैं उनको कोटा नहीं दिया जाता है, बड़े-बड़े सेटों को दिया जाता है। आज क्या है कि कोटा मैन्युफेक्चरर्स को नहीं मिलता है और आज उस रूप में जो मिडल मैन को प्रोफिट मिलना चाहिये वह उसको नहीं मिले और जो मैन्युफेक्चरर्स हैं वे चिल्लाते रहते हैं, उनको रॉ मैटीरियल नहीं मिलता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मिडलमैन जो बीच में आ गये हैं उनको अवोइड किया जाना चाहिये और एक्चुअल मैन्युफेक्चरर को कोटा मिलना चाहिये। आज के चार दिन पहले राज्य विधान सभा के सामने २०० आइरन एण्ड स्टील के मैन्युफेक्चरर्स हैं उन्होंने प्रदर्शन किया था और मुझे आशा है कि वे माननीय मंत्री महोदय से भी मिले होंगे। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिलाया था कि अच्छा तुम्हें कोटा मिलेगा। उन्होंने कहा था कि आप मिडल मैन को मत दो, अगर आपको राजस्थान में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है। अगर लोगों को कुटीर उद्योगों द्वारा पनपाना है तो ऐसी चीजें जिनसे ये चीजें पनपती हों उनमें इस बात का ध्यान रखें कि एक्चुअल मैन्युफेक्चरर्स कौन हैं और मिडलमैन कौन हैं और आपको मिडलमैन को अवोइड कर की चेष्टा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूं कि लोगों को धन्धा मिलेगा और यही शब्द कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : माननीय सभापति महोदय,....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, क्या कट मोशन्स का विरोध करने के लिए मेम्बर्स को इजाजत नहीं मिलेगी।

श्री सभापति : Not at all. He is replying.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कल की बहस के दौरान में भी और आज की बहस के दौरान में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में कुछ बातें कही गई। मैं चाहता हूं कि इनका स्पष्टीकरण कर दूं क्योंकि अब समय भी कम रह गया है, इसलिए संक्षेप में ही कहूंगा। एक बात यह कही गई कि सरंजाम कार्यालय ने जो लकड़ी खरीदी उसमें गोलमाल थी। तो मुझे जो जानकारी इसके संबन्ध में मिली है उसके अनुसार मैं आपको बता देता हूं। सरंजाम कार्यालय ने जो लकड़ी नासिक से खरीदी है वह अम्बर चर्खे हेतु आवश्यक साइज़ों के अनुसार चिरी हुई तथा सीज़न्ड लकड़ी है और जो भाव यहां के बताये गये हैं वे गोले के हैं

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

च बिना सीज़न्ड किये हुये के हैं। इसके साथ ही यह लकड़ी किसी प्राइवेट पार्टी से नहीं खरीदी गई है, बल्कि खादी कमीशन के अम्बर सरंजाम विभाग, नासिक से खरीदी गई है। अतः भाव अधिक देना व गड़बड़ करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यह लकड़ी टैक्नीकल दृष्टि से सभी प्रकार से उपयुक्त थी। अम्बर चर्खा डाइरेक्टर के निर्देशन से ही यह लकड़ी खरीदी गई थी। इसलिए यह सन्देह करना मुनासिब नहीं है।

दूसरी बात यह कही गई थी कि एक ऑर्डर दिया गया था सरंजाम कार्यालय को, उसकी पाबन्दी नहीं की गई और दूसरी जगह से माल खरीदा गया। उसके लिए मेरा निवेदन करना यह है कि सरंजाम कार्यालय अम्बर चर्खा, कर्घा तथा ग्रामोद्योग के अन्य प्रकार के औजार बनाता है। ये औजार लकड़ी के होते हैं और लोहा किसी में लगता है तो वह थोड़ी मात्रा में या छोटे पार्ट्स में होता है। लोहे का बड़ा व भारी सामान सरंजाम कार्यालय की तरफ से नहीं बनाया जाता। पहली बार एक दफा सन् १९५६ में सरंजाम कार्यालय को गुड़ खांडसारी विभाग की तरफ से ऑर्डर दिया था, लेकिन सरंजाम कार्यालय की तरफ से कहा गया कि कन्ट्रोल के लोहे का कोटा न मिलने के कारण समय पर माल नहीं बनाया जा सकेगा, तब वह माल दूसरी जगह से खरीदा कोटेशन लेकर और काफी तहकीकात के बाद माल खरीदा गया है। उसमें कोई शंका करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए....

श्री ब्रजलाप्रसाद शर्मा : तो फिर सरंजाम कार्यालय ने टेन्डर क्यों दिया जब कि वह ऐसे औजार बनाता ही नहीं था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे मालूम पड़ा है, उसमें टेन्डर का नियम नहीं है इसलिए टेन्डर नहीं लिया गया।

श्री भैरोंसिंह : ७५ रुपये के हिसाब से जब सरंजाम कार्यालय नहीं बना सकता था तो फिर उसने एप्लाई क्यों किया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो खांडसारी विभाग ने सरंजाम कार्यालय को ऑर्डर दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस खरीद के मामले में एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट ने जांच की थी क्या ; कोई रिपोर्ट दी थी कि सरंजाम कार्यालय से खरीदा जाना चाहिए ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : इसके अन्दर करप्शन ही नहीं है तो फिर एन्टी-करप्शन विभाग क्या जांच करेगा !

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके बाद में यह कहा गया था कि ग्राम—सेवा मण्डल के श्री बालकृष्ण ने एक जमीन खरीदी है और उसकी अपने नाम से रजिस्ट्री कराई है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने पूछा था कि इसकी एन्टी—करप्शन डिपार्टमेंट ने जांच की थी क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरी जानकारी के अनुसार एन्टीकरप्शन में इसकी शिकायत ही नहीं है। लेकिन मैं कह देता हूँ कि जो रजिस्ट्री हुई है वह बालकृष्ण गर्ग, सेक्रेटरी

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

ग्रामसेवा मण्डल के नाम से हुई है, अकेले बालकिशन के नाम से नहीं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ओन ए पोइन्ट ऑफ इनफोर्मेशन, सर, मैं किसी चीज पर ज्वालाप्रसाद शर्मा दस्तखत करूं, मान लो किसी प्रोपर्टी के लिए; तो क्या वह लेजिस्लेटिव असेम्बली की प्रोपर्टी हो जायेगी ?

श्री सभापति : This is hypothetical and it is disallowed. You will kindly take your seat.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, S r. I point out..

श्री पी० के० चौधरी : No point of order on a ruling, Sir.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : You gave your rul ng day before yesterday or yesterday that if anything remains..

(व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I will request the Chair to check these shock absorbers.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Sir, there is an ambiguity and I am asking through you that if I write something in a document...

श्री सभापति : The question that you have posed is hypothetical.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : The property belongs to that...

श्री सभापति : You are free to give notice of a question and seek information there. Other ways are open to you.

एक माननीय सदस्य : He has concluded. The Hon'ble minister has concluded his reply it appears, and another Hon'ble Minister has risen up to give reply.

श्री सभापति ; Hon'ble Minister.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रथम तो आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि आज इस मांग के सिलसिले में माननीय सदस्यगण से जिस प्रकार से इस विभाग की अलग अलग प्रवृत्तियां जो चल रही हैं, जो जो उद्योग इस विभाग द्वारा सहायता देने के फलस्वरूप आगे आये हैं या जिनमें कमियें रही हैं उनके बारे में प्रकाश डाला, मैं उनका बहुत आभारी हूं । मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इन सब बातों के लिये मुझे कम से कम एक घंटे का समय मिलना चाहिये ताकि मैं सही प्रकार से, सही तरीके से जो कुछ बातें हैं उनको मैं सदन के सामने रख सकूं । ....

श्री सभापति : Is it the sense of the House that time should be extended ?

श्री पी. के. चौधरी(फुलेरा): He can continue tomorrow, Sir.

श्री सभापति : No. I think we have to complete it today. The list of business says that it should be completed today.

Page No.111

श्री पी० के० चौधरी : It is not necessary that the demand should be passed today. There is no such decision. This demand can be passed even tomorrow.

श्री सभापति : The Business Advisory Committee has taken a decision that at least one demand should be discussed and passed on a particular day. This demand was put in the list of business for today.

श्री पी० के० चौधरी : I would like to know how the Business Advisory Committee has fixed one demand for today.

श्री सभापति : It has fixed this demand for today.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, आपके रूलिंग के बाद कोई नहीं बोल सकता।

श्री सभापति : There is a recorded decision of the Business Advisory Committee to this effect, adopted by the House.

श्री पी० के० चौधरी : I cannot understand one thing. Before the P. A. C. has decided the order of the demands, how can the Business Advisory Committee fix this demand for today ?

श्री सभापति : The decision of the P. A. C. has only to be taken into consideration by the Leader of the House in determining the order in which the demands will be discussed in the House. As far as the time is concerned it is allotted by the Businsss Advisory Committee. The Business Advisory Committee has accordingly taken a decision which has been heard and confirmed by the House and the matter ends there.

श्री श्रीमानसिंह : In that case no time should be extended and it should be completed at 5.

श्री सभापति : Well, sense of the House has to be taken on it.

श्री श्रीमानसिंह : This is the only thing that have got now.

श्री सभापति : So we decide to sit only for one hour beyond the prescribed time.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, Upto 5.

श्री भैरोंसिंह : It is left to the choice of the Hon'ble Minister, Sir.

श्री सभापति : I think when the Hon'ble members have taken the trouble of moving cut motions they should also be equally anxious to listen to the reply of the Government. The Hon'ble Minister should be enabled to give a full and thorough reply.

एक माननीय सदस्य : The Hon'ble Minister should conclude his reply by 5. 30 at the latest.

श्री पी. के. चौधरी : Sense of the House should be taken, Sir.

श्री सभापति : It has been taken and it has been announced.

श्री पी. के. चौधरी : It has not been taken.

श्री सभापति : Yes, Hon'ble Minister.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री) : सभापति महोदय, मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहूँगा कि उद्योग विभाग की अलग अलग प्रवृत्तियों के बारे में जिन माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी सुझाव दिये और जिन बातों, कठिनाइयों तथा उद्योग विभाग की कमियों के बारे में प्रकाश डाला उसके लिये मैं बहुत आभारी हूँ। मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा कि हमको हमारे इस देश की आजादी के बाद में उद्योग और खासकर राजस्थान में उद्योग की प्रवृत्तियों का क्या इतिहास रहा ? इस वक्त यह भी कहना जरूरी होगा कि आज हम हमारे देश के निर्माण में लगे हैं और हर तरह के सेक्टर चाहे वह एग्रीकल्चर हो, चाहे वह सोशियल एजुकेशन हो, चाहे वह इन्डस्ट्रीज़ हो, उनमें जब हम तरक्की करना चाहते हैं जब हम एक ट्रान्ज़ीशनल पीरियड में से गुजर रहे हैं, तो जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे के दांत निकलने लगते हैं तब जिस प्रकार की तकलीफों को बर्दाश्त करना पड़ता है, उसी तरह की चीज़ इसमें भी है। यह सही है कि जब तक हम इस आजाद देश की वे बातें जो देश बहुत अर्से से आजाद हो चुके है वे जिस दौर से गुजर चुके है हम उसी दौर से आज गुजर रहे हैं, इस जमाने में गुजर रहे है, जिसमें से वे गुजर चुके है। इस सब वातावरण को देखते हुए यह देखना है कि आखिर राजस्थान की स्थिति क्या है।

राजस्थान में उद्योग का जहां तक सवाल आया, आपने देखा होगा कि सन् १९५७ के बाद ही ज्यादातर इसके ऊपर ध्यान दिया। हमारा राजस्थान बना और उसके बनने के बाद जो कठिनाइयां हमारे सामने आईं और जो काम करने पड़े इन्टीग्रेशन आदि के, उसमें उलझे रहे और आखिर में उसके बाद जब देश में इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन का एक वातावरण बना तो राजस्थान भी उससे पिछड़ा हुआ नहीं रहा और सन् ५७ के बाद हम बराबर इस बात में लगे रहे कि हम किस प्रकार से अपने इकोनोमिक सेक्टर और इन्डस्ट्रियल सेक्टर में भी आगे बढ़ सकते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि समय समय पर सवाल आया, इस सदन को मालूम है, इन तीन-चार सालों में जो स्टेप्स लिये गये, जो कंडीशन इन्डस्ट्रियलाइजेशन की क्रिएट की उससे एक प्रकार का बेस बना, वातावरण बना और उसकी वजह से आज भी हमारे राजस्थान के रहने वाले बहुत से भाई हैं जिन्होंने राजस्थान के बाहर जाकर काफी इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन किया है, आज उनका ध्यान राजस्थान की ओर गया....

श्री श्रीभानसिंह : कौनसी पार्टी आई है, जिसका ध्यान इस ओर गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। इस प्रकार से जो भी आज हम चाहते हैं कि किस प्रकार से इस राजस्थान में उद्योग पनपे. हमारे राजस्थान में रहने वाले भाई, बाहर रहने वाले भाई यहां आकर हमारी जो इन्डस्ट्रियल पोटेन्शियलिटी है और मिनरल पोटेन्शियलिटी हैं उनको डेवलप करें और राजस्थान का औद्योगिकरण कर सकें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि इन्डस्ट्रियल पॉलिसी के अनुसार यह निश्चित है कि कुछ ऐसी इन्डस्ट्रीज़ हैं जिनको हम पब्लिक सेक्टर में करना चाहते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में मिक्स्ड कर सकते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर में करना चाहते हैं। कुछ ऐसी इन्डस्ट्रीज़ है जो लघु इन्डस्ट्रीज़ कहलाती हैं, छोटी छोटी हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में ही डेवलप कर सकते हैं और जो लघु उद्योग हैं उनको पनपाने की जिम्मेदारी स्टेट पर रखी है और भारत सरकार से भी भिन्न भिन्न प्रकार से उनको सहायता देने का प्रावधान है क्योंकि हमको वहां से सहायता मिलती रही है। मैं इस समय यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितने रुपये दिये गये और हमने क्या खर्चा किया और उससे हमारे फिज़ीकल टार्गेट्स थे उनको कहां तक एचीव कर सके हैं। और अब जब कि हम तृतीय पंच वर्षीय योजना में जाने लगे हैं तो क्या खर्चा करना चाहते हैं और फिज़ीकल टार्गेट्स क्या हैं ?

यह निश्चित बात है कि आज माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से अपनी भावना प्रकट की, सरकार ने उद्योग क्यों नहीं चलाये, सरकार चमड़ा, हड्डी और साबुन का उद्योग चला सकती थी, और दूसरे छोटे छोटे उद्योग चलाने थे आदि। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जहां तक सरकार द्वारा सहायता देने का सवाल है वह सहायता व फेसिलिटीज़ देने को बराबर तैयार है, लेकिन वहां के रहने वाले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति उद्योग को चलावें और उनको हम सहायता नहीं दें या सरकार की ओर से सहायता नहीं मिले, तो कहा जा सकता है कि हमने उनके लिये कुछ नहीं किया।

मैं यह निवेदन करूंगा कि सेकिंड फाइव इयर प्लान में हमारा जो प्लान आउट-ले था वह ३६६.७० लाख था और उसका जो एक्सपेन्डीचर इस साल के आखिर तक हम एक्सपेक्ट करते हैं वह ३१३.६७ लाख के करीब होगा। इस प्रकार से यह जो हमारा खर्चा कुल मिला कर है वह करीब ८५ पर्सेन्ट ऑफ दी टोटल आउट-ले होगा। इसलिए मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो प्रोग्राम इस खर्च के लिए निश्चित किया था सैकंड फाइव इयर प्लान में, वह है हैंड लूम के अन्दर प्लान आउट-ले था १५, हम इस साल के अन्दर ६२.१६ खर्च करेंगे। वूल डेवलपमेंट के लिए ११.०० था, अब १६.०० खर्च करेंगे। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़, जिसमें सारे आ गये, लोन देना, प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग सेन्टर, उसमें १८६ लाख था, उसमें १६६.७६ खर्च किया है। हैंडी क्राफ्ट के अन्दर ३८.४५ लाख था, उसमें से २१.४६ खर्च कर सके, खादी एण्ड विलेज इन्डस्ट्रीज़ के लिए ११ लाख था उसमें हमने १३.०७ खर्च किया है।

Page No.114

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

सेरीकल्चर का .६६ लाख था, जिसमें खर्च कर सकेंगे १६ लाख। इन्डस्ट्रियल एस्टेट के लिए ६१ लाख का प्रावधान था, उसमें हम ३८.१६ लाख खर्च कर सकेंगे । इसी तरह से वेट्स एण्ड मेजर्स के अन्दर ३.०२ का प्रावधान था, उसमें हम १.५२ खर्च कर सके हैं। इस प्रकार से इन जगहों के अन्दर, जिन स्कीम्स के अन्दर शार्ट फॉल हुआ है, किसी में एक्सेस किया है, उसमें एक कारण है, जो शोर्ट फॉल होने का कारण था, जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैक्शन्ड स्कीम्स थीं, वे चल नहीं सकीं। उसके कारण ये। एक तो सैंक्शन देरी में आई, कुछ स्कीम्स उन्होंने बीच में ड्रॉप कर दीं कि अभी ये स्कीम्स नहीं चलायेंगे। उस प्रकार शोर्ट फॉल हुआ है, इन्डस्ट्रियल एस्टेट में शोर्ट फॉल हुआ है। मैं रीज़न निवेदन करना चाहूँगा कि शुरू दो साल के अन्दर में यह रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक सैंक्शन नहीं कर देती तब तक काम नहीं कर सकते । तो उस प्रोसीजर को तब्दील करने में करीब दो साल लग गये। सारे हिन्दुस्तान में ऐसा हुआ है, उसके बाद प्रोसीजर को तब्दील किया, फिर हमारे यहां के सारे मामलों को देखने पर मालूम होगा कि जयपुर इन्डस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना की; भीलवाड़ा, मौकूपुरा; इस तरह १४ इन्डस्ट्रियल एस्टेट जो अन्डर कन्स्ट्रक्शन हैं और कुछ आगे चालू हैं, उनमें खर्चा हुआ । मैं उम्मीद करता हूँ कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो प्रावधान किया गया है उससे ज्यादा काम करेंगे, उससे कम खर्च करने की आशा नहीं करते ।

इसी तरह से इस साल का एक्सपेन्डीचर १००.५८ लाख है, उसमें से ६२.६० लाख खर्च कर सकेंगे । यह भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, हैंड लूम के बारे में अभी पाली से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर कोई सहकारी समिति चलती है, उसको लोन नहीं मिला इत्यादि हो। सकता है कि उनकी सूचना सही हो, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि हैंड लूम सेक्टर के अन्दर हमने अच्छी प्रगति की है। हैंड लूम सेक्टर के जो फिज़िकल टार्गेट्स हैं, उनको अचीव किया है। हैंड लूम का जहां तक सवाल है, मैं निवेदन करूंगा कि उसकी ठीक प्रगति हुई है, उनको अच्छे लूम व एक्सेसरीज़ दी गई। डाई हाउसेज़ इत्यादि कोऑपरेटिव सेक्टर के अन्दर और इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव भी स्थापित हुई। इस प्रकार यह हुआ, इसमें ४६ लाख का प्रोवीज़न है कोऑपरेटिव का, ११ डाई हाउसेज़, एक मोबाइल वान, फाइव हाउसिंग कोलोनीज़ फोर ३००० वीवर्स, ३ लूम एसेसरीज़ दीं, १३० पॉवर लूम स्थापित कर दिये, २०० की सेंक्शन दे दी जिसमें रुपया सात–आठ लाख खर्च होगा। कुल ३३० पॉवर लूम्स दीं। इसके साथ इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग सेन्टर चला रहे हैं, और जो इन्डस्ट्रीज़ सेक्टर में हैं वे ६३७३ हैं। वे बढ़ कर १९६०-६१ में २६,६१५ हुए। इस तरह हैंडलूम क्लोथ में काफी बढ़ोतरी हुई, उसकी वेल्यू के अन्दर हुई, जब पैदावार में बढ़ोतरी हुई तो वेल्यू में होनी चाहिए। ये सारी बातें हैंडलूम सेक्टर में हुई।

इसी तरह से वूल डेवलपमेंट एण्ड कॉमन फेसीलिटीज़ फोर वूल कार्डिंग एण्ड फिनिशिंग

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

बीकानेर में चल रहा है, उसके अलावा ओल्ड कोटेज इन्डस्ट्रीज़ इन्स्टीट्यूट बीकानेर को रीऑर्गेनाइज़ किया और मोडल ट्रेनिंग सेन्टर फोर वुलन प्रोडक्ट किया। एक कारपेन्ट्री सेन्टर जयपुर में है, एक टोंक में नमदा वगैरह का चल रहा है। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि करीब ८२ लाख का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया और २१५० यूनिट्स को अलग अलग लोन ८२ लाख का दिया। इसी तरह छोटी इन्डस्ट्रीज़ को सब्सिडी देने की बात है। वह सब्सिडी दी गई और जो हमारे प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग सेन्टर्स चलते हैं, वे ४२ चलते हैं। प्रोडक्शन-कम-ट्रेनिंग सेन्टर के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि उन्हें रीऑर्गेनाईज़ कर रहे हैं, इस तरह से हमारी बहुत सारी स्कीम्स थीं, लेदर की हैं, और दूसरी क्वालिटी मार्किंग की हैं। इस प्रकार से हैंडीक्राफ्ट के अन्दर हमने जैसा कहा कि उसमें प्रगति की है, ओल्ड आर्टस स्कूल में चल रहे कॉटेज इन्डस्ट्रीज़, जयपुर, को रीऑर्गेनाइज़ किया, आर्टिस्टिक क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कूल के अन्दर, जिसमें ५० आदमी ट्रेनिंग पा रहे हैं, उसको रीऑर्गेनाइज़ करके सेट अप किया।

इसी तरह से अलग अलग जगह पर एम्पोरियम, सब-एम्पोरियम खोले, दूसरे मैटल, आइवरी, प्रिन्टिंग, ग्रासवेअर के सेण्टर्स चल रहे हैं और इनमें प्रगति हुई।

इसी तरह से इन्डस्ट्रियल एस्टेट में मैं निवेदन करूंगा कि ६ इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स जयपुर, मौकूपुरा, भीलवाड़ा, कोटा, भरतपुर, गंगानगर, जोधपुर, उदयपुर और सुमेरपुर हैं। इनके अन्दर बहुत सारों के अन्दर तो कन्स्ट्रक्शन कम्प्लीट हो गये, बहुत सारों के अन्दर कन्स्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत सारों के अन्दर सैकंड फेज़ आई है। तो इस तरह से दूसरी जो नई पांच बस्तियां बनाई है; अलवर, गंगापुर, धौलपुर, बीकानेर, पाली; इनके अन्दर इस साल जो कुछ प्रावधान था उसके अनुसार जमीन को लेना तथा प्लान वगैरह बनाना ये सारी की सारी प्रिलिमिनरी कार्यवाही करनी थी वह की। धौलपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा धौलपुर एस्टेट के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। धौलपुर एस्टेट में जमीन वगैरह का थोड़ा झगड़ा था, वह मैं समझता हूँ जल्दी से तय होकर कम्पेन्सेशन की समस्या को तय करके ले लिया जायगा और काम शुरू कर देंगे....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इस वर्ष कर देंगे ?

एक माननीय सदस्य : कल ही।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस वर्ष कम्पेन्सेशन की कार्यवाही कम्प्लीट हो जायगी।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : कल शुरू कर दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मतदाताओं को सूचित कर दें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इलेक्शन से पहले हो जायगा।

डॉ० बहादुरसिंह : Thank you.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस तरह से रानी और फालना के अन्दर दो अस्टिटेड इन्डस्ट्रियल एस्टेट के लिए किया है। मैं, सभापति महोदय, आपके जरिये निवेदन करना चाहूँगा कि रानी और फालना के दो असिस्टेड इन्डस्ट्रियल एस्टेट इस सारे भारतवर्ष में प्रथम बार स्थापित होंगे, जिनके बारे में स्टेप्स लिये। हमने रूल्स बना दिये हैं और लोन की गारन्टी देकर रुपया उन्हें दिलावेंगे। सरदारशहर में भी ऐसा किया जा रहा है। वैसे इन्डस्ट्रियल एस्टेट के लोन को गारन्टी देकर और प्रोग्राम के अनुसार, प्लान के अनुसार, उनको सारी सैंक्शन देकर हम बनाना चाहते हैं। इस तरह से ५८ शैड्स जयपुर, ५५ शैड्स मौकूपुरा, १२ शैड्स भीलवाड़ा, इस तरह ८५ कम्प्लीट हैं और अलॉट कर दिये हैं और ११२ शैड्स इस वक्त बन रहे हैं और करीब करीब कम्प्लीशन की स्टेज पर हैं। इस प्रकार इन्डस्ट्रियल एस्टेट के अन्दर प्रगति हुई।

मैंने यह निवेदन किया कि १९६१ के आखिर तक और इस दृष्टि में कि हम हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना के काम, जो कि ३१ मार्च, १९६१ तक खत्म होने जा रहा है, इसमें और कितना रुपया खर्च किया....

श्री श्रीभानसिंह : ३१ मार्च ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, ३१ मार्च, १९६१ को जो खत्म होने जा रहा है उसमें हमने किया पांच साल में, वह मैं ने निवेदन किया अब अगले साल जो हमारा फाइव इयर प्लान शुरू हो रहा है १ अप्रेल, ६१ से उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा। कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात जाहिर की है कि गये साल का ६६ लाख का बजट था, इस साल ५४ लाख का कर दिया है, कटौती कर दी तो उद्योग विभाग तो बजट कम कर रहा है, फिर क्या प्रगति हो रही है, यह समझ में नहीं आता। मैं निवेदन करूंगा कि पहले द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ३.६६ करोड़ था, आज हमारा बजट ५.३० करोड़ का है। इस बजट में हमको जो थर्ड फाइव ईयर प्लान के फर्स्ट ईयर में खर्च करना है, ८५ लेक्स हैं, उसका प्रोग्राम भी दिया है कि किस तरह खर्च करना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा ज्यादा खर्चा इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने में और लोन्स देने में ज्यादा रखा है। जो कि पहले प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग सैंटर्स थे उनको हमने देखा कि इससे इतना फायदा नहीं हो सकता, जितना कि हम चाहते हैं कि रूरल इन्डस्ट्रियलाइजेशन में क्राफ्ट्समैन ट्रेन्ड होकर जायें, चाहे वे कारपेंटर हों या ब्लेकस्मिथ हों। हमारा यह भी निश्चित मत है कि रूरल एरियाज़ में छोटी इन्डस्ट्री को ज्यादा पनपाया जाय। मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि हाल ही में जो ऑल इण्डिया स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ के बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें तय हुआ कि प्लान का ५० पर्सेन्ट रूरल इन्डस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम में देना चाहिये ताकि अधिकाधिक रूरल क्राफ्ट्समैन तैयार हों।

हो सकता है कि हम प्रथम वर्ष में ५० पर्सेन्ट खर्च नहीं कर सकें, पर कोशिश करेंगे कि रूरल एरियाज़ में इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स या वर्क शेड्स बन सकें, तो वह ठीक होगा। मैं समझता हूँ कि इसी के अनुसार हम चलना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा अभी कहा गया कि हमारा बजट कम हो गया,

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

हमने बहुत से आदमियों को कम करने का तय किया है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को और लेबर स्टाफ है उसको कम करने का तय किया है और टोप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया है। इस तरह का रीऑर्गेनाइजेशन किया है। रीऑर्गेनाइजेशन पर मैं फिर कहूँगा। अभी यह निवेदन कर दूं कि डिमान्ड को पूरी तरह मुलाहिजा करेंगे तो नोन प्लान का २०,४३० है और प्लान स्कीम्स का २३,८७ है। इसी तरह से ५८.३ है। इसके अन्दर जो कुछ कमी की है वह है ६.५। यह कहा जाता है कि कमी की गई है, कुछ स्टाफ को हटा दिया, स्कीम्स हटा दिये, मैं इस बारे में निवेदन करूंगा कि यह कट किस किस हैड में किया है।

पहले मैं यह कह दूं। थोड़ा सा इस प्लान बजट के ब्रेक अप की तरफ तवज्जोह दिलाना चाहूँगा कि इन्डस्ट्रीज़ एन्ड सप्लाइज़ में जो हमारा प्लॉन बजट है, डिफरेन्ट हैड्स में है; वह इस प्रकार है :

Under different heads :-

Within Plan ceilings : 18. 17 lakhs.

Outside Plan ceilings : 4. 17 lakhs.

Under head 56

Within Plan ceilings : 0. 16 lakhs.

Outside Plan ceilings : 2. 00 lakhs.

Under head Capital'

Within Plan ceilings : 39. 00 lakhs.

Outside Plan ceilings : 2. 00 lakhs.

Under head '72-Capital'

Within Plan ceilings : 7. 34 lakhs.

Under head 'P-Loans'

Within Plan ceilings . 20. 33 lakhs

Outside Plan ceilings : 2. 67 lakhs.

यह ८५ लाख रुपया जो हम अगले साल खर्च करना चाहते हैं, उसका ब्रेक अप इस प्रकार है :

Handlooms, including wool.	6. 00 lakhs.
Small scale Industries	34. 12 lakhs.
Industrial Estates.	32. 40 lakhs.
Khadi & Village Industries.	0. 50 lakhs.
Sericulture.	0. 10 lakhs.
Handicrafts.	2. 54 lakhs.
Sodium Sulphate Pilot Project.	5. 34 lakhs

Besides these, there are provisions for large and medium industries development, industrial areas, weights and meausres and Power Looms.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन कर दूं कि यह तो थर्ड फाइव इयर प्लान को जिस समय हम डिस्कस करेंगे उस समय बता दें। अभी तो सिर्फ हमें प्रोडक्शन के फीगर्स बता दें कि कितनी इन्डस्ट्रीज़ हैं और कितनी बोगस इन्डस्ट्रीज़ के खिलाफ एक्शन लिया है। ये दो चीजें हमको बता दें। बाकी खर्चा प्लान का है यह तो हम थर्ड फाइव इयर प्लान आयेगा उस समय डिस्कस कर लेंगे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वैसे तो पूरे कट मोशन्स आये हैं उनमें कहा है कि

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

कोटेज इन्डस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के कार्य में कुछ नहीं किया। यह भी कहा गया कि जो कुछ किया जाता है बड़े बड़े शहरों में किया जाता है, रूरल एरियाज़ में कुछ नहीं किया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारा आगे का रूरल प्रोग्राम है उसमें हम क्या करना चाहते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : अदर कन्ट्रोल्ड कोमोडिटीज़ में इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन है....

श्री सभापति : Reply has to be given on all the points raised.

श्री पी० के० चौधरी : And has to be concluded at 5.30

श्री सभापति : Of course. So I will request the Hon'ble Minister to be brief. Brevity is the soul of wit.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो इस बजट में कट किया गया है, यानी ६.५० लाख इसमें से अगले वर्ष की स्कीम चलाने के लिये कुछ लोगों को तो एब्जोर्ब कर लेंगे यानी करीब करीब ४.०२ लाख प्लान बजट में ट्रान्सफर कर दिया जायगा।

श्री पी० के० चौधरी : रीऑर्गेनाइज़ेशन पर प्रकाश डाल दीजिये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रीऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने जाहिर किया कि रीऑर्गेनाइज़ेशन करना चाहते हैं तो जोइन्ट डाइरेक्टर्स को बढ़ा दिया, डिप्टी डाइरेक्टर्स को बढ़ा दिया और दूसरा हैड क्वार्टर्स में स्टाफ है उसको बढ़ा दिया, नीचे का स्टाफ कम कर दिया, इस तरह की बातें सामने आई हैं। तो मैं निवेदन करूं कि रीऑर्गेनाइज़ेशन हमने किस दृष्टि से किया, हमने रीऑर्गेनाइज़ेशन इस दृष्टि से किया कि प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग सेंटर्स प्रोग्राम हम चला रहे थे, उनको अबोलिश करना चाहते हैं, उनकी जगह कलर ट्रेनिंग सेंटर्स रखना चाहते हैं, वह हम ब्लॉक एरिया में खोलेंगे। और यह सर्वे करना चाहते हैं, जिससे यह पता चले कि उन एरियाज़ में कौन कौन से क्राफ्ट्स हैं, किस किस प्रकार के आर्टीज़न्स हैं, कौन कौन से ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, जिनकी ट्रेनिंग दी जा सके। इस वक्त प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनमें जो मशीनें हैं, उनको वहां ले जाकर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हों, चाहे इधर हों उन्हें ट्रेनिंग देना चाहते हैं। जो स्टाफ प्रोडक्शन स्कीम्स में लगा हुआ है उसको वहां ले जायेंगे।

मैं आज आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों ने जैसा कहा कि डाइरेक्टर तीन चार साल तक बराबर रहना चाहिये और उसका ट्रान्सफर नहीं होना चाहिये। मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि रहना चाहिये। इसके अलावा डिप्टी डाइरेक्टर और जोइन्ट डाइरेक्टर ज्यादातर तो ट्रेन्ड ही हैं। हो सकता है कि एक या दो आर. ए. एस. हों जो अनट्रेन्ड हों, जैसा कि बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं किसी सरकारी ऑफिसर को डिफेन्ड करने के लिये नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं यह कहूँगा कि मुझे इस विभाग का ज्यादा तजुर्बा है। मैं जानता हूँ कि कौन ऑफिसर कैसा है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

कि हैंड लूम के डिप्टी डाइरेक्टर हैं मि० भुटानी, जब से उन्होंने हैन्डलूम और इन्डस्ट्रियल एस्टेट का काम हाथ में लिया है तब से उसमें काफी प्रगति हुई है और काफी खर्चा भी कर पाए हैं।

श्री श्रीभानसिंह : आप कहते हैं कि काफी प्रगति हुई है और काफी खर्चा भी हुआ है, यह कैसे ?

श्री पी. के. चौधरी : मैं यह पूछना चाहूँगा कि वे ८०० से १२०० के ग्रेड में एक साल में कैसे चले जाते हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं यह निवेदन करूंगा....

(घन्टी)

श्री सभापति : No interruptions please.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हमने आज ६६ लाख रुपया खर्च किया है....

श्री पी. के. चौधरी : आपने कहा कि ३०० से ८०० और १२०० के ग्रेड में एक साल में कैसे चले गये ?

श्री भैरोंसिंह : यह कोई ज्यादती नहीं है। तहसीलदारों से कलेक्टर में पहुँच जाते हैं।

श्री पी. के. चौधरी : That is what we are not able to understand. I would like to know the justification of having him.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Justification is the work of the man, justification is there when we see that the officer is a very honest man and is doing very well. That is the correct justification. Moreover he is drawing his pay as an R. A. S. Officer plus allowance only.

श्री पी. के. चौधरी : Honesty is not ability.

श्री सभापति : The Hon'ble minister is in possession of the floor of the House and he should be allowed to continue.

Yes, have you concluded ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That is all I can say.

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सिलसिले में जो भी हमारा वर्तमान सेट अप था....

श्री श्रीभानसिंह : Is this the same man who was working as Deputy Director, Handlooms ?

श्री सभापति : This is not the Question Hour please. The members have the option of tabling a question after due notice. The Hon'ble Minister is making a reply and he is entitled to be heard in silence.

श्री श्रीभानसिंह : But these points have been brought by me in the cut motion.

श्री सभापति : Then have patience. He has not yet replied.

श्री श्रीमानसिंह : You said that he has concluded his reply, therefore, I rose.

श्री सभापति : No he is still replying.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो रीऑर्गेनाइज़ेशन करना चाहते हैं उसमें एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर अलग अलग स्थानों पर हैं उनको हम समाप्त करके रीजनल डाइरेक्टर करना चाहते हैं। इसी तरह से डो. आई. ओज़. को कम करना चाहते हैं। १४ या ज्यादा से ज्यादा १८ डी. आई. ओज़. की पोस्ट ही भरना चाहते हैं। इसमें यह बात नहीं है कि हमने फोर्थ क्लास को हटा दिया हो। हम इस सेट अप को ठीक समझते हैं कि इसमें हम ठीक तरह से काम कर सकेंगे। इसलिये यह कटौती रखी है। मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।

जो सेन्ट्रलाइज़ेशन की बात कही जाती है उसके लिये मैं यह कहना चाहूंगा कि हम डीसेन्ट्रलाइज़ेशन करना चाहते हैं। हमको डीसेन्ट्रलाइज़ेशन करना होगा और उनको अधिकार ज्यादा देने होंगे। जो एक्टीविटीज हैं districts में उनमें district level पर भी decentralisation करना चाहते हैं। सेट अप में इस प्रकार काम करना चाहते हैं ताकि इकोनॉमी करते हुए एफिशियेन्सी में कोई फर्क नहीं हो।

इसमें हमारे डिप्टी डाइरेक्टर को ज्यादा अधिकार देने होंगे। आज हम लोन सेंक्शन करते हैं, इसके लिये कलेक्टर और डाइरेक्टर को ज्यादा अधिकार देंगे। इस तरह से डीसेन्ट्रलाइजेशन करना चाहते हैं जिससे enterpreneurs को सहूलियतें मिल सकें।

इस तरह से हम यह भी चाहते हैं कि एक Small-scale Industries Corporation बनाया जावे। यह माल की खरीदी करेगा और इसके जरिये लोगों को आसानी से मिल सकेगा और कच्चे माल का mis-utilisation रोका जा सकेगा। इसी तरह से पॉवर लूम आदि को ज्यादा बढ़ाने का हमारा प्रोग्राम है।

एक माननीय सदस्य ने यह प्रकट किया कि जो इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स बनी हुई हैं वे ठीक प्रकार से नहीं चल रही हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह उनका ख्याल सही हो सकता है किसी हद तक इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स बनने में समय लगता है। मैं उनकी जानकारी के लिये यह निवेदन करूंगा कि जयपुर के बारे में हमारे पास शिकायत आई। हमने इसके लिये कमेटी मुकर्रर कर दी कि वह इसको जांच करे कि उसमें रॉ मेटीरियल जो उसको दिया जाता है ठीक तरह से इस्तेमाल करते हैं या नहीं। अभी उस कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं है और मैं निवेदन करूंगा कि उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में हम सही स्थिति में आ सकेंगे कि ठीक प्रकार से वे प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं।

उसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी माननीय सदस्य बतावेंगे, मैं उसकी इन्क्वायरी करूंगा और गलती साबित होगी तो कायदे के अनुसार हम कार्यवाही करेंगे, इसमें दो राय नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

में हमने इफेक्टिव एक्शन लिया है । हमने जो स्टेप्स लिए हैं वे इस प्रकार हैं ।

हमने यह किया है कि जितने डी. आई. ओ. हैं वे कम से कम साल में दो दफे उन लोगों की जिन्हें controlled raw material मिलता है इन्सपेक्शन करें और रिपोर्ट दें और रिपोर्ट डाइरेक्टोरेट को भी भेजे । उसके बाद में एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर खुद साल भर में कम से कम एक दफे जाकर मुआयना करें और डी. आई. ओ. की रिपोर्ट आये उसके बारे में अपनी राय भेजे । इसी तरह डाइरेक्टोरेट उच्च अधिकारियों की एक इन्सपेक्शन कमेटी मुकर्रर कर दी है कि किसी भी किस्म की कोई भी शिकायत आवे, चाहे वह डी. आई. ओ. की रिपोर्ट के आधार पर हो या अन्य तरह से हो वे खुद जाकर उसकी जांच करें । जयपुर में डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ ने एक एक इन्डस्ट्री का इन्सपेक्शन किया है । इसलिये हर प्रकार से यह प्रयत्न किया जाता है कि mis-utilisation नहीं हो दरअसल में जिन जिन छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज़ को लोन दिया जाता है या रॉ मेटीरियल दिया जाता है, उसकी चीजें बनें और बाजार में आकर बिकें । हो सकता है कि कुछ युनिट इसको मिस युटिलाइज़ करते हों । अगर कोई युनिट ऐसा करते हों तो आप उसकी मुझे जानकारी दें, मैं उनकी इन्क्वायरी कराऊंगा । अगर आपके जानकारी कराने पर मैं उसकी इन्क्वायरी नहीं करता हूँ या उसके बाद में अगर कोई कार्यवाही नहीं करूं तो मैं दोषी हो सकता हूँ ।

मैं इतना ही निवेदन कराना चाहूँगा कि यह सब ठीक है । लेकिन हम कुछ ऐसी स्टेज में गुजर रहे हैं जब कि हमको एक ओर लघु उद्योग को प्रोत्साहन भी देना है और दूसरी ओर यह भी देखना है कि वह ठीक तौर से स्थापित हो । रॉ मेटीरियल की दिक्कत है । आइरन और स्टील को चार केटेगरीज़ हैं, जिसकी दिक्कत है । और किसी में दिक्कत नहीं है ।

इसके अलावा और माल कन्ट्रोल और बाजार में एक भाव मिलता है उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है । बी. पी. और जी. पी. शीट और वायर के बारे में दिक्कत है । समय समय पर गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को लिखा गया है । एस. टी. सी. द्वारा सारे हिन्दुस्तान भर के लिए करीब करीब ४० हजार टन इन केटेगरीज़ में से इम्पोर्ट हो रहा है और उन्होंने कहा है और इन्डीकेट किया है कि करीबन २००० टन राजस्थान को देंगे और उसकी राजस्थान फिज़िकल डिलिवरी लेकर रॉ मेटीरियल डिपो के जरिये या दूसरी एजेन्सीज़ कायम करके फिज़िकली डिलीवरी देकर बंटवाना चाहते हैं । जहां तक हमारी कोशिश है हम चाहते हैं कि जो रॉ मेटीरियल मिलता है, चाहे बाजार से लें, चाहे कन्ट्रोल से लें, कोटा सर्टिफिकेट से लें या एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट से लें उस माल का ठीक युटिलाइजेशन होना चाहिये । और कोई नहीं करता है तो मैं कहूँगा कि यह राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति है । हर एक आदमी चाहेगा कि जिन चीजों की कमी इस देश में है उनका निर्माण करके ज्यादा से ज्यादा चीजें यहां पैदा कर सकें । इन स्टेप्स के बाद भी माननीय सदस्य कोई इफेक्टिव स्टेप्स के लिए सजेशन्स देंगे तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ । मैं हर प्रकार से, हर तरह से इस कोशिश में हूँ कि रॉ मेटीरियल के

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

mis-utilisation के केसेज़ हैं वे हमेशा के लिए बन्द हों। जो कोई आदमी हमारे पास आता है, या तो वह ईमानदार है या यह कह कर चलें कि बेईमान है। कोई नया आदमी आता है तो यही विश्वास लेकर चलते हैं कि वह आदमी ईमानदार है और यदि बेईमान है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाय।

एक माननीय सदस्य : आज तक एक्शन लिया है क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : (अपना भाषण जारी रखते हुए) श्री माधोपुर से आये माननीय सदस्य ने बताया कि उनकी इन्फोर्मेशन है कि रॉ मेटीरियल का मिस–यूज़ किया है। वे मुझको दें····

श्री भैरोंसिंह : दी हुई है। आपका पत्र आया है और एक्शन नहीं लिया है।

श्री रिखबचंद धारीवाल : बराबर जांच होगी।

श्री भैरोंसिंह : डेढ़ वर्ष हो गया।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो उनके बारे में कहा है उनकी जांच करके मैं फिर अर्ज कर दूंगा। और भी इन्स्टान्सेज हों तो बता सकते हैं; हो सकता है कि उस जांच में कोई बात हुई हो। इन्फोर्मेशन देंगे तो जांच कराऊंगा। माननीय सदस्य ने कहा कि दूसरी चीजें, आइरन स्टील आदि नहीं मिलती हैं। स्केयरसिटी है आयरन केटेगरीज़ में। हो सकता है कि उस चीज़ को बनवाना चाहते हों जिनमें वे चीजें जरूरी हों। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनको आवश्यकता न हो। हम हर वक्त में यह कहते हैं कि ये चीजें शोर्ट सप्लाई में हैं और उनकी इन्डस्ट्रीज़ उन पर बेस न करें। आज भी डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ रॉ मेटीरियल का कोटा अलॉट करने से पहले उसको स्क्रीनिंग कमेटी में जांच के लिए भेज देते हैं। उसके बावजूद भी मिस युटिलाइजेशन के मामले होते हैं तो हम उसकी जांच करने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ, यही काफी होगा इस स्टेज पर और कुछ जानकारी मिलेगी उसके लिए स्टेप लिये जावेंगे।

इसी तरह से सीमेन्ट के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। कहा गया है कि सीमेन्ट नहीं मिलता। यह कोई कन्ट्रोल्ड आइटम नहीं है। राजस्थान सरकार का या भारत सरकार का इस पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। जयपुर उद्योग का प्रोडक्शन बढ़ा है सीमेन्ट का, इसमें कोई शक नहीं है। जयपुर उद्योग, लाखेरी फेक्ट्री दोनों राजस्थान में है। कहा यह गया है कि यह होते हुए भी सीमेन्ट नहीं मिलता है। मैं यह कहूँगा कि सीमेन्ट फेक्ट्री के सीमेन्ट के अलॉटमेंट की एक रीजनल कमेटी है वह सारे भारतवर्ष के लिए अलॉटमेंट करती है। जयपुर उद्योग अपना सीमेंट सिर्फ राजस्थान को ही देता हो-ऐसा नहीं है। राजस्थान को कुछ मात्रा में जो अलॉटमेंट मिलता है उसको हम अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रि-ब्यूट करते हैं। पी. डब्ल्यू डी., राजस्थान केनाल और दूसरे दूसरे वर्क्स हैं, इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट सिविल सप्लाइज़ के लिए जिले के कलेक्टरों को दे देता है। इस प्रकार से हम दे देते हैं। सवाल यह रह जाता है कि आया वे चीजें मिलती हैं या नहीं ? यह सही है कि छः महीने से सीमेन्ट की स्केयरसिटी आई है। पहले कोई नहीं थी। लेकिन कन्ट्री भर में

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

यह स्केयर्सिटी हुई है। इस तरह से रेलवे वेगन्स न मिलने और कन्ज़म्पशन अधिक होने से यह स्केयरसिटी हुई है। फिर जयपुर उद्योग का जो डिस्ट्रिब्युटिंग एजेन्ट है उनको बुलाकर बातचीत करके वेगन मूवमेन्ट के बारे में भी किया है और मैं समझता हूँ कि करीब करीब २५--३० वैगन्स बराबर फेक्टरी से देते रहेंगे और इस प्रकार से सप्लाई होती रहेगी। यह सही है कि दिक्कत जरूर है, इसमें दो राय नहीं हो सकती है। सीमेन्ट के डिस्ट्रिब्युशन के लिए कोई कन्ट्रोल नहीं किया है। सीमेन्ट के स्टॉकिस्ट्स हैं वे ही बेचते हैं। सारे देश में कोई इसका कन्ट्रोल नहीं है। जो जो फेक्ट्रीज़ हैं, डिस्ट्रिब्युशन के बारे में अलॉटमेंट अलग २ जगहों पर उन्होंने किये हैं, that is Statewise allotment and not consumer-wise allotment.

इसी तरह से कोल के बारे में भी कहा गया। यह सही है कि कुछ अर्से से सारे देश भर के अन्दर कोल की सप्लाई कम हुई है और उसका असर राजस्थान पर भी पड़ा है। मैं जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान में १००० टन्स पी० डब्लू० डी०, राजस्थान केनाल १६५.०, चम्बल ६२ टन्स और दूसरी डिमान्ड्स भी होती हैं। यह भी निवेदन करूंगा कि अब जो सिस्टम किया है वह रेक सिस्टम पर कर दिया है। कोल माइन्स से आवेगा। One rake of soft coal in every month......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : शारदा इन्डस्ट्रीज़ आदि की जरूरी बातें बताइये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ....and one rake of miscellaneous in every two months.

कोल की सप्लाई की अलबत्ता डिफिकल्टी हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि ज्यों ज्यों वैगन्स की सप्लाई होती जायगी त्यों त्यों कोल की सप्लाई हो जावेगी।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, बयाना से आये हुये माननीय सदस्य ने कुछ बातों के बारे में कहा। कुछ केसेज़ भी सदन के सामने रखे, जिसके लिये यह बतलाया गया कि इन लोगों को एसेन्शियल सर्टिफिकेट दिया गया। एसेन्शियल सर्टिफिकेट क्या होता है और इसका कितना महत्व है, वह मैं बतलाना चाहता हूँ........

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : दिया गया या नहीं।

श्री सभापति : Hon'ble Minister, you are exceeding the limit of your time. I would request you, if possible, to confine yourself to the points which are being stressed by the Hon'ble members.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जिनके लिए ज्यादा उत्सुक मालूम पड़ते हैं वे दो या तीन व्यक्तियों के बारे में ज्यादा जानने के इच्छुक हैं........

श्री श्रीभानसिंह : यह गलत कह रहे हैं। मैं इच्छुक नहीं, जो बातें मेरे नोटिस में आई थीं मैं आपके नोटिस में लाया; मेरी

(श्री श्रीभानसिंह)

किसी के साथ पर्सनल एनिमिटी नहीं है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (जारी) : इच्छा तो आपने प्रगट को है, यही मैं अर्ज करना चाहता हूँ। जो केसेज़ वे मेरे नोटिस में लाये हैं, किसी से दुश्मनी होने की वजह से लाये हों, यह बात मैं नहीं कहता; लेकिन जो बातें उन्होंने बताई उनके बारे में फेक्ट्स निवेदन कर देना चाहता हूँ। एसेन्शियल सर्टिफिकेट डाइरेक्टर किसी प्रकार की मशीनरी इम्पोर्ट करने के लिये या रॉ-मेटीरियल के इम्पोर्ट करने के लिए देता है। सर्टिफिकेट इस बात का होता है कि एक इन्डस्ट्री लगाने के लिये और उस इन्डस्ट्री के लिये इतना रॉ मेटीरियल चाहिये। उस तरह का सर्टिफिकेट डेवलपमेंट कमिश्नर और कन्ट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट्स के पास जाता है। डेवलपमेंट कमिश्नर उसको देखता है और वह यदि मुनासिब नहीं समझता तो वह वहीं पर कट कर देता है, फोरिन एक्सचेन्ज नहीं होता है तो भी कट हो जाता है और एसेन्शियल सर्टिफिकेट उन्हीं को दिया जाता है जिन्होंने उस इन्डस्ट्री के लिये जमीन खरीद ली हो या कुछ स्टेप्स ले लिये हों जिससे मालूम हो सके कि वे इन्डस्ट्री लगाना चाहते हैं और इसी आधार पर इ० सी० ग्रान्ट किया जाता है। शारदा और सवाइका के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा। ये बातें मेरे नोटिस में गत सेशन में आई थीं। मैंने इस बारे में जानकारी प्राप्त की और मैंने उनका एसेन्शियल सर्टिफिकेट रुकवा दिया। कोई भी व्यक्ति हो दरअसल में उसके बोनाफाइड्स इन्डस्ट्री लगाने के हैं या नहीं, देखना पड़ता है। चाहे वह मशीन के अन्दर दस लाख खर्च करे या बीस लाख खर्च करे, हमें उसके बोनाफाइड्स को देखकर ही कार्यवाही करनी चाहिये। मशीनरी के लिए इसेन्शियल सर्टिफिकेट हो लिबरल व्यू लेकर दिया जाता है ताकि राजस्थान में छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़ लग सकें।

श्री श्रीभानसिंह : You ouly talk about bonafides. But did these two fellows follow the procedure laid down ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं अर्ज करूं कि उसके बाद में एसेन्शियल सर्टिफिकेट रॉ मेटेरियल के कुछ ग्रान्ट किये गये। आपके बताने के बाद मैंने उनको फौरन बन्द कर दिया।

श्री श्रीभानसिंह : क्यों? When their bonafides were not in question, why did you stop them ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं अर्ज यह करना चाहता हूँ, माननीय सदस्य को यह अच्छी तरह से मालूम है, जो बात मैं निवेदन कर रहा हूँ वह इस वास्ते कि आपने एक शिकायत की इस तरह से एसेन्शियल सर्टिफिकेट गलती से जारी कर दिया गया। मैंने फौरन उस पर स्टेप लिया और उसको बन्द कर दिया। उसके बाद मैंने जानकारी प्राप्त की और जैसा कि मैंने कहा जो मशीन्स लेना चाहते थे उसका Essentiality certificate दिया गया। Raw Material का बन्द कर दिया। मशीन आ जाने व लग जाने पर दुबारा जांच करके raw material का Essentiality certificate दिया जाना चाहिये, ऐसे आदेश दिए गए।

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

आपने कहा है सवाईका ने टेलो और कोकोनट के E. C. का माल ले लिया, यह आपकी खबर गलत है

दूसरी बात यह है कि एसेन्शियल सर्टिफिकेट इश्यू किया और कोई माल नहीं मिला, उसके बाद फिर जानकारी की गई कि किन किन ने मशीनरी सेट अप कर दी। यह केवल दो के लिए ही बात नहीं करते, यह तो हमारी नीति है। हम देख लें कि मशीनरी आकर लग गई और उसके बाद जो रॉ मेटीरियल आदि होता है उसको भी सप्लाई करने की हमारी जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसी हालत में किसी के इन्टेन्शन्स मेलाफाइड हो तो समझ में आ सकता है, लेकिन जिनके लिये कहा गया उन्होंने मशीनरी के लिए ऑर्डर्स दे दिये वैसी हालत में रॉ मटेरियल देने की जिम्मेदारी हो जाती है। रॉ मेटेरियल हम दें और मिस युटिलाइजेशन होता है तो उसको चेक अप करें, यह सही है। We shall certainly check up and impose panalty on those who misutliise

श्री श्रीभानसिंह : Penalty should be ..

श्री सभापति : Hon'ble member will appreciate, there can be no end to it.

श्री श्री श्रीभानसिंह : I am very much appreciating it, Sir, the Hon'ble Minister has said that he has taken the action. What action has he taken against the officers who granted these E. Cs. It cannot be taken just now on the floor of the House.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपकी उत्सुकता को तो एक भी सन्तोष दिला नहीं सकता। लेकिन जहां तक रॉ मेटेरियल का मिस युटिलाइजेशन का सवाल है वह किसी के अन्दर हुआ नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : मिस युटिलाइजेशन की कौन कहता है? एसेन्शियल सर्टिफिकेट जो राजस्थान के ऑफिसर्स द्वारा दिया जाता है उस पॉवर को तो एक्सर्साइज़ कर लिया, उसमें उनके द्वारा फेवर कर दिया गया; लेकिन जो इसके लिये प्रोसीजर है उसको तो फोलो नहीं किया गया। मशीनरी सेट अप नहीं की, उसके पहले यह कैसे दे दिया गया? what action you have taken ?

श्री सभापति : He has replied and you have to take his reply as it is. The Hon'ble Minister will please conclude his reply within 5 minutes. We cannot prolong the House ad infinitum.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I will request the Hon'ble member to listen to me. When the Hon'ble member broght it to my notice, I took immediate steps. Nothing has been given to them, and still the same thing is being agitated here again and again

श्री श्रीभानसिंह : आपने उन ऑफिसर्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया है क्या? जिन्होंने आउट ऑफ वे जाकर कार्य किया?

Page No.126

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There may be a procedural defect, but that does not..

श्री सभापति : There is room for it in a democracy.

श्री श्रीभानसिंह : There is no question of democracy. The thing has been admitted by the Hon'ble minister. He

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि या तो आप ही बोल लें या मंत्री महोदय को ही बोलने दें। दो–दो, तीन–तीन सदस्य साथ बोलने लग जाते हैं, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता।

श्री सभापति : One member at a time.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : किसी पर्टिक्युलर समस्या के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : आपने स्वयं ने कहा था....

श्री सभापति : Order please! I don't know how the Hon'ble member is rising. He has not raised any point of order. This is not Question Hour.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Minister, while replying to the debate.....

श्री सभापति : There cannot be any end to this questioning and answering. You have to take the reply as it is.

श्री श्रीभानसिंह : Then what is the purpose of our moving cut motions and raising these things in the House. You can put a question to the house and we will sit for another two hours, for all our cut motions to be answered fully.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बीकानेर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा था कि बीकानेर के लिये किसी प्रकार की भी इन्डस्ट्री की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, उस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूँ कि बीकानेर के लिये जो माननीय सदस्य को जानकारी है उसके होते हुए भी वे न मालूम उसे कहना क्यों नहीं चाहते....

श्री सभापति : I think the Hon'ble Minister has concluded his reply.

श्री भैरोंसिंह(श्रीमाधोपुर): मुद्दे के पोइन्ट जो उठाये गये हैं उनका तो जवाब नहीं मिलता। जो चार्जेज़ आपके विभाग के बारे में लगाये गये हैं उनका आप जवाब दे दीजिये। We are of the opinion that these points should be clarified.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : These are not light matters. They are serious matters.

श्री सभापति : Again and again it has been repeated that you cannot put words in his mouth. His reply is there as it is and you have to take it.

श्री ज्वालाप्रसाद : रिप्लाई तो मिल गया। ये चाहते हैं वह रिप्लाई मिले, यह कैसे हो सकता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बीकानेर में शार्दूल टैक्सटाइल, गंगानगर में फर्टिलाइज़र फैक्टरी बनने जा रही है। पलाना लिगनाइट का प्लान्ट अलग है। फुलर्स अर्थ है। इतनी सारी इन्डस्ट्रीज़ हैं।

श्री श्रीभानसिंह : Has the sense of the House been taken that the time be extended for another 15 or 10 minutes.

श्री सभापति : Because of the interruptions of the Hon'ble members his time was curtailed and it is, therefore, being extended by five minutes.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातों पर ध्यान दिलाया। यह सही है कि इन सारे छोटे छोटे उद्योगों को खोलने के सिलसिले में जो कुछ तीसरी योजना में प्रावधान रखा है और जिस सैट अप को हम बिठाना चाहते हैं उसका नतीजा यह है कि लोगों को जो फैसीलिटी हम प्रोवाइड करना चाहते हैं वह आसानी से मिल जावे जिससे कि कम से कम दिक्कत उठाकर ये इन्डस्ट्रीज़ सैट अप कर सकें। तो इस सिलसिले में मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो बातें बताई हैं उनका जवाब मैंने अभी दिया और मेरा निश्चित मत है कि यदि ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें चलाना है तो उस पर जोर देना चाहते हैं।

आपने यह भी कहा कि हमको ऐसी सर्वे रिपोर्ट मिलनी चाहिये कि कितनी रजिस्टर्ड फैक्टरियां हैं और उनको पब्लिश करना चाहिये कि ये क्या क्या काम करती हैं। इसी तरह से कन्ज्यूमर्स गुड्स के बारे में सर्वे होना चाहिये। सही है उनका ख्याल। मैं समझता हूँ कि जो सुझाव उन्होंने दिये हैं उन पर विचार किया जावेगा।

सोडा एश की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो रही है और इसमें करीब करीब एक लाख रुपया खर्चा करेंगे।

इसी तरह ब्लास्ट फर्नेस के लिये भी कहा। फोरिन कोलोबोरेशन की बात चल रही है, कुछ आदमी इन्टरेस्टेड हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें प्रोग्रेस होगी।

इसी तरह से जयपुर डिस्ट्रिक्ट के इन्डस्ट्रियल सर्वे के बारे में है। वैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने सर्वे किया है और आइन्दा भी करना चाहते हैं और इसके बाद में इस स्थिति में आवेंगे कि वाकई में इस डिस्ट्रिक्ट में कितने लघु. उद्योग लगा सकते हैं।

मिल्क पाउडर की बात कही। एस. टी. सी. ने कहा कि हम इम्पोर्ट नहीं करते हैं तो फिर यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री श्रीभानसिंह : Did you grant milk powder to these two people who were caught in black marketing ? What action did you take against them ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति ब्लैक मार्केट करते हुए और अपनी कन्डीशंन और

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

टर्म के खिलाफ देते हुए पकड़ा गया उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है।

श्री श्रीभानसिंह : What step?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन करूंगा कि उनके खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : Against whom?

श्री सभापति : I have said again and again that there can be no end to this sort of questions and answers. Is it the sense of the House that w should further prolong the time?

एक माननीय सदस्य : No, Sir.

श्री सभापति : So kindly conclude your reply within two minutes.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जो तथ्य सदन के सामने मैंने रखे हैं, मैं फिर भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कोई भी इन्स्टान्स बता दीजिये कि जिसमें हमने एक्शन नहीं लिया हो। तो ऐसी स्थिति के अन्दर....

श्री श्रीभानसिंह : I would like to know. ...

श्री रिखबचन्द धारीबाल : आपके कहने से, पर्टिक्युलर व्यक्ति के कह देने से बात नहीं हो सकती।

श्री सभापति : I am sorry, the Hon'ble member is violating the Rules of Procedure.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मिसयुटिलाइज़ेशन, हम भी कहते हैं कि नहीं होना चाहिये। हम भी उत्सुक हैं और सभी उत्सुक हैं। जो स्टैप हमने लिये हैं वैसे हर मामले में लेंगे। जो केसेज़ आपकी नोलेज में आवें हमारी नोटिस में आप लावें। जानकारी करेंगे, जो वाजिब एक्शन होगा बराबर लेंगे। यह आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और आपको इसका विश्वास दिलाना चाहता हूँ।

मैंने यह निवेदन किया कि जिन जिन लोगों के बारे में हमने जानकारी की और जिनको दोषी पाया हमने उनके रॉ मैटीरियल के कोटे बन्द कर दिये। जब से केस हमारे नोटिस में आता है हम बराबर स्टैप्स लेते हैं। आप गलत वातावरण न बनावें। जिसमें हमको....

श्री श्रीभानसिंह : श्रीमान् मंत्री महोदय, मैंने आपसे सही आंकड़े अर्ज किये हैं; गलत वातावरण बनाने की कोई बात नहीं कही है।

श्री रिखबचन्द धारिवाल : आपके कहे हुए फैक्ट्स से सारा का सारा वातावरण ही ऐसा हो जाता है, मानो हमने हरएक आदमी को गलत कोटा दिया, हर एक आदमी ने ब्लैक किया।

श्री श्रीभानसिंह : फिर आप कहेंगे, मैंने इन्टरप्ट किया। मैंने किसी आदमी को करप्ट नहीं बताया, मैंने तो पार्टियों के नाम लिये हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस तरह से बात करने से नतीजा नहीं निकल सकता है। आप जो केस लाये हैं हमने एक्शन लिया है उन पर और मैं समझता हूँ मेरे इन तथ्यों को सामने रखने के बाद जिन्होंने अपने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं वे वापिस लेने की कृपा करेंगे।

श्री सभापति : I think I have the leave of the House to prolong the proceedings for atleast 10 minutes, because the votes have to be taken and it has to be ascertained whether the Hon'ble members would like to withdraw their cut motions.

जो माननीय सदस्य अपने अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेना चाहें।....

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि इस डिमान्ड को एज़ ए होल रख दिया जावे, बाकी जो डिमान्डस् हैं, अपने आप निगेटिव हो जावेंगी।

श्री सभापति : No, no. That is not the procedure. We cannot shortcut the procedure.

श्री ज्वालाप्रसाद : He is noboby to advise the Chair.

श्री सभापति : जो वापिस लेना चाहें अपने कटौती प्रस्ताव वे कृपया खड़े हो जावें।

(कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए)

प्रश्न यह है कि डॉ० बहादुरसिंह, श्री भीमसेन, श्री पी० के० चौधरी, श्री चन्दनमल वैद, श्री श्रीमानसिंह, श्री सूबेदारसिंह, श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी और श्री सोहनलाल भटनागर को इनके कटौती प्रस्तावों को वापिस लेने की अनुमति दी जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

(विराम)

The Hon'ble members may kindly withdraw.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मैं भी अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : मैं भी वापिस लेता हूँ।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : मैं भी लेता हूँ।

श्री सूबेदारसिंह (बाडी) : मैं भी लेता हूँ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : मैं भी अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो

(श्री सभापति)

कटौती प्रस्ताव श्री सतीशचन्द्र ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री भैंवरलाल कालाबादल ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखा है वह स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री लक्ष्मीचन्द ने रखे हैं उन्हें जायें ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री हीराभाई ने रखे हैं वे स्वीकार किया जायें ।

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव रावराजा श्री सरदारसिंह ने रखे है उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री अनूपसिंह ने रखे है वे स्वीकार किये जाये ?

श्री अनूपसिंह : ये तो स्वीकार हो रहे हैं ।

(अस्वीकृति के पश्चात्)

श्री सभापति : कटौती के प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह ने रखे हैं वे स्वीकार किये जायें ।

(अस्वीकृत)

(श्री सभापति)

कटौती के प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग और प्रदाय के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५७, ६८,००० तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

The House Now stands adjourued to 11 A. M. tomorrow.

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ६ बजे दिनांक १७ मार्च, १९६१ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई]

संक्षिप्त–विवरण

(गुरुवार, १६ मार्च, १६६१)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ		स्कम्भ
	२६३३	बांध की नहर से पानी ।	
पंचायत समिति, देवली द्वारा खरीद की गई कुट्टी की मशीनें ।		प्रान्त में हुई डकैतियां ।	
चोर विरोधी पुलिस अभियान ।		लोक गीतों तथा लोक नृत्यों के आयोजन एवं प्रदर्शन हेतु निर्मित समितियां ।	
किशनगढ़ मैटल वर्क्स के बरामदशुदा तांबे का मामला ।		पाली में मेला दरवाजे के बाहर के काले कोटा के पीछे की जमीन के आवंटन के सम्बन्ध में कार्यवाही ।	
भूपाल सागर तालाब की पाल ।			
जुरेहरा (भरतपुर) पंचायत के भूतपूर्व सरपंच द्वारा श्री गुरुदयाल प्रसाद की नाक काटा जाना ।		आर. जे. एल. ६१६३ (स्टेशन वेगन) का दुरुपयोग ।	
जिला बांसवाड़ा के वन विभाग द्वारा जंगल की पैदावार का दिया जाने वाला–ठेका ।		भारत १६५८ प्रदर्शनी हेतु खरीद किये गये कांच ।	
तहसील चाकसू व लालसोट के पटवारियों के खिलाफ हुई जांच का परिणाम ।		जेवाणा, भावा व पटोल्या तालाबों का निर्माण ।	
लूणकरणसर, बीकानेर एवं कोलायत तहसील के गांवों को उपनिवेशन क्षेत्र से पृथक् करना ।		कुम्हार सांवलिया, साकिन खंडप द्वारा अपनी औरत की हत्या कर दिये जाने का मामला ।	
पी. एस. आई., श्री पृथ्वीसिंह ।		पशु–पालन विभाग को मिली सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग ।	
भूपालसागर तालाब को मांधडी		ब्रह्मपुरी में नल लगाना ।	

Page No.133

स्कम्भ

डी. वाई. एस. पीज़. की होम डिस्ट्रिक्ट में नियुक्तियां।

सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पाली की बकाया की वसूली।

रतनगढ़ में हुई चोरियों की बरामदगी।

पाली जिले में सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट व एक्स्ट्रा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट्स को अदालतों में क्लर्को द्वारा बयान लिया जाना।

पाली शहर के आयुर्वेदिक 'बी' श्रेणी के औषधालय का 'ए' श्रेणी में परिवर्तन।

जयपुर–कोटा बस रूट को झालावाड़ तथा भोपाल तक बढ़ाना।

आय–व्ययक, १९६१–६२
द्वितीय अवस्था–अनुदानों की मांगों पर मतदान

स्कम्भ

मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग और प्रदाय २९८३

उपरोक्त मांग श्री रिखबचन्द धारीवाल, उद्योग मन्त्री द्वारा प्रस्तावित की गई। इस पर कुल ५८ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

उद्योग मन्त्री के उत्तर के पश्चात् ३२ कटौती प्रस्ताव वापस ले लिये गये तथा शेष अस्वीकृत हुए। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

सदन की बैठक ठीक ६ बजे शुक्रवार, दिनांक १७ मार्च, १९६१ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

शुक्रवार, दिनांक १७ मार्च, १९६१ की कार्य-सूची

मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग।

———

३१६६]

परिशिष्ट-१

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३१६ का उत्तर देखिये)

पंचायतों को दी गई मशीनों की सूची

१	धुआं	६	बीजवाड़
२	नासीरदा	७	राजमहल
३	पनवाड	८	आंवा
४	थांवला	९	दूणी
५	गांवडी	१०	वंथली

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, १६ मार्च, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२६३६	अन्तिम	के विरुद्ध ।	के विरुद्ध
२६३७	१५	की प्रतिज्ञा	की प्रतीक्षा
,,	१६	प्रगतीशील	प्रगतिशील
२६४२	१३	एडि निस्ट्रेटिव	एडमिनिस्ट्रेटिव
२६४४	२३	perties के	parties के
,,	अन्तिम	किये है ।	किये हैं ।
२६४७	४	अ पसिंह	अनूपसिंह
२६४६	शीर्ष	(श्री रामकि र व्यास)	(श्री रामकिशोर व्यास)
२६५३	अन्तिम से ५	(पोरिंट्स)	(पोस्टिंग्स)
२६५७	अन्तिम से ८	बाली सोजत	बाली, सोजत
२६६३	२	की गई	की गईं
,,	५	गई हैं ।	गई है ।
,,	२२	दी गई ।	दी गईं
२६६४	२३	आई उनमें	आईं उनमें
,,	२६	दी गई	दी गईं
२६६६	२३	चन्द वाजी	चन्दवाजी में
,,	अन्तिम	चद्दर एक	चद्दर, एक
२६६६	१	श्री रांकिशोर	श्री रामकिशोर
२६७२	१२	कहते 'लगाओ	कहते हैं, 'लगाओ
२६७७	३	dlear	clear
२६८१	५	कितनी सन्	कितनी ? सन्
,,	६	कहां ३	कहां २
२६६३	२१	लिए)	लिए)]
२६६५	१४	में समझने	में, समझने
२६६८	२	सख्ति से	सख्ती से
३००१	शीर्ष	(श्री स च अ । ल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
३००५	१२	ये पर्चेजज	ये पर्चेज़ेज़
३००६	अन्तिम से ३	उपाध्याय था;	उपाध्याय
३०२०	२६	बहत से	बहुत से
३०२४	८	दोगें १२	दोगे १२

१	२	३	४
३०३६	२१	वह है नाथद्वारा	नाथद्वारा
,,	२३	यह कि	यह है कि.
३०४५	२२	समात किया	समाप्त किया
३०५२	६	था न	था, न
,,	१०	तनख्वा चुकाने	तनख्वाह चुकाने
३०५४	१०	your debdte	your debate
३०५६	१२	भेज देते	बेच देते
३०६१	३	में इएके	में इसके
३०६७	२४	our freedm	our freedom
३०६८	१४	एक इन्स्ट्रमेन्ट	एक इन्सट्रूमेंट
३०७२	अन्तिमसे ३-२	मेग्नीटयूड	मेग्नीट्यूड
३०७५	२३	चाहिये फेक्टरीज़	चाहिये। फेक्टरीज़
३०८१	७	के फीर्नचर्स	के फर्नीचर्स
३०६१	अन्तिम	जावब के	जवाब के
३११३	२३	हजारों लाखों	हजारों-लाखों
३१२२	१३	से तो	में तो
,,	२३	हैं। कहीं	हैं कहीं
३१२३	८	मैं वह	मैं
,,	६	बम्बई दिल्ली	बम्बई, दिल्ली
३१२७	२१	ज्यादा हैं। वहां	ज्यादा हैं, वहां
३१३२	३	फॉस्टी नही	फॉल्टी नहीं
३१३५	१५	स्मल्टिंग	स्मैल्टिंग
३१३६	५	लिए फेरिन	लिये फोरिन
३१३६	७	में कोतई	में कोताई
,,	अन्तिम से ४	को गौरव	को गौरव
३१४५	शीर्ष	(भी भैरोंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
३१४८	६	कर की	करने की
३१५१	१२	order,s r	order, Sir
३१५६	१२	ओई और	आई और
,,	१६	उससे बिछड़ा	उससे पिछड़ा
३१५७	२३	सैकड फाइव	सैकन्ड फाइव
३१६०	६	हो ! सकता	हो सकता
३१६२	३	सैकड	सैकन्ड
३१६८	१६	हों, चा	हों, चाहे
३१७५	२३	बना सकते	बता सकते

१	२	३	४
३१८०	७ व २२	श्रीभानसिह	श्री श्रीभानसिंह
,,	१३	मेटेरियल	मेटीरियल
३१८१	१३	हो तो	हों तो
,,	२१	misutuse	misutilise
३१८६	शीर्षक	उद्योग अर	उद्योग और
३१९१	अन्तिम से ३	उन्हें जायें ?	उन्हें स्वीकार किया जाये !
३१९२	१६	जाये ?	जायें ?
३१९६	अन्तिम	व्रह्मपुरी	ब्रह्मपुरी
३१९७	९	मजिस्ट्रेटस	मजिस्ट्रेट्स

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२९४८ व २९६१	शीर्षक	तारकित	ताराकित
२९८२	५	दौलमराम	दौलतराम
२९९२	शीर्षक	उद्यग	उद्योग
३०१७	शीर्ष	काला ादल	कालाबादल
३०४२	शीर्षक	ग्रदाय	प्रदाय
३०५१	शीर्ष	चोधरी	चौधरी
३१८८	शीर्षक	३१	३१८८